चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 28 अगस्त– 03 सितंबर 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

अहमद पटेल कांग्रेस के चाणक्य

संतोष भारतीय

अहमद पटेल को कांग्रेस के चाणक्य का नाम मिला है. अहमद पटेल गुजरात से चुनाव जीत गए, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हराने में कोई कसर बाकी नहीं रखी. भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि किसी तरह अहमद पटेल हार जाएं. अहमद पटेल को इसके लिए एड़ी–चोटी का जोर लगाना पड़ा. उनके साथी शंकर सिंह वाघेला पार्टी छोड़कर चले गए. उनके साथ 14 विधायक चले गए और विधायकों के भी जाने का डर बना रहा. अंततः अहमद पटेल जीत गए. कर्नाटक में जिस मंत्री के रिजॉर्ट में विधायकों को रखा गया था, वहां छापा पड़ा. इतना ही नहीं, पहली बार इनकम टैक्स अधिकारियों के साथ पुलिस अंदर गई, इन सब के बावजूद अहमद पटेल को इस घटना से एक बड़ी सीख मिली. क्या सीख मिली, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. अभी हम बात करते हैं कि पिछले 20 साल में अहमद पटेल ने गुजरात में कैसी कांग्रेस खड़ी की?

गुजरात कांग्रेस का नेता कौन

अहमद पटेल ने पिछले 20 साल में कांग्रेस को अपनी आंखों के सामने पैदा किया और पुराने नेताओं की जगह नए नेता खड़े किए. इनमें भरत सिंह सोलंकी, मोडवाडिया, शक्ति सिंह, सिद्धार्थ पटेल और शंकर सिंह वाघेला शामिल हैं. इन पांचों को ही गुजरात कांग्रेस माना जाता था. गुजरात के इन चार नेताओं में भरत सोलंकी, श्री माधव सिंह सोलंकी के बेटे हैं. माधव सिंह सोलंकी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने गुजरात में कांग्रेस को बहुत मजबूत बनाया था. बाद में वो देश के विदेश मंत्री भी बने. उन्हें बोफोर्स पेपर के मामले में या बोफोर्स कांड के मामले में स्वीडन के विदेश मंत्री से बात करने के आरोप में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था. सिद्धार्थ पटेल चिमनभाई पटेल के बेटे हैं. चिमनभाई पटेल गुजरात के कई बार मुख्यमंत्री रहे. उन्हीं के समय गुजरात का मशहूर नवनिर्माण आन्दोलन शुरू हुआ था. बाद में वे जनता दल में आ गए थे और फिर उन्होंने गुजरात जनता दल बनाया.

इनमें शंकर सिंह वघेला अकेले ऐसे थे, जिनके पास जनाधार था, जिन्हें लोग सुनना चाहते थे और जिन्हें सचमुच का जननेता कह सकते हैं. बाकी चार, चाहे वो भरत सिंह सोलंकी, मोडवाडिया, शक्ति सिंह या सिद्धार्थ पटेल हों, इनके पीछे जनता नहीं है. शंकर सिंह और भरत सोलंकी के अलावा बाकी तीन नेताओं का भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ बिजनेस इंटरेस्ट है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मिलकर कांग्रेस को चला रहे थे. मोडवाडिया बड़े कॉन्ट्रेक्टर हैं. उसी तरह सिद्धार्थ पटेल भी बड़े व्यापारी हैं. शक्ति सिंह बुनियादी तौर पर लाइजन का काम करते हैं. वो सिफारिश करते हैं, काम होते हैं और उसमें उनका इंटरेस्ट होता है. अब इनकी इज्जत की बात करें. न कांग्रेस पार्टी में और न ही जनता में इनकी इज्जत है, क्योंकि इनका जनता के साथ बहुत कम रिश्ता है. पिछले चुनाव में यही नेता कांग्रेस की हार के प्रमुख कारण रहे हैं. इनकी इज्जत अगर गुजरात में है, तो सिर्फ इसलिए कि इनके साथ पद लगे हुए हैं. कोई विधानसभा में नेता है, कोई प्रदेश का अध्यक्ष है, कोई महामंत्री है. अगर ये पद इनके नाम के आगे से हट जाएं, तो शायद गुजरात में इन्हें कोई पूछे भी नहीं. गुजरात कांग्रेस के लोग कहते हैं कि इनके पास अपने पांच आदमी भी नहीं हैं. मैंने कांग्रेस के एक बड़े नेता से पूछा कि तब इन्हें कांग्रेस ने पद पर क्यों बना रखा है? उन्होंने इसका स्पष्ट उत्तर दिया कि ये अहमद पटेल साहब के सबसे विश्वस्त लोग हैं या दूसरे शब्दों में कहें कि अहमद पटेल साहब के ये सबसे बड़े चंपू हैं. अहमद पटेल साहब ने इन चारों लोगों को पिछले 20 साल से अपने इर्द–गिर्द रखा है. इन्हीं के हितों को ध्यान में रखकर उन्होंने गुजरात कांग्रेस की गतिविधियां तय की हैं. नरेश रावल और राजू परमार को अहमद पटेल दिल्ली लाए. राजू परमार कई साल से राज्य सभा के सदस्य हैं. उनके बारे में मशहूर है कि जिस दिन ये राज्यसभा से हटेंगे, उस दिन उनके साथ कितने लोग खड़े दिखाई देंगे, ये कोई नहीं जानता. उनके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि तीन बार सदस्य रहने के बावजूद वो एक–एक जिले में घूम जाएं, हालांकि वे स्वयं दलित हैं, लेकिन अगर उनको दलित ही पहचान लें, तो ये एक आश्चर्यजनक बात होगी. कांग्रेस के लोगों का कहना है कि अहमद भाई का चुनाव ऐसे ही लोगों का चुनाव है. दरअसल उनके लिए वही व्यक्ति नेता है या उसमें आगे बढ़ने की सलाहियत है, जो उनका व्यक्तिगत वफादार है.

अहमद पटेल ने पिछले 20 साल में कांग्रेस को अपनी आंखों के सामने पैदा किया और पुराने नेताओं की जगह नए नेता खड़े किए. इनमें भरत सिंह सोलंकी, मोडवाडिया, शक्ति सिंह, सिद्धार्थ पटेल और शंकर सिंह वाघेला शामिल हैं. इन पांचों को ही गुजरात कांग्रेस माना जाता था. गुजरात के इन चार नेताओं में भरत सोलंकी, श्री माधव सिंह सोलंकी के बेटे हैं. माधव सिंह सोलंकी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने गुजरात में कांग्रेस को बहुत मजबूत बनाया था. बाद में वो देश के विदेश मंत्री भी बने.

अहमद पटेल पर क्या है आरोप

अहमद पटेल पर एक बड़ा आरोप है कि उन्होंने गुजरात में कांग्रेस को बढ़ने नहीं दिया. कांग्रेस के लोगों का कहना है कि पिछले 25 साल में उनका एक भी कदम, एक भी सुझाव ऐसा नहीं रहा, जो कांग्रेस पार्टी के प्रभाव में बढ़ोत्तरी करने वाला हो. जब कांग्रेस के लोगों ने ऐसा कहा तो ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है. जो व्यक्ति देश भर की कांग्रेस को कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव के नाते चला रहा हो, उसके बारे में गुजरात में ऐसी राय क्यों है? 1989 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तब गुजरात में जनता दल की सरकार बनी. वीपी सिंह के हटने के बाद कांग्रेस के दोबारा सत्ता में आने की संभावना थी, लेकिन श्री अहमद पटेल के फैसले के फलस्वरूप गुजरात जनता दल से कांग्रेस का समझौता हुआ, जिसके नेता चिमनभाई पटेल थे. कांग्रेस पर फिर ये इल्जाम लगा कि कांग्रेस तो भ्रष्ट लोगों को समर्थन देती है और इसमें भ्रष्ट लोग ही हैं. लोगों में ये भावना फैली कि कांग्रेस सिर्फ पावर के लिए है, लोगों के लिए नहीं है और भ्रष्ट लोगों को ही आगे बढ़ाती है. इन लोगों ने शंकर सिंह वाघेला के साथ भी ऐसा ही किया. शंकर सिंह वाघेला को मुख्यमंत्री बनाया और शंकर सिंह वाघेला को मुख्यमंत्री पद से हटाया. इस सवाल के जवाब में कि यह गुजरात कांग्रेस ने किया या अहमद पटेल ने, कांग्रेस के लोगों का कहना था कि ये सारे फैसले अहमद पटेल ने लिए. अहमद पटेल का ही मतलब गुजरात कांग्रेस था और आज भी गुजरात कांग्रेस का मतलब अहमद पटेल ही हैं.

अभी गुजरात में कांग्रेस की जीत के लिए एक नई संभावना बनी है. लेकिन वहां के (शेष पृष्ठ 2 पर)

3 बोफोर्स तोप घोटाला फिर संकट में सोनिया

4 बीमार भारत कैसे बनेगा न्यू इंडिया

5 हादसे के बाद जागने की आदत बदलनी होगी

6 खोखले वादों की दस्तावेज़ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

अहमद पटेल : कांग्रेस के चाणक्य

पृष्ठ 1 का शेष

लोगों का कहना है कि इसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है. पिछले वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में रहने के कारण, जो लोगों की नाराजगी है, उसकी वजह से कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं बन गई हैं. इस जीत की संभावना को कांग्रेस सत्यता में बदल पाएगी, इसे लेकर गुजरात कांग्रेस के नेताओं, वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनता के बीच बहुत बड़ा संदेह है. अशोक गहलोत गुजरात कांग्रेस के प्रभारी हैं. वो गुजरात में समय दे रहे हैं. उन्होंने अहमदाबाद में घर भी ले लिया है. लेकिन नीचे के लोग, जिन्हें गुजरात में काम करना है, अशोक गहलोत के पास नहीं पहुंच पाते. अशोक गहलोत भी उन्हीं नेताओं से घिरे हुए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये अहमद पटेल से जुड़े हुए हैं.

शंकर सिंह वाघेला

मोदी की भाजपा, रूपानी की भाजपा

मोदी की भारतीय जनता पार्टी और रूपानी की भारतीय जनता पार्टी में क्या फर्क है? हमें पता चला कि इसमें कोई बहुत फर्क नहीं है. नरेन्द्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी या संघ से जुड़े तीन-साढ़े तीन लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ा था. जिनके पास कुछ नहीं था, उन्हें अवसर देकर धीरे-धीरे करोड़पति बना दिया. लगभग साढ़े तीन लाख लोग 15 से 20 करोड़ रुपए की आर्थिक संपत्ति के स्वामी बन गए. आज वही लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए आधार का काम करते हैं. चुनाव में पैसा खर्च करना हो, लोगों को इकट्ठा करना हो, हवा बनानी हो, मीडिया को सहायता देनी हो, ये सारे काम वो तीन-साढ़े तीन लाख लोग करते हैं. इसके बावजूद कि 2014 से नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं हैं. गुजरात के मौजूदा मुख्यमंत्री रूपानी उसी परंपरा को निभा रहे हैं. पिछले पांच वर्षों में भारतीय जनता पार्टी में संघ का दखल बढ़ जाने से नए लोगों का आना रुक गया है. गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से काम कराने के लिए या किसी प्रकार की अनुमति के लिए संघ की अनुमति परम आवश्यक है, इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी में नए लोग नहीं आ रहे हैं. गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का मुख्य आधार पाटीदार समाज था. ये तो नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी से पाटीदार समाज पूरी तरह से अलग हो गया है, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा जरूर अलग हो गया है. गुजरात में एक और अजीब चीज पता चली. मुझे लगता था कि बहुत कम और खासकर राजनीति से प्रेरित लोग ही भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे. लेकिन अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा में घूमते हुए मुझे इस सवाल को लेकर निराशा हाथ लगी. लगभग सभी लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट पार्टियों की सूची में इस समय सबसे ऊपर है.

गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री रूपानी राजकोट के मेयर रहे. उसके बाद वो संसद में गए. मुझे एक अजीब चीज पता चली. रूपानी का नियम था कि वे हर हफ्ते राजकोट कॉर्पोरेशन और वहां की जिला पंचायत से पैसे लेते थे और वो पैसे पार्टी के नाम पर लेते थे. मैं जब राजकोट में घूमा, तो काफी लोगों ने मुझे यह बताया कि रूपानी के बारे में यह बात मशहूर है कि इन्हें पैसे दो और कोई भी काम करा लो. जब मैंने नरेन्द्र मोदी के बारे में पूछा कि इनके बारे में लोगों की क्या राय है, तो लोगों ने कहा कि वो बाकी लोगों की तरह पैसे नहीं वसूलते थे, लेकिन उनके पास पैसे आ जाते थे. कहने वाले तो ये तक कहते मिले कि नरेन्द्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में 40 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा अहमदाबाद या गुजरात से बाहर गए. अगर कभी भविष्य में इसकी जांच होगी, तो इस गोरखधंधे में कांग्रेस के कुछ लोग भी फंसे मिलेंगे और शायद उन्हें भी शर्मिंदगी झेलनी पड़े. मुझे लोगों ने बताया कि शंकर सिंह वाघेला ने सार्वजनिक तौर पर ये कहा था कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने ही भारतीय जनता पार्टी से सुपारी ली है.

गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री रूपानी राजकोट के मेयर रहे. उसके बाद वो संसद में गए, मुझे एक अजीब चीज पता चली. रूपानी का नियम था कि वे हर हफ्ते राजकोट कॉर्पोरेशन और वहां की जिला पंचायत से पैसे लेते थे और वो पैसे पार्टी के नाम पर लेते थे. मैं जब राजकोट में घूमा, तो काफी लोगों ने मुझे यह बताया कि रूपानी के बारे में यह बात मशहूर है कि इन्हें पैसे दो और कोई भी काम करा लो. जब मैंने नरेन्द्र मोदी के बारे में पूछा कि इनके बारे में लोगों की क्या राय है, तो लोगों ने कहा कि वो बाकी लोगों की तरह पैसे नहीं वसूलते थे, लेकिन उनके पास पैसे आ जाते थे

वाघेला वापस आएंगे!

गुजरात में शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस के बड़े नेता थे. आमतौर पर गुजरात में ये माना जा रहा है कि शंकर सिंह वाघेला अगर कांग्रेस में होते तो कांग्रेस हर हालत में चुनाव जीतती, लेकिन अब वे कांग्रेस से बाहर हैं. शंकर सिंह वाघेला को कांग्रेस में रहकर बहुत अपमान झेलना पड़ा. उनसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं मिले. उनसे कहा गया कि आपकी सोनिया गांधी से मुलाकात तय हो गई है, जब वो दिल्ली पहुंचे तो उनसे कहा गया कि कोई मुलाकात तय नहीं हुई है. वे 20 जुलाई को अहमद पटेल से मिले. उन्होंने कहा कि मेरे लिए अगर कोई संदेश हो या गुजरात में कांग्रेस को कुछ नया करना हो तो मुझे बता दीजिए, अन्यथा मैं कल अहमदाबाद जाकर कोई फैसला करूंगा. अहमद पटेल ने कहा, मैं बता दूंगा. दरअसल कांग्रेस का आलाकमान गुजरात में किसी को भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करना चाहता. शंकर सिंह वाघेला को तो बिल्कुल नहीं करना चाहता था. शंकर सिंह वाघेला की राजनीति ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग उन सारे लोगों को इकट्ठा करें, जिनके पास थोड़ा सा भी जनाधार है. वे इसमें कांग्रेस को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस उनके साथ जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ अहमद पटेल को करना है. अगर कांग्रेस नहीं जुड़ती है, तब भी गुजरात के जितने बचे हुए राजनीतिक दल हैं और जो दो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो शंकर सिंह वाघेला के साथ हैं. शंकर सिंह वाघेला सारे सामाजिक संगठनों और भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस से अलग बची हुई राजनीतिक पार्टियों के संभावित नेता के तौर पर उभर चुके हैं. शंकर सिंह वाघेला ने सार्वजनिक रूप से राजनीति से संन्यास का एलान कर दिया है, पर मुझे लगता है कि अगर उनसे सामूहिक रूप से राजनीति में दोबारा लौटने की अपील की जाए, तो उन्हें इसमें कोई हिचक नहीं होगी.

अहमद पटेल की परीक्षा

और अब यहीं पर अहमद पटेल का इम्तिहान है. वे अब तक एक अच्छे राजनीतिक सचिव, एक अच्छे मैनेजर, एक अच्छे रणनीतिकार और चाणक्य के रूप में देश में जाने गए. इस राज्यसभा के चुनाव में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने उनको हराने की कोशिश की, अहमद पटेल गुजरात और देश में एक नेता के रूप में उभरे हैं. उन पर ये भी आरोप है कि उन्होंने अपनी राज्यसभा सीट के लिए गुजरात में कांग्रेस को नहीं बढ़ने दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. लेकिन इस बार अहमद पटेल को ये साफ पता चल गया होगा कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता. अगर अमित शाह का दांव थोड़ा सा भी सही पड़ जाता, तो अहमद पटेल राज्यसभा से और राजनीति से भी बाहर होते. कांग्रेस की राजनीति में सत्ता का केन्द्र लगभग बदल चुका है. अहमद पटेल सोनिया गांधी के विश्वासपात्र थे, लेकिन अहमद पटेल राहुल गांधी के विश्वासपात्र नहीं हैं. अहमद पटेल पर प्रियंका गांधी को तो भरोसा है, लेकिन राहुल गांधी को भरोसा नहीं है. अहमद पटेल कांग्रेस की राजनीति में पिछले तीन साल में लगभग निष्क्रिय दिखाई दिए हैं. इस चुनाव ने अहमद पटेल की अहमियत, सार्थकता और प्रासंगिकता बढ़ा दी है.

अब देखना ये है कि गुजरात में अहमद पटेल भारतीय जनता पार्टी से बाहर बचे हुए सारे राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को अपने साथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी का डटकर मुकाबला करते हैं या नहीं करते हैं. गुजरात यात्रा में मुझे ये साफ लगा कि अगर अहमद पटेल ऐसा करते हैं और अपने अहम को किनारे रख गुजरात को जीतने का अभियान छेड़ते हैं, तो वे गुजरात में कांग्रेस को बहुत वर्षों के बाद दोबारा सत्ता में ला पाएंगे. वे भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में ही हराकर देश में एक नया राजनीतिक संदेश दे सकते हैं. पर मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि क्या अहमद पटेल अपनी निद्रा से जाग पाएंगे? क्या अहमद पटेल अपनी नई राजनीतिक पहचान का इस्तेमाल गुजरात के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़ा करने में करेंगे या फिर एक बार दोबारा अपनी निद्रा में चले जाएंगे. गुजरात कांग्रेस को उसके हाल पर छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मदद करेंगे, ताकि उनके द्वारा बनाए हुए नेताओं का आर्थिक हित वैसा ही बरकरार रहे, जैसा पिछले सत्रह साल में बरकरार रहा है. ये प्रश्न कठिन हैं, कड़वे हैं, गुस्सा दिलाने वाले हैं, इसके बावजूद सवाल तो हैं. इन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के पास है जिसका नाम अहमद पटेल है.

editor@chauthiduniya.com

अर्जुन मोडवाडिया

भरत सिंह सोलंकी

शक्ति सिंह गोहिल

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 09 अंक 26
28 अगस्त- 03 सितंबर 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786
+91-8451050786
+91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

बोफोर्स तोप घोटाला

फिर संकट में सोनिया

“मजे की बात यह है कि गंभीर आरोपों के बावजूद क्वात्रोच्ची जुलाई 1993 में देश से बाहर भाग गया. बताते हैं कि गांधी परिवार से अपनी नज़दीकियों के चलते क्वात्रोच्ची लम्बे समय तक कानून और अदालत को धता बताता रहा. आरोपी होने के बाद भी वह कभी अदालत में हाज़िर नहीं हुआ. मनमोहन सिंह सरकार के समय 4 मार्च 2011 को सीबीआई अदालत ने क्वात्रोच्ची को यह तर्क देकर केस से बरी कर दिया कि सरकार अब उसके प्रत्यर्पण पर जनता की गाढ़ी कमाई का और पैसा खर्च नहीं कर सकती. सरकार 64 करोड़ के इस घोटाले का सच जानने के नाम पर वैसे ही तकरीबन 250 करोड़ फूंक चुकी है.”

सुरेश त्रिवेदी

तरह-तरह के राजनीतिक संकटों से जूझ रहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी फिर एक नई मुसीबत में फंसती दिख रही हैं. कारण यह कि सन 1986 से गांधी परिवार के गले की फांस बना बोफोर्स का जिन्न एक बार फिर सियासत की बोतल से बाहर निकल आया है. संसद की लोक लेखा समिति ने बोफोर्स मामले से जुड़ी कुछ बेहद गोपनीय फाइलों के गायब होने पर गहरी नाराज़गी तो जताई ही थी, अब सोनिया गांधी के खिलाफ 2014 में रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके सर्वोच्च न्यायालय के वकील अजय कुमार अग्रवाल ने इस केस की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मामले को नया तूल दे दिया है. याचिका में सीबीआई पर आरोपियों के साथ सांठ-गांठ कर पूरे मामले को रफा-दफा करने का भी आरोप है. अग्रवाल की इस याचिका और सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को लिखी उनकी ताज़ा चिट्ठी के कारण सर्वोच्च अदालत से संसद के गलियारों तक यह मामला एक बार फिर खदबदाने लगा है.

दरअसल, संसद की लोक लेखा समिति से सम्बंधित रक्षा मामलों की उपसमिति ने पिछले दिनों भारत के महालेखाकार (सीएजी) की रिपोर्ट्स की पड़ताल की. इस जांच के दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई. पता चला कि बोफोर्स दलाली से सम्बंधित सीएजी की रिपोर्ट में उठाई गई आपत्तियां अभी तक निस्तारित नहीं की गई हैं. इस मामले में जब समिति के अध्यक्ष बीजद सांसद भर्तृहरि महताब ने सीबीआई के निदेशक और रक्षा सचिव को तलब किया, तब एक नया खुलासा हुआ. मालूम हुआ कि रक्षा मंत्रालय की बोफोर्स घोटाले से सम्बंधित जरूरी फाइलों के कुछ अंश ही गायब हैं. रक्षा समिति के कड़े रुख के बाद सीबीआई अब इन फाइलों से गुम हुए या गायब किए गए पन्नों की तलाश में जुटी है. बताया जाता है कि इन्ही पन्नों में बोफोर्स दलाली कांड के वे सूत्र छिपे हैं, जिनके तार गांधी परिवार से जुड़े माने जाते हैं.

सीबीआई निदेशक को गत 3 अगस्त को लिखे पत्र में भाजपा नेता और वकील अजय अग्रवाल ने बोफोर्स मामले से जुड़ी उन घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया है, जो 10 जनपथ की ओर इशारा करती हैं. यूपीए एक के शासन के दौरान की गई इन फ़ितरतों को बोफोर्स दलाली के असली गुनहगारों को बचाने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है. अजय अग्रवाल का कहना है कि सीबीआई ने वर्ष 2003 में बोफोर्स मामले के आरोपी अट्टाविया क्वात्रोच्ची के लंदन में दो बैंक खाते फ्रीज करा दिए थे. बताया जाता है कि इन खातों में दलाली की 42 करोड़ रकम जमा थी. बीएसआईएजी बैंक लंदन में चल रहे ये खाते क्रमशः 55151516 एम और 55151516 एल क्वात्रोच्ची और उसकी पत्नी मारिया के नाम थे. हैरत की बात यह है कि 11-12 जनवरी 2006 को इन दोनों खातों पर लगी रोक एकाएक हटा ली गई. इसके लिए भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बी दत्ता को बाकायदा लंदन भेजा गया. हालांकि खातों पर लगी रोक हटाने की खबर मिलते ही अग्रवाल ने कोर्ट में अर्ज़ी देकर फैसले पर अपनी आपत्ति दर्ज़ कराई, लेकिन इस पर 16 जनवरी को सुनवाई हुई और इसी बीच खातों में जमा रकम को ठिकाने लगा दिया गया.

सीबीआई निदेशक को गत 3 अगस्त को लिखे पत्र में भाजपा नेता और वकील अजय अग्रवाल ने बोफोर्स मामले से जुड़ी उन घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया है, जो 10 जनपथ की ओर इशारा करती हैं. यूपीए एक के शासन के दौरान की गई इन फ़ितरतों को बोफोर्स दलाली के असली गुनहगारों को बचाने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है. अजय अग्रवाल का कहना है कि सीबीआई ने वर्ष 2003 में बोफोर्स मामले के आरोपी अट्टाविया क्वात्रोच्ची के लंदन में दो बैंक खाते फ्रीज करा दिए थे.

फिर लटकी जांच की तलवार

याचिका में मांग की गई है कि लंदन के इन दोनों बैंक खातों से इधर-उधर की गई दलाली की रकम कहां और किसे भेजी गई, इसकी नए सिरे से जांच जरूरी है. सवाल यह भी है कि खातों पर लगी रोक हटाने का फैसला यूपीए सरकार ने किसके इशारे पर लिया? खातों को डीफ्रीज़ करने की जानकारी सम्बंधित अदालत को क्यों नहीं दी गई, जबकि मामला अदालत में विचाराधीन था. यही नहीं, वर्ष 2009 में क्वात्रोच्ची के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस भी वापस ले ली गई. ऐसे कई सवाल हैं, जिनकी अगर गहराई से पड़ताल की जाए, तो सोनिया गांधी समेत उनके कई सम्बन्धी संदेह के घेरे में आ सकते हैं. अंदेशा जताया जा रहा है कि क्वात्रोच्ची के खातों से निकली दलाली की रकम आखिर में सोनिया गांधी के कुछ करीबियों के खातों में जमा की गई थी, जो श्रीमती गांधी के लिए अंततः परेशानी का सबब बन सकती है.

याचिकाकर्ता अजय अग्रवाल ने अपनी याचिका में बोफोर्स दलाली मामले में हिंदुजा बंधुओं (श्रीचंद, गोपीचंद, और अशोक हिंदुजा) को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के फैसले पर भी सवाल खड़े किए हैं. मालूम हो कि बोफोर्स दलाली मामले के आरोपी हिंदुजा भाइयों को दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 मई 2005 को दिए फैसले में बरी कर दिया था. उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ सीबीआई ने ऊपरी अदालत में अपील भी नहीं की. इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने हाय-तौबा मचाई तो सीबीआई ने यह कह कर अपना पल्ला झाड़ लिया कि उसे केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय ने अपील दायर करने की मंज़ूरी ही नहीं दी है. बाद में अजय अग्रवाल ने एक जनहित याचिका के जरिए हाईकोर्ट के इस फैसले को भी चुनौती दी. 18 अक्टूबर 2005 को अदालत ने उनकी यह याचिका मंज़ूर तो कर ली, लेकिन तब से इसकी सुनवाई कछुआ चाल से चल रही है. मसलन 12 अगस्त 2010 के बाद इस केस की अगली सुनवाई 6 वर्ष बाद 01 दिसंबर 2016 को हुई. इससे सरकार और सीबीआई के इरादों को साफ समझा जा सकता है. अग्रवाल ने अब इस याचिका की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम अदालत में गुहार लगाई है.

बोफोर्स ने डुबोई थी राजीव की नैया

अब ज़रा बोफोर्स घोटाले के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं. दरअसल 24 मार्च 1986 को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय और स्वीडन की एबी बोफोर्स कंपनी के बीच 155 एमएम की 400 हॉवित्जर तोपों की खरीद का करार हुआ. 1437 करोड़ के इस सौदे में 64 करोड़ की दलाली लिए जाने के आरोप थे. जब 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो ने यह खुलासा किया कि इस रक्षा सौदे में कुछ प्रभावशाली राजनेताओं और सेना के अधिकारियों को दलाली की रकम दी गयी है, तो संसद से सड़क तक बखेड़ा खड़ा हो गया. तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी इस घोटाले में निशाने पर थे. उन्ही की सरकार में रक्षा मंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए देश भर में मुहिम छेड़ी. नतीज़तन वर्ष 1989 में राजीव गांधी को सत्ता गंवानी पड़ी. वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनने पर 22 जनवरी 1990 को सीबीआई ने इस घोटाले पर एफआईआर दर्ज़ की, जिसमें बोफोर्स कंपनी के चेयरमैन मार्टिन ओर्डिबो, कंपनी के भारत में प्रतिनिधि विन चड्ढा और हिंदुजा बंधुओं को आरोपी बनाया गया. लम्बी छानबीन के बाद 1999-2000 में सीबीआई ने इस मामले में मार्टिन ओर्डिबो, विन चड्ढा, इतालवी नागरिक अट्टाविया क्वात्रोच्ची, पूर्व रक्षा मंत्री एस के भटनागर और ब्रिटिश भारतीय हिंदुजा भाइयों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए.

मजे की बात यह है कि गंभीर आरोपों के बावजूद क्वात्रोच्ची जुलाई 1993 में देश से बाहर भाग गया. बताते हैं कि गांधी परिवार से अपनी नज़दीकियों के चलते क्वात्रोच्ची लम्बे समय तक कानून और अदालत को धता बताता रहा. आरोपी होने के बाद भी वह कभी अदालत में हाज़िर नहीं हुआ. मनमोहन सिंह सरकार के समय 4 मार्च 2011 को सीबीआई अदालत ने क्वात्रोच्ची को यह तर्क देकर केस से बरी कर दिया कि सरकार अब उसके प्रत्यर्पण पर जनता की गाढ़ी कमाई का और पैसा खर्च नहीं कर सकती. सरकार 64 करोड़ के इस घोटाले का सच जानने के नाम पर वैसे ही तकरीबन 250 करोड़ फूंक चुकी है. बाद में 13 जुलाई 2013 को क्वात्रोच्ची की मौत हो गई. क्वात्रोच्ची के अलावा बोफोर्स मामले के तीन आरोपी मार्टिन ओर्डिबो, एस के भटनागर और विन चड्ढा भी अब तक दुनिया से रुखसत हो चुके हैं. हिंदुजा भाइयों को हाई कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ की गई अपील सर्वोच्च न्यायालय में ठंढे बस्ते में पड़ी है, जबकि उनके विरुद्ध ढेरों सबूत अब भी मौजूद हैं.

पिछले दिनों बोफोर्स घोटाले से सम्बंधित खबरें मीडिया में आने के बाद यह मुद्दा संसद में भी गरमाया रहा. कुछ भाजपा सांसदों ने पूरे मामले की नए सिरे से जांच कराने की भी मांग की. सांसदों का कहना था कि इसमें दलाली की रकम खाने से बड़ा सवाल देश की सुरक्षा से जुड़ा है. अजय अग्रवाल ने अपनी याचिका में यह सवाल भी खड़ा किया है कि जब फ्रांस की सोफमा तोपें सैन्य अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों की नज़र में बोफोर्स तोपों के मुकाबले बेहतर थीं तथा फ्रांस इसकी तकनीक व गोला-बारूद देने को भी तैयार था, तो बोफोर्स तोपें खरीदी ही क्यों गईं? अगर हमारी सेना के पास बोफोर्स से ज़्यादा दूरी तक निशाना साधने वाली सोफमा तोपें होती, तो शायद कारगिल युद्ध में इतनी बड़ी संख्या में हमारे जवानों की मौत नहीं होती और हम युद्ध में फतह भी जल्दी हासिल कर लेते.

बहरहाल संसद में उठे सवालों के बाद याचिकाकर्ता अग्रवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को भी एक पत्र भेजा है. 28 जुलाई को भेजे गए इस पत्र में दलाली की रकम को अवैध तरीके से हस्तांतरित करने, क्वात्रोच्ची के खातों पर लगी रोक हटाने की फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अन्तर्गत जांच कराने की मांग की गई है. जाहिर है, यदि सर्वोच्च न्यायालय, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय बोफोर्स मामले की नए सिरे से जांच करते हैं, तो घोटाले की नई परतें तो खुलेंगी ही, साथ ही सोनिया गांधी भी जांच की जद में जरूर आएंगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

सीएजी का ख़ुलासा : ख़ुद आईसीयू में है देश का स्वास्थ्य विभाग

बीमार भारत कैसे बनेगा न्यू इंडिया

भारत सरकार अपनी जीडीपी का महज 1.4 फीसदी हिस्सा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इस्तेमाल करती है. इतने कम बजट में से भी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए आवंटित पैसा अगर देश के 27 राज्य खर्च ही नहीं करें, तो क्या होगा? सीएजी रिपोर्ट के इस खुलासे का परिणाम जो भी हो, लेकिन ऐसी अनियमितताओं का ही असर है कि आजादी के 70 साल का जश्न गोरखपुर की मांओं के आंसुओं के सैलाब में धुल गया.

निरंजन मिश्रा

हमारे देश में हादसा होने के बाद ही सरकारें जगती हैं, सिस्टम तब एक्शन में नहीं आता जब उस हादसे से पहले किसी अनियमितता से जुड़ी रिपोर्ट सामने आती है. सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएं समय-समय पर हमारी व्यवस्था की खामी उजागर करने वाली रिपोर्ट्स सार्वजनिक करती रहती हैं. लेकिन हमारी सरकार और व्यवस्था गलतियों से सीख लेने की जगह उनकी लीपापोती में जुट जाती है और यही कारण है कि हमें गोरखपुर जैसे हादसों का सामना करना पड़ता है. 2 महीने पहले भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने संसद में जो रिपोर्ट पेश की, उसमें स्वास्थ्य सेवाओं में हुई अनियमितता का भी जिक्र था. लेकिन सरकारी और सियासी हलकों में उसे लेकर कोई आवाज नहीं उठी.

इस रिपोर्ट में सीएजी ने 2011 से 2016 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यकलाप और खर्चों का ब्यौरा पेश किया है. इस रिपोर्ट में जो चौंकाने वाली बात है वो ये कि 27 राज्यों ने इस योजना के मद में दिए गए पैसे को खर्च ही नहीं किया. गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण

हैरानी की बात ये है कि 13 राज्यों के 67 स्वास्थ्य केंद्रों में कोई डॉक्टर ही नहीं है. डॉक्टर और स्टाफ की कमी के कारण स्वास्थ्य उपकरण भी बेकार हो रहे हैं और मरीजों को उनका लाभ भी नहीं मिल रहा. सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 17 राज्यों में 30 करोड़ की लागत वाले अल्ट्रा साउंड मशीन, एक्स रे मशीन, ईसीजी मशीन जैसे कई उपकरणों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, क्योंकि उन्हें ऑपरेट करने वाले मेडिकल स्टाफ नहीं हैं. साथ ही ज्यादातर अस्पतालों में इन्हें रखने के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं है, जिसके कारण ये बेकार पड़े-पड़े खराब हो रहे हैं. सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कई अस्पतालों की जिक्र भी किया है.

स्वास्थ्य मिशन बहुत महत्वपूर्ण योजना है. इस योजना के मद में 2011-12 में 7,375 करोड़ और 2015-16 में 9,509 करोड़ की राशि दी गई थी, जो ख़र्च ही नहीं हो सकी. सीएजी ने तो अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि देश के 20 राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े 1285 प्रोजेक्ट कागज़ों पर चल रहे हैं. उनके नाम पर पैसों की उगाही हो रही है, लेकिन वे जमीन पर हैं ही नहीं.

सीएजी रिपोर्ट का ये खुलासा तो और भी चिंतनीय है कि 27 राज्यों के लगभग हर स्वास्थ्य केंद्र में 77 से 87 फीसदी डॉक्टरों की कमी है. हैरानी की बात ये है कि 13 राज्यों के 67 स्वास्थ्य केंद्रों में कोई डॉक्टर ही नहीं है. डॉक्टर और स्टाफ की कमी के कारण स्वास्थ्य उपकरण भी बेकार हो रहे हैं और मरीजों को उनका लाभ भी नहीं मिल रहा. सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 17 राज्यों में 30 करोड़ की लागत वाले अल्ट्रा साउंड मशीन, एक्स रे मशीन, ईसीजी मशीन जैसे कई उपकरणों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, क्योंकि उन्हें ऑपरेट करने वाले मेडिकल स्टाफ नहीं हैं. साथ ही ज्यादातर अस्पतालों में इन्हें रखने के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं है, जिसके कारण ये बेकार पड़े-पड़े खराब हो रहे हैं. सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कई अस्पतालों का जिक्र भी किया है. रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात के नडियाड जनरल अस्पताल में ऑपरेशन थियेटर तो है, लेकिन ऑपरेशन के पहले और बाद में मरीज़ को रखने के लिए कमरे नहीं हैं, साथ ही जगह की कमी के कारण लैब का काम भी मरीज़ों के वेटिंग एरिया में ही होता है. वहीं गोधरा के जनरल अस्पताल में मरीजों के लिए 440 बिस्तर की ज़रूरत है, लेकिन 210 बेड ही उपलब्ध हैं. नतीजतन सैकड़ों मरीज फर्श पर लेटे हुए इलाज कराते हैं. झारखंड में तो 17 प्राइमरी हेल्थ सेंटर बिना इमारत के ही चल रहे हैं. झारखंड के 5 ज़िला अस्पतालों में 32 स्पेशल ट्रीटमेंट सुविधाओं में से 6 से 14 सुविधाएं ही उपलब्ध हैं. केरल की 1100 से अधिक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (सीएससी) और प्राइमरी हेल्थ सेंटर (पीएचसी) में से सिर्फ 23 में डिलीवरी की सुविधा है. बिहार की हालत तो और भी खराब है. यहां जननी सुरक्षा योजना के तहत 40 फीसदी योग्य महिलाओं को टीके ही नहीं दिए गए.

हमारे देश में आज भी औरतों और लड़कियों की एक बड़ी आबादी आयरन की कमी के कारण होने वाली एनिमिया से जूझ रही है. प्रसव के दौरान पचास फीसदी माएं एनिमिया से मर जाती हैं. इसके बाद भी हालत ये है कि प्राथमिक केंद्रों में महिलाओं को आयरन टैबलेट दी ही नहीं जा रही है. ये हाल किसी एक राज्य या शहर का नहीं है, पूरे देश की यही हालत है. सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि एनएचआरएम सेंटर में गर्भवती महिलाओं को सौ फौलिक एसिड टेबलेट देनी होती है, लेकिन ऑडिट के दौरान 28 राज्यों में इसके वितरण में 3 से 75 फीसदी की कमी मिली. अरुणाचल, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर और मेघालय में तो 50 फीसदी गर्भवती महिलाओं को टेटनस का टीका भी नहीं दिया जा सका है.

एक दूसरी रिपार्ट कहती है कि भारत में होने वाली 27 फीसदी मौत का कारण है, सही समय पर इलाज न मिलना. देश में सरकारी इलाज की सुविधा का आलम ये है कि यहां 61,011 लोगों पर एक अस्पताल, 1,833 मरीजों पर एक बेड और 1,700 मरीजों पर एक डाक्टर उपलब्ध है. ये आंकड़े बताते हैं कि देश की स्वास्थ्य सुविधा खुद ही आईसीयू में है. केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद सस्ते मेडिकल बीमा को लेकर खूब ढोल पिटा गया. जनता को भी लगने लगा था कि अब शायद उन्हें इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़ना पड़ेगा. लेकिन हकीकत ये है कि 86 फीसदी ग्रामीण और 82 फीसदी शहरी आबादी के पास मेडिकल बीमा है ही नहीं. आर्थिक विकास से लेकर सामरिक समृद्धि तक, हर क्षेत्र में हम अमेरिका से खुद की तुलना करते हैं, लेकिन इसपर कभी भी हमारा ध्यान नहीं जाता कि अमेरिका अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं पर जीडीपी का 8.3 फीसदी खर्च करता है, जबकि हम सिर्फ 1.4 फीसदी. ये सोचने वाली बात है कि हमारे देश में अस्पताल, बेड, डाक्टर, दवाई सभी के हालात त्रासदी दायका हैं, लेकिन फिर भी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च क्यों नही करती. स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में दुनिया के 188 देशों की रैंकिंग में भारत का नंबर 143वां है. इस स्वतंत्रता दिवस को प्रधानमंत्री जी ने लालकिले से ऐलान किया कि 2022 तक भारत न्यू इंडिया बन जाएगा, लेकिन सोचने वाली बात है कि जिसका स्वास्थ्य विभाग खुद आईसीयू में हो, वो बीमार भारत न्यू इंडिया कैसे बनेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

न आना इस देश में बच्चों...

लड़कियों के प्रति सामाजिक उपेक्षा के भाव को देखते हुए किसी ने ये नारा गढ़ा था कि 'न आना इस देश में लाडो', लेकिन हम बात कर रहे हैं, व्यवस्था के उस उपेक्षा की, जो लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए समान रूप से है. ये वो उपेक्षा है, जो हमारे देश में जन्म लेने वाले 7,30,000 बच्चों को जन्म के एक महीने के भीतर ही मरने पर मजबूर कर देती है. ये वो उपेक्षा है, जो 10,50,000 बच्चों को पहला जन्मदिन भी नहीं मनाने देती. यही उपेक्षा हमें भी ये कहने पर मजबूर करती है कि 'न आना इस देश में बच्चों.' हमारे ये कहने के पिछे का दर्द ये है कि भारत में जन्म लेने वाले 40 फीसदी बच्चे 5 साल की उम्र पूरा करने से पहले मर जाते हैं. ऐसे बच्चों की संख्या 2,91,288 है, जो अपना पांचवा जन्मदिन भी नहीं मना पाते. वहीं 14 वर्ष के 4,31,560 बच्चों की मौत हर साल होती है. 2016 में ही निमोनिया और डायरिया से 2,96,279 बच्चों की मौत हो गई. ये सभी आंकड़े वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) के हैं. आजादी के 70 साल बाद भी अगर निमोनिया और डायरिया से हर साल लाखों बच्चे मर रहे हैं, तो ये भारत जैसे देश के लिए शर्मिंदगी की बात है. शर्म करने वाली बात तो ये भी है कि बम-गोला-बारूद के मामले में अग्रणी देशों की सूची में शामिल होने के लिए अथक प्रयास कर रहा हमारा देश बच्चों की एक बड़ी आबादी की भूख मिटा पाने में भी असमर्थ है. डब्ल्यूएचओ की ही रिपोर्ट कहती है कि भूखे बच्चो की तादाद में 118 देशों की सूची में भारत का स्थान 97 वां है. यानि हम नीचे से 21वे नम्बर पर हैं. ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब हम अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकते, तो फिर स्वस्थ कैसे रख सकते हैं. वर्तमान समय में जबकि हमारी सरकार के लिए देश की अंदरूनी स्थिति नहीं, बल्कि वैश्विक संस्थाओं की रिपोर्ट मायने रखती है, इस समय डब्ल्यूएचओ की ये रिपोर्ट्स सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है. डब्ल्यूएचओ की ही रिपोर्ट बताती है कि भारत में अभी 39 फीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं. 6 साल तक के 2 करोड़ 30 लाख बच्चे कुपोषित हैं, जिनका शारीरिक विकास रुक गया है. कुपोषण जनित बीमारियों के कारण हर साल लगभग 10 लाख बच्चे दम तोड़ देते हैं. इतना ही नहीं, गंदे पानी के कारण होने वाली बीमारियों से हर साल करीब 15 लाख बच्चे मर जाते हैं. हद तो ये है कि वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों से हर वर्ष जो 10 लाख लोग मरते हैं, उनमें से आधे बच्चे होते हैं. देश में हर वर्ष 12 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसी बीमारियों से मर जाते हैं, जिनका इलाज संभव है. लेकिन अफसोस कि वो साधारण इलाज भी भारत में संभव नहीं है. जहां सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य क्रेंद्र तक पहुंचने के लिए भी सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती हो, जहां शहरों में भी एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो और जहां गार्ड ही कम्पाउंडर का काम करे, वहां हम कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी की आशा कर सकते हैं. शिशु मृत्य दर के मामले में भारत का हाल इतना खराब है कि प्रति हजार बच्चों में से 37 बच्चे पैदा होते ही मौत के मुंह में चले जाते हैं, वहीं मातृ मृत्यु दर अभी भी 167 है. ये हाल तब है, जबकि इनमें कमी आई है. 21 मार्च 2017 को राज्यसभा में ये आंकड़े गिनाते हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया था, जबकि सरकार के लिए ये एक बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए. गौरतलब है कि जो शिशु मृत्यु दर हमारे देश में 37 है, वो विकसित देशों में 5 से भी कम है. ■

शिशु स्वास्थ्य के निम्न तीन मामलों में 5 फिसड्डी राज्य

5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चे	सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर	जिन्हें मां का पहला दूध नहीं मिलता
बिहार- 48.3	यूपी- 64	यूपी 75
यूपी- 46.3	छत्तीसगढ़- 54	उत्तराखंड 72.2
झारखंड- 45.3	मध्य प्रदेश- 51	राजस्थान 70.6
मेघालय- 43.8	असम- 48	दिल्ली 70.9
मध्य प्रदेश- 42	बिहार- 48	पंजाब 69.3

ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के आंकड़े हैं. दिए गए सभी आंकड़े प्रतिशत में हैं.

हादसे के बाद जागने की आदत बदलनी होगी

सदर अस्पताल के स्पेशल न्यू बर्न केयर यूनिट में नवजात बच्चों के इलाज के लिए 11 रेडिएंट वार्मर मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन इनमें से आठ मशीनों में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है. कहने के लिए पांच ऑक्सीजन कांसेंट्रेटर मशीनें लगी हैं, लेकिन तीन ऑक्सीजन कांसेंट्रेटर मशीनें काम नहीं करती हैं. एक तरह से देखा जाए, तो 11 में तीन मशीनें ही पूर्ण रूप से काम कर रही हैं. इन्हें चलाने के लिए चार डॉक्टरों व करीब एक दर्जन एएनएम की ड्यूटी लगी है. जरूरत पड़ने पर कभी न तो एएनएम मिलती हैं और न ही डॉक्टर.

सरोज सिंह

हादसे के बाद जागने की आदत ने गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो विनाशलीला मचाई, उससे सारा देश स्तब्ध है. ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चों की मौत ने पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आजादी के इतने साल बाद भी हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के मामले में कितने पीछे हैं. साठ से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद हर अस्पताल में जीवनरक्षक उपकरणों और दवाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा हो रही है. ऐसी घटना दोबारा किसी सरकारी या निजी अस्पताल में न हो, इसके लिए शासन-प्रशासन भी सक्रिय हो गया है. बिहार के नामी-गिरामी अस्पतालों में भी समीक्षा का दौर जारी है और कोशिश है कि समय रहते सबकुछ दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि गोरखपुर की घटना दोहराई न जा सके. लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि आखिर इतनी देर के बाद क्यों!

सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में ऑक्सीजन को लेकर जब पड़ताल की गई, तो पता चला कि अभी यहां बहुत कुछ किया जाना बाकी है. हालांकि प्राचार्य ने गोरखपुर हादसे के बाद यह व्यवस्था की है कि हर रोज ऑक्सीजन के स्टॉक को चेक किया जाए और यह सुनिश्चत किया जाए कि ऑक्सीजन की कमी न होने पाए. पीएमसीएच में गंभीर नवजात का इलाज हो, इसके लिए शिशु वार्ड में 24 बेडों का अलग से एनआईसीयू बन कर तैयार है, लेकिन ऑक्सीजन पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं होने से एनआईसीयू शुरू नहीं हो पा रहा है. एनआईसीयू उद्घाटन के इंतजार में है. नतीजतन पुराने आईसीयू में नवजातों की संख्या बढ़ गई है और एक बेड पर तीन बच्चों का उपचार किया जा रहा है. ऐसे में जब ऑक्सीजन की कमी होती है, तो छोटा सिलिंडर लाना पड़ता है. यह स्थिति स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, टाटा और हथुआ वार्ड में भी है. अस्पताल अधीक्षक डॉ. लखींद्र प्रसाद कहते हैं कि हमारे यहां ऑक्सीजन से लेकर सभी तरह की व्यवस्था दुरुस्त है. रही बात शिशु वार्ड में एनआईसीयू शुरू नहीं होने की, तो वहां ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम होना बाकी है. बिजली आपूर्ति के लिए संबंधित कंपनी से बात चल रही है. जल्द ही 24 बेडों के एनआईसीयू की सुविधा मिलेगी. पटना के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल आईजीआईएमएस के जनरल वार्ड में अभी तक ऑक्सीजन पाइप लाइन की व्यवस्था नहीं की गई है. यहां कागजों पर ही सभी वार्ड में ऑक्सीजन पाइप लाइन बिछाने की बात चल रही है, जबकि आईजीआईएमएस के जनरल वार्ड में 500 से अधिक बेड हैं, जहां मरीज भरती रहते हैं. जनरल वार्ड में खासकर बच्चा वार्ड, हड्डी, सामान्य औषधि विभाग, सांस रोग विभाग, यूरोलॉजी विभाग और कैंसर आदि कुछ ऐसे वार्ड हैं, जहां ऑक्सीजन की काफी जरूरत पड़ती है. यहां मरीजों को छोटे सिलिंडर से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है. बड़ी बात यह है कि मरीज के परिजन सिलिंडर के लिए इधर-उधर भटकते रहते हैं. अगर समय पर टेकिनिशियन नहीं मिला, तो मरीजों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती है. पटना से बाहर निकलें तो सीवान सदर अस्पताल के स्पेशल न्यू बर्न केयर यूनिट में नवजात बच्चों के इलाज के लिए 11 रेडिएंट वार्मर मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन इनमें से आठ मशीनों में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है. कहने के लिए पांच ऑक्सीजन कांसेंट्रेटर मशीनें लगी हैं, लेकिन तीन ऑक्सीजन कांसेंट्रेटर मशीनें काम नहीं करती हैं. एक तरह से देखा जाए, तो 11 में तीन मशीनें ही पूर्ण रूप से काम कर रही हैं. इन्हें चलाने के लिए चार डॉक्टरों व करीब एक दर्जन एएनएम की ड्यूटी लगी है. जरूरत पड़ने पर कभी न तो एएनएम मिलती हैं और न ही डॉक्टर.

बक्सर सदर अस्पताल में कुल 58 ऑक्सीजन सिलिंडर एवं चार इलेक्ट्रिक ऑक्सीजन मशीनें मौजूद हैं. सदर अस्पताल में पहले की अपेक्षा जीवनरक्षक संसाधनों में कमी हुई है, जिसके कारण अस्पताल की आईएसओ की सुविधा भी छिन चुकी है. सदर अस्पताल के सभी वार्डों में ऑक्सीजन सिलिंडर पर्याप्त होने के साथ स्टोर में भी सात सिलिंडर अभी सुरक्षित रखे गए हैं. इसके साथ ही इलेक्ट्रिक संचालित तीन यूनिट्स भी मौजूद हैं.

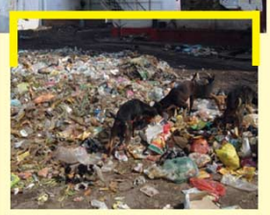

बक्सर सदर अस्पताल में कुल 58 ऑक्सीजन सिलिंडर एवं चार इलेक्ट्रिक ऑक्सीजन मशीनें मौजूद हैं. सदर अस्पताल में पहले की अपेक्षा जीवनरक्षक संसाधनों में कमी हुई है, जिसके कारण अस्पताल की आईएसओ की सुविधा भी छिन चुकी है. सदर अस्पताल के सभी वार्डों में ऑक्सीजन सिलिंडर पर्याप्त होने के साथ स्टोर में भी सात सिलिंडर अभी सुरक्षित रखे गए हैं. इसके साथ ही इलेक्ट्रिक संचालित तीन यूनिट्स भी मौजूद हैं. सदर अस्पताल के लिए कुल 32 एवं एसएनसीयू के लिए कुल 26 सिलिंडर हैं, जिसमें 26 सिलिंडर रिफिल होने के लिए पटना भेजे गए हैं. गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में महज दो ऑक्सीजन कांसंट्रेटर मशीन के भरोसे ही ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है. इस मशीन में नियमानुसार एक बार में एक ही मरीज को जोड़ा जा सकता है, लेकिन इमरजेंसी वार्ड में इस मशीन में एक साथ दो-तीन मरीज भी जोड़े जाते हैं. जो व्यवस्था है, उसी के बीच मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाता है. वार्ड में मशीन कम करने से कई बार मरीजों को परेशानी होती है. अगर मरीज की संख्या बढ़ती है, तो उपलब्ध ऑक्सीजन सिलिंडर का उपयोग किया जाता है. वहीं सिलिंडर उपलब्ध नहीं होने पर परेशानी बढ़ जाती है. देखा जाए तो पूरे बिहार के अस्पतालों में अभी सुधार की बहुत गुंजाइश है. अच्छी बात यह है कि बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग के आला अफसर खुद पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. अस्पताल के प्रभारी भी मामले की गंभीरता को देखते हुए सुधार की दिशा में लगे हुए हैं.

गोरखपुर में ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से बच्चों की सामूहिक मौत के बाद बिहार के बड़े अस्पताल अलर्ट हैं. पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच दरभंगा, एसकेएमसीएच गया सहित बड़े अस्पतालों में व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जा रही है. गया व मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज में एईएस से पीड़ित बच्चों की काफी संख्या में भर्ती होने के कारण उनकी सघन निगरानी की जा रही है. स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के बाद पीएमसीएच में बड़ा बदलाव किया गया है. शिशु रोग विभाग में सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई पाइपलाइन में तत्काल 30 और प्वाइंट बढ़ाने के लिए विभागाध्यक्ष ने अधीक्षक को पत्र भेजा है. जबकि इमरजेंसी में रखे एक्सपायरी अग्निशमन सिलेंडर को तत्काल हटा दिया गया है. पीएमसीएच के लिए अतिरिक्त डेढ़ सौ ऑक्सीजन सिलेंडर को सुरक्षित रखा गया है. शिशु रोग विभाग के वार्ड में 250 बेड हैं. गंभीर बच्चों के उपचार के लिए 40 बेड हैं, जहां ऑक्सीजन पाइपलाइन है. विभागाध्यक्ष डॉ. एके जायसवाल ने बताया कि तत्काल 30 और ऑक्सीजन प्वाइंट बढ़ाने के लिए अधीक्षक से कहा गया है, ताकि गंभीर बच्चों की संख्या बढ़ने पर इलाज में कोई दिक्कत न हो. वार्ड में 50 ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए हैं, ताकि इमरजेंसी में इस्तेमाल किए जा सकें.

गोरखपुर हादसे से सबक लेते हुए अस्पताल प्रशासन एहतियाती कदम उठा रहे हैं. लेकिन सवाल यह है कि हादसे से पहले ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मरीजों खासकर बच्चों की जान जाने के बाद ही हम अस्पतालों की व्यवस्थता को लेकर चिंतित दिखते हैं. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय कहते हैं कि हम चूक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे. सूबे के हरेक नागरिक की जान हमारे लिए कीमती है. सबको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है. पांडेय का मानना है कि गोरखपुर में जो हुआ, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. बिहार सरकार खासकर स्वास्थ्य महकमा पूरी कोशिश कर रहा है कि जो कुछ भी कमियां हैं या जो कमियां विभिन्न माध्यमों से हमारे संज्ञान में आ रही हैं, उसे जल्द से जल्द दुरुस्त कर दिया जाए. मंगल पांडेय अपील करते हैं कि इस बड़े काम में प्राइवेट अस्पताल व अन्य लोग भी सहयोग करें, ताकि इलाज के अभाव में किसी की जान न जाए.■

feedback@chauthiduniya.com

डायरिया, टीबी और मधुमेह

भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती है

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

भारत में साल 2015 में रोजाना 321 बच्चों की मौत डायरिया से हुई. विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए हैं. भारत में डायरिया की रोकथाम के उपायों के बावजूद यह बीमारी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है. डायरिया की रोकथाम केवल साफ-सफाई और साफ पीने के पानी से संभव है. डायरिया की वजह से होने वाली मौत का आंकड़ा ये बताता है कि भारत में साफ-सफाई और पीने के पानी का क्या हाल है? डायरिया बच्चों में कुपोषण का भी कारण बनता है. डायरिया का इलाज आसान है, लेकिन भारत में ये आसान लगने वाला इलाज भी सर्वसुलभ नहीं है. 2015-16 में आधे के करीब बच्चों को ही ओआरएस की सप्लाई की जा सकी थी, जिससे भारत की हेल्थ सिस्टम की दुर्दशा का पता चलता है. यूनिसेफ डेटा के मुताबिक, 2015 में भारत में 1,17,285 बच्चों की डायरिया से मौत हुई, जिनकी उम्र 5 साल से कम थी, जबकि पाकिस्तान, केन्या, म्यानमार जैसे देशों में इससे कम मौतें हुईं. गौरतलब है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय इन देशों की तुलना में कहीं अधिक है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा के मामले में भारत इन देशों से भी पीछे है. हालांकि, मौत का ये आंकड़ा पिछले कुछ सालों के मुकाबले घटा है. 2010 में जहां ऐसी मौतों की संख्या 1,67,000 थी, वहीं 2015 में ये संख्या 1,17,000 रही. ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि 2005 में लॉन्च नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ज्यादातर बच्चों को ओआरएस बांटे गए. रोटावायरस की वजह से होने वाली डायरिया काफी खतरनाक मानी जाती है और इसका इलाज रोटावायरस का टीका है, लेकिन दुर्भाग्य से इसे मिशन इन्द्रधनुष में शामिल नहीं किया गया है. प्राइवेट अस्पतालों से ये टीका लगवाना काफी महंगा है. जाहिर है, डायरिया जैसी बीमारी हमारे स्वच्छ भारत अभियान की भी पोल खोलती है.

नियंत्रण से बाहर है टीबी – विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत डब्लूएचओ द्वारा बताए गए टीबी नियंत्रण के 16 उपायों में से 6 पर ध्यान नहीं दे रही है. इसके अलावा, टीबी नियंत्रण के लिए चल रही राष्ट्रीय नीति में शामिल 4 नीतियों का भी क्रियान्वयन पूरी तरह से नहीं हो रहा है. यह तथ्य आउट ऑफ स्टेप नाम की एक रिपोर्ट से सामने आई है. यह स्टडी 29 देशों में चलाई जा रही टीबी नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा करती है. दुनिया भर में भारत सबसे अधिक टीबी के प्रकोप से ग्रसित है. साल 2015 में भारत में करीब 28 लाख टीबी के मरीज थे. वैसे तो टीबी का इलाज है और इसकी रोकथाम भी की जा सकती है, फिर भी यह दुनिया की सबसे खतरनाक संक्रमणकारी बीमारी है. अकेले 2015 में टीबी ने दुनिया भर में करीब 18 लाख लोगों की जिन्दगी छीन ली. भारत में टीबी की डायगोनोसिस और ड्रग रेसिस्टेंट ट्रीटमेंट ऐसे दो क्षेत्र हैं, जहां अब भी भारत को अपने नेशनल टीबी पॉलिसी में बहुत काम करना है और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के अनुरूप बनना है. भारत ने अभी तक बच्चों और व्यस्कों में टीबी के प्रारंभिक जांच के लिए आवश्यक एमटीबी/आरआईएफ नहीं बनाया है. यह त्वरित रूप से टीबी को डायग्नोस करता है और बीमारी से लड़ने के लिए आवश्यक ड्रग की अनुशंसा करता है. एक तरफ पूरी दुनिया में टीबी को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है. लेकिन, दुख की बात ये है कि इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित लोग भारत में ही हैं. भारत में टीबी के मरीजों की संख्या अनुमान से तीन गुणा ज्यादा हो सकती है. मशहूर मेडिकल पत्रिका लेसेंट ने साल 2014 में किए एक अध्ययन में पाया कि भारत में निजी क्षेत्र में करीब 19 लाख से लेकर 53 लाख तक मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जो सरकारी अस्पतालों में इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या से दोगुनी है. इस अध्ययन से पहले अनुमान था कि भारत में करीब 22 लाख तपेदिक के मामले हो सकते हैं, जो दुनिया भर के तपेदिक मामलों का एक-तिहाई है. दुनिया भर में करीब 63 लाख तपेदिक के मरीज होने का अनुमान है. इस अध्ययन में बताया गया है कि भारत में टीबी का मानकीकृत इलाज केवल सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है. लेकिन इसका समय पर पता लगाना और निदान करना अनियमित निजी स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़े पैमाने पर उपस्थिति के कारण संभव नहीं हो पा रहा है. अध्ययन में कहा गया है कि टीबी की जांच का मुकम्मल ढांचा नहीं होने तथा इलाज में देरी के कारण भारत में टीबी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जबकि निजी क्षेत्र में जिन मामलों का इलाज चल रहा होता है, उसे वे सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को अधिसूचित नहीं करते. शोधकर्ताओं के मुताबिक, शोध के निष्कर्षों से यह पता चला है कि निजी क्षेत्र द्वारा किए जा रहे टीबी के इलाज की निगरानी बढ़ाने की जरूरत है. हालांकि देश में टीबी के मरीजों की संख्या में कमी आ रही है, लेकिन दवाइयों के प्रति बीमारी की प्रतिरोध क्षमता में बढ़ोतरी से प्रगति काफी धीमी है. भारत में टीबी के कुल मामलों में से 10 फीसदी बच्चों में होते हैं, लेकिन सिर्फ छह फीसदी का ही पता चल पाता है. बच्चों में टीबी को अक्सर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि बच्चों में इसकी जांच और इलाज करना बहुत मुश्किल होता है.

एक तरफ पूरी दुनिया में टीबी को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है. लेकिन, दुख की बात ये है कि इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित लोग भारत में ही हैं. भारत में टीबी के मरीजों की संख्या अनुमान से तीन गुणा ज्यादा हो सकती है. मशहूर मेडिकल पत्रिका लेसेंट ने साल 2014 में किए एक अध्ययन में पाया कि भारत में निजी क्षेत्र में करीब 19 लाख से लेकर 53 लाख तक मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जो सरकारी अस्पतालों में इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या से दोगुनी है.

शहरी गरीबों पर बढ़ रहा है मधुमेह का ख़तरा – दुनिया भर में करीब 35 करोड़ लोग मधुमेह (डायबिटिज) के शिकार हैं. इनमें से करीब 6.3 करोड़ अकेले भारत में हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2030 तक डायबिटीज लोगों की मौत का सातवां सबसे बड़ा कारण होगा. डायबिटिज को एक समय अमीरों का रोग माना जाता था. लेकिन आज यह शहरी गरीबों में तेजी से फैल रहा है और इसे रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है. ये कहना है भारत के प्रसिद्ध डायबेटोलॉजिस्ट वी मोहन का. वी मोहन इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 15 राज्यों में कराए गए एक स्टडी में शामिल हुए थे. यह शोध बाद में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लैंसेट में 7 जून 2017 को प्रकाशित हुई थी. चीन के बाद भारत में सबसे अधिक डाइबिटिज पीड़ित हैं. ये जाहिर तौर पर जीवन शैली और खाने की वजह से है. सर्वे में 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 57,000 लोगों को शामिल किया गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक रूप से अधिक सम्पन्न माने जाने वाले सात राज्यों के शहरी इलाकों में सामाजिक-आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति वाले तबके के मुकाबले सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर तबके में मधुमेह के रोगियों की संख्या अधिक है. उदाहरण के लिए, चंडीगढ़ के शहरी इलाकों में सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के बीच मधुमेह की दर 26.9 फीसद पाई गई, जो अच्छी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के बीच 12.9 प्रतिशत की दर से कहीं अधिक है. चिकित्सकों के लिए ही नहीं, वल्कि आम आदमी के लिए भी यह चिंता की बात है. भारत को विश्व की मधुमेह राजधानी के रूप में जाना जा रहा है और 2025 तक यहां 5 से 7 करोड़ मधुमेह रोगी होने की आशंका है. मधुमेह अमीर की हहलीज लांघ कर अब गरीब की चौखट पर भी दस्तक देने लगा है.■

खोखले वादों की दस्तावेज़ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

शफीक आलम

तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के रहने वाले 30 वर्षीय मुरुगन एक सड़क हादसे में बुरी तरह से ज़ख़्मी हो गए. एम्बुलेंस उन्हें लेकर सात घंटे तक केरल के कोल्लम और तिरुवनंतपुरम के कई अस्पतालों का चक्कर लगाती रही, लेकिन किसी अस्पताल ने उन्हें भर्ती नहीं किया. समय पर उपचार न मिलने से उनकी मौत हो गई. ख़बरों में बताया गया कि जिन अस्पतालों में उन्हें ले जाया गया, उन्होंने गवाहों के अभाव में मुरुगन को भर्ती करने से इंकार कर दिया. इसी से मिलती-जुलती एक खबर राजधानी दिल्ली से आई, जहां एक नवजात, जिसके दिल में सुराख़ थी, के माता-पिता दिल्ली के अलग-अलग अस्पतालों में लेकर दौड़ते रहे. कहीं फ़ीस नहीं चुका सकने के कारण भर्ती नहीं मिली तो कहीं ईडब्लूएस (आर्थिक रूप से कमज़ोर) कोटे के तहत बेड खाली नहीं होने का बहाना बना दिया गया. एक अस्पताल ने भर्ती भी किया तो केवल रात भर के लिए.

ज़ाहिर है ये देश में कोई अनोखी घटनाएं नहीं हैं. अस्पतालों की बेईमानी की कहानी अक्सर अखबारों की सुर्ख़ियों में रहती हैं. इन दो हालिया घटनाओं की तरफ ध्यान आकर्षित करने का मकसद यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 को अनुमोदित कर दिया है. सरकार की ओर से जारी 30 पन्नों के इस दस्तावेज़ को देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के इतिहास में बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा रहा है. यह भी दावा किया जा रहा है कि एनएचपी 2017 बदलते सामाजिक-आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और महामारी-विज्ञान परिदृश्य में मौजूदा और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए अस्तित्व में आई है. यह नीति राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 का स्थान लेगी. इस दस्तावेज़ में यह भी कहा गया है कि एनएचपी 1983 और एनएचपी 2002 ने पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान स्वास्थ्य नीति को सही दिशा देने का कार्य किया.

नई स्वास्थ्य नीति की प्रस्तावना में जो तारीफ की गई है, उसे समझने के लिए मेडिकल जर्नल 'द लैंसेट' में प्रकाशित 'ग्लोबल बर्डेन ऑफ डिजीज स्टडी' पर एक नजर डालनी होगी. इसके अनुसार, भारत स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं के मामले में 195 देशों की सूची में 154 वें स्थान पर है. शर्मिंदगी की बात यह है कि स्वास्थ्य सुविधाएं देने में भारत अपने पड़ोसियों श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन और भूटान से भी पीछे है. शिशु मृत्युदर के मामले में भारत की रैंकिंग सोमालिया और अफगानिस्तान से भी नीचे है. अब सवाल यह उठता है कि बेहतर ढंग से काम करने का यह नतीजा है तो नई स्वास्थ्य नीति से क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं. यह स्थिति तब है, जब भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 के प्रमुख लक्ष्य

- 2025 तक पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर कम कर 23 तक लाना.
- जीवन प्रत्याशा को 67.5 से बढ़ा कर 2025 तक 70 वर्ष करना
- नवजात शिशु मृत्यु दर को घटाकर 16 करना तथा मृत पैदा होने वाले बच्चों की दर को 2025 तक घटाकर 'एक अंक' में लाना.
- 2018 तक कुष्ठ रोग, 2017 तक कालाजार का उन्मूलन करना.
- क्षयरोग (टीबी) के नए रोगियों में 85 प्रतिशत से अधिक को रोगमुक्त करना तथा नए मामलों की व्याप्तता में कमी लाना, ताकि 2025 तक इसका उन्मूलन किया जा सके.
- 2025 तक दृष्टिहीनता के मामलों को वर्तमान स्तर से घटाकर एक-तिहाई करना.
- हृदवाहिका रोग, कैंसर, मधुमेह या सांस के पुराने रोगों से होने वाली अकाल मृत्यु को 2025 तक घटाकर 25 प्रतिशत तक करना.

नई स्वास्थ्य नीति में सबके लिए स्वास्थ्य के सिद्धांत पर काम करते हुए कमज़ोर वर्ग के लोगों को मुफ्त दवा और इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है. साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट को बढ़ाकर जीडीपी के 2.5 प्रतिशत के स्तर तक लाना, जो फ़िलहाल 1.5 प्रतिशत है. इसके अलावा बीमारियों, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के साथ जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है. नई नीति में सरकार का ध्यान प्राथमिक स्वास्थ्य पर अपेक्षाकृत अधिक केंद्रित करने की बात कही गई है. बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए निजी क्षेत्र पर भी निर्भर होने की बात की गई है, यानी इसके लिए प्राइवेट अस्पतालों का सहयोग लिया जाएगा. लेकिन प्राइवेट अस्पतालों से जुड़ी ऊपर दर्ज घटनाएं ये बताती हैं कि यह कम कितना मुश्किल है.

नई नीति में जो सिद्धांत और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, वो कागज़ पर देखने में तो बहुत शानदार लगते हैं, लेकिन उनका ज़मीन पर उतरना बहुत मुश्किल है. सबके लिए स्वास्थ्य को ही ले लीजिए. सबके लिए स्वास्थ्य पर हमेशा से जोर दिया जाता रहा है, लेकिन इस नीति में प्राइवेट सेक्टर को भी इससे जोड़ दिया गया है. गौरतलब है कि बड़े निजी अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि दिल्ली जैसे शहर में भी इस आदेश का पालन नहीं होता. बहरहाल केवल ज़िक्र मात्र कर देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता. गोरखपुर की घटना इसकी सबसे ज्वलंत मिसाल है. सच्चाई यह है कि देश में जिला स्तर की स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है. अस्पताल तो हैं, लेकिन डॉक्टर और दवाइयां नहीं हैं. बुनियादी ढांचा नहीं है. इन तमाम कमियों का एकमात्र इलाज प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बता कर सरकारें अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाती हैं.

दरअसल ज़रूरत इस बात की है कि सबके लिए स्वास्थ्य को कारगर बनाने के लिए कानून बनाया जाए और उसे सख्ती से लागू किया जाए. कई क्षेत्रों से शिक्षा और खाद्य सुरक्षा की तरह स्वास्थ्य को भी बुनियादी अधिकार बनाने की मांग उठ रही है. यहां तक कि 2015 में जारी इस पॉलिसी के ड्राफ्ट में इसे अधिकार बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया. दूसरी, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो सबसे बड़ी कमी नज़र आती है और जिसका जवाब इस नीति में नहीं मिलता है, वो है सरकारी फंडिंग के इस्तेमाल करने की क्षमता का अभाव. उसी तरह डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए 2001 से 2015 के बीच मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई गईं, लेकिन इससे नीति में स्थापित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है. आंकड़े बताते हैं कि केवल 11.3 प्रतिशत एलोपैथिक डॉक्टर ही सार्वजानिक क्षेत्र में काम करते हैं. चौथी दुनिया ने पिछले अंक में राष्ट्रीय मेडिकल आयोग बिल पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पर जोर दिया गया है. उसमें यह भी प्रावधान रखा गया है कि आयोग केवल 40 प्रतिशत सीटों की फीस को ही नियंत्रित कर सकता है. अब जिन कॉलेजों में कैपिटेशन फीस के नाम पर लाखों की उगाही की जाती है, वहां से निकलने वाले डॉक्टरों से मुफ्त इलाज की आशा कैसे की जा सकती है?

दरअसल केवल नीति बना देने मात्र से देश में स्वास्थ्य की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है. इसके लिए ज़रूरी है कि स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को प्राथमिक स्तर पर चुस्त-दुरुस्त किया जाए. निजी क्षेत्र की बजाय सार्वजनिक क्षेत्र को इसकी जिम्मेदारी दी जाए और सरकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज खोले जाएं. ज़रूरत इस बात की भी है कि इसके क्रियान्वयन के लिए सख्त कानून बनाया जाए. ■

feedback@chauthiduniya.com

कम बजट में कैसे सुधरे ग़रीबों का स्वास्थ्य

चंदन राय

देश में 80 फीसद शहरी और 90 फीसद ग्रामीण अपने सालाना खर्च का आधे से अधिक हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं. वहीं एक मरीज इलाज पर हुए खर्च का 70 फीसद दवाइयों पर खर्च करता है. इस वजह से चार फीसदी लोग हर साल गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं. नामी रिसर्च एजेंसी अर्न्स्ट एंड यंग ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है. नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि भारत की 80 फीसद से ज्यादा लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं. ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए उन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है और धीरे-धीरे वे ऋण जाल में फंसकर कंगाल हो जाते हैं.

सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि स्वास्थ्य राज्य सूची में शामिल होने के कारण केंद्रीकृत स्वास्थ्य योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं में समन्वय का अभाव होता है. कई स्वास्थ्य योजनाएं इसलिए निष्फल रहीं, क्योंकि उनमें राज्य सरकारों ने रुचि नहीं दिखाई. राज्यों के वित्तीय संकट और कुप्रबंधन, प्रशिक्षित चिकित्सकों व चिकित्सकीय उपकरणों की कमी और केंद्र सरकार द्वारा लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट की कमी के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में कोई सुधार नहीं दिख रहा है. महिलाओं और बच्चों की स्थिति सभी राज्यों में चिंताजनक बनी हुई है. हम विकासशील देशों के लिए हेल्थ हब के तौर पर विकसित तो हो रहे हैं, लेकिन देश में ये सुविधाएं कुछ धनाढ्य और मध्यवर्ग तक ही सीमित हैं. शिक्षा और खाद्य सुरक्षा की तरह स्वास्थ्य को आज तक नागरिकों के अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है. केंद्र सरकार कहती है कि राज्य ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं. वहीं राज्यों का तर्क है कि बुनियादी सुविधाओं व सीमित वित्तीय संसाधनों में ऐसा करना संभव नहीं है.

2015 में नीति आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं, मुफ्त दवाओं के वितरण और जांच पर खर्च कम करने के निर्देश दिए थे. देखा जाए तो अन्य विकासशील देशों के मुकाबले भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर अब भी काफी कम पैसे खर्च किए जाते हैं. सरकार एक तरफ तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भरता कम कर प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा दे रही है, वहीं सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है. एक अच्छी बात है कि देश में शिशु मृत्यु दर 2015 में घटकर 37 हो गई है, जबकि सरकार का यह लक्ष्य 27 का था. ग्रामीण क्षेत्रों में 41 और शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर 25 है. शिशु मृत्यु दर में कमी के बावजूद अभी हम किसी भी विकासशील देश से काफी पीछे हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक देश में दिल की बीमारियों से मरने वाले करीब 13 फीसद हैं. इसके बाद दमा, डेंगू, मलेरिया, डायरिया, सांस की परेशानी और टीबी जैसी बीमारियां से अधिक मौतें होती हैं.

बीमार तंत्र बना रहा ग़रीबों की हेल्थ पॉलिसी

ब्रिटिश सरकार जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी भूमिका सीमित करती जा रही है और प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा दे रही है. भारत भी एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहता है, जहां सरकारी और निजी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतियोगिता हो. इसमें सरकार की भूमिका निर्णायक की होगी, यानी जो अस्पताल बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेंगे या जिनका बेहतर रिकॉर्ड होगा, उनको सरकार आर्थिक मदद देगी. जाहिर है आंकड़ों की बाजीगरी में प्राइवेट अस्पताल हमेशा आगे रहेंगे और सरकारी मदद हथियाने की होड़ में वे सरकारी अस्पतालों को फिसड्डी साबित करने से भी पीछे नहीं रहेंगे. ऐसे में अभी तक आमलोगों को जो थोड़ी-बहुत स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में मिल जाती थी, उससे भी वे वंचित हो जाएंगे. ■

बदहाल स्वास्थ्य सेवा

राज्य	पीएचसी	पीएचसी डॉक्टर	सीएचसी	सीएचसी विशेषज्ञ	सरकारी डॉक्टर
मध्यप्रदेश	1156	814	333	267	4929
राजस्थान	1528	1755	382	148	9551
महाराष्ट्र	1811	2760	363	514	14509
केरल	809	1152	217	774	3878

स्रोत- सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलीजेंस 2012-13

वहीं, खबर है कि मोदी सरकार प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं को निजी डॉक्टर्स के हाथों सौंपने जा रही है. सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र की बेहतरी के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रतिस्पर्द्धा की पक्षधर है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा 2017 में सरकार इन फैसलों को अमलीजामा पहनाने जा रही है. मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा का अनुमोदन कर दिया है. सरकार ने कहा है कि स्वास्थ्य खर्च को जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने और बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रयास किए जा रहे हैं. लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकार जीडीपी का 2.5 प्रतिशत भी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करती है, तो यह कई विकासशील देशों की तुलना में काफी कम होगा. इतने कम बजट से प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में भी सुधार संभव नहीं है, बाकी के अन्य लक्ष्यों की बात तो जानें दें. अर्न्स्ट एंड यंग का भी मानना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत को जीडीपी का चार फीसद तक खर्च करना होगा.

ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर ही निर्भर होते हैं. पीएचसी में एक डॉक्टर नियुक्त होता है और वहां फर्स्ट ऐड या साधारण बीमारियों का इलाज होता है. सरकार के अथक प्रयास के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए डॉक्टर तैयार नहीं हैं. इसके अलावा सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय निवेश भी कम कर दिया है. ऐसे में अगर स्वास्थ्य सेवाओं को निजी हाथों में सौंप दिया गया, तब इन तक गरीबों की पहुंच मुश्किल होगी. सरकारी अस्पतालों की लचर व्यवस्था के बावजूद आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल जाता है. आलीशान फाइव स्टार अस्पतालों में गरीबों के इलाज का सपना सरकार जरूर देख सकती है, लेकिन धरातल पर यह दिवास्वप्न ही साबित होगा. सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को उद्योग का दर्जा बेशक दे, लेकिन जरूरी है कि सार्वजनिक चिकित्सा सेवा को निजी हाथों में न सौंपा जाए. ■

feedback@chauthiduniya.com

चारा घोटाले की सुनवाई में रांची आते हैं तो बड़े गुमसुम रहते हैं राजद सुप्रीमो

अब लालू समझ रहे अपनी मुश्किलें

प्रशान्त शरण

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का ग्रह नक्षत्र इन दिनों कुछ ज्यादा ही खराब चल रहा है. इधर सीबीआई ने चारा घोटाले के मामलों में भी लालू प्रसाद की मुश्किलें कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है. उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले की सुनवाई नौ माह में पूरी करने के आदेश के बाद सीबीआई की तीन विशेष अदालतों में चारा घोटाले की सुनवाई रोजाना हो रही है. लालू प्रसाद चारा घोटाले के चार मामलों में आरोपी हैं और चारो मामलों की सुनवाई अलग-अलग हो रही है. लालू प्रसाद ने अपने बचाव में लगभग 70 गवाहों की सूची अदालत को उपलब्ध कराई है. लेकिन गवाहों के बयान दर्ज होने के समय उन्हें भी सशरीर हाजिर रहने के आदेश से लालू प्रसाद की परेशानियां बढ़ गई हैं. सप्ताह में तीन दिन उन्हें कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है. सीबीआई अदालतों की सीढ़ियां चढ़ते-उतरते लालू थक से गए हैं और उनके चेहरे पर झल्लाहट साफ दिखाई पड़ती है. अपने चुटीले अंदाज के लिए जाने जाने वाले लालू इन दिनों गुमसुम रहते हैं. उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई है. मीडिया फ्रेंडली कहे जाने वाले लालू इन दिनों मीडिया से दूरी बनाए रहते हैं. काफी जोर आजमाईश के बाद ही वे मीडिया के सामने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं. लालू काफी दिनों के बाद मीडिया से तब मुखातिब हुए जब नीतीश कुमार ने राजद का साथ छोड़ कर भाजपा का दामन थाम लिया. लालू ने नीतीश को पलटू राम कहते हुए कहा कि भाजपा नेताओं के पास नीतीश का काला चिट्ठा है और उसे जब भाजपा नेताओं ने उजागर करने की धमकी दी, तब आनन-फानन में नीतीश राजद का साथ छोड़ भाजपा की गोद में जा बैठे.

लालू प्रसाद को इन दिनों चारा घोटाले की सुनवाई के दौरान सप्ताह में तीन दिन वृहस्पतिवार, शुक्रवार एवं शनिवार को रांची आना पड़ता है. इन तीनों दिन लालू के गवाहों के बयान दर्ज कराए जाते हैं. गवाहों के बयान दर्ज होने के दौरान लालू प्रसाद को अदालत में सशरीर हाजिर रहने का आदेश दिया गया है. इस अदालती आदेश से लालू परेशान तो जरूर हैं, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं बचा है. लालू ने कोर्ट से गुहार भी लगाई थी कि वे एक राजनेता हैं, उनके पास ढेरों राजनैतिक काम है. पटना में कार्यकर्ताओं कमी रैली है, लोकसभा चुनाव भी होना है. इसलिए उन्हें सशरीर हाजिर होने वाले आदेश में ढील दी जाय. वे अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी हाजिरी लगाएंगे. उन्होंने यह भी अनुरोध किया था कि उन्हें पटना से आने में परेशानी होती है. लेकिन सीबीआई अदालत ने को लालू की ये दलीलें रास नहीं आई, उसने लालू की गुहार को अनदेखा कर दिया. पटना में जिस दिन महागठबंधन टूटा और भारी राजनीतिक गहमागहमी थी, उसके अगले ही दिन सीबीआई अदालत में मामले की सुनवाई की तिथि निर्धारित थी. इसलिए लालू प्रसाद पटना की राजनीतिक गहमागहमी को छोड़ कर देर रात अपने चुनावी रथ से रांची के लिए रवाना हो गए. दूसरे दिन सीबीआई अदालत में लालू हाजिर हुए, तो उनके चेहरे पर झल्लाहट साफ नजर आ रही थी. लालू

प्रसाद ने उसी झल्लाहट में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में यह कहा कि इस न्यायालय से हमें न्याय की उम्मीद नहीं है. लालू ने अदालत बदलने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि मैंने अदालत बदलने के लिए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया है. मैं अनुरोध करूंगा कि उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद ही इस अदालत में मामले की सुनवाई की जाय. लेकिन सीबीआई अदालत ने लालू की इस दलील को सीरे से खारिज कर दिया. सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने कहा कि गवाह अपना बयान दर्ज कराने को अदालत आए हैं, तो बयान दर्ज किया जाएगा.

गवाही के दौरान मामले ने एक अलग तूल पकड़ लिया, जब सुनील कुमार निर्धारित तिथि से पहले ही गवाही देने पहुंच गए. लालू प्रसाद के बचाव में पटना के तत्कालीन वरीय आरक्षी अधीक्षक सुनील कुमार की गवाही की तिथि 10 अगस्त निर्धारित थी. लेकिन वे 3 अगस्त को ही गवाह देने पहुंच गए. जब उनका बयान दर्ज हो रहा था, तभी विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह को इस बारे में पता चल गया. इस बात पर विशेष न्यायाधीश ने उन्हें फटकार लगाते हुए गवाही वाले कागजात को फाड़ डाला. लालू प्रसाद ने अदालत के बाहर इसे मुद्दा बनाना चाहा, लेकिन मीडिया का समर्थन नहीं मिलने के कारण यह मुद्दा नहीं उछल पाया. सुनील को भी अब ये डर सताने लगा है कि कहीं वे भी चारा घोटाले में न फंस जाएं.

यूपीए के शासनकाल में जब लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाला मामले में केस दर्ज हुआ, तो उस समय चारा घोटाले से जुड़े सभी मामलों को एक ही मानकर केस दायर किया गया था.लेकिन उच्चतम न्यायालय के फैसले ने लालू प्रसाद को नई परेशानी में डाल दिया. दरअसल, उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी कि चारा घोटाले के सभी मामलों की अलग-अलग सुनवाई हो. इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने सभी मामलों की अलग-अलग सुनवाई का आदेश दे दिया. ■

feedback@chauthiduniya.com

साज़िश के तहत मुझे फंसाया गया : लालू

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद भाजपा नेताओं पर खुलकर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि मोदी एंड पार्टी ने मेरी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए सीबीआई को अपना हथियार बना लिया है और साजिश के तहत मुझे फंसाने का काम किया जा रहा है. 'अगर मेरे पास चारा घोटाले का पैसा रहता, तो सीबीआई उसे जरूर बरामद करती. चारा घोटालेबाजों से मैं मिला भी नहीं, तो मेरे पास अवैध धन कहां से आएगा. अगर मेरे पास अवैध धन रहता, तो वो इतनी छापेमारी में सीबीआई को जरूर मिलता.' लालू प्रसाद कहते हैं, 'मेरा दोष सिर्फ इतना है कि मैंने पशुपालन विभाग के एक अधिकारी को सेवा विस्तार दिवा था, वह भी पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के कहने पर. जगन्नाथ मिश्रा ने अनुशंसा करते हुए लिखा था कि अगर इस अधिकारी को सेवा विस्तार नहीं दिया गया, तो पशुपालन विभाग डूब जाएगा, पूरा काम ठप्प हो जाएगा. इसे देखते हुए एक साल के लिए सेवा विस्तार दिवा गया. यही मेरा दोष है, लेकिन मुझे इस तरह फंसा दिया गया है कि मैं कितना बड़ा अपराधी हूं.'

लालू प्रसाद पर सीबीआई ने डोरंडा कोषागार से साढ़े तीन करोड़, चाईबासा कोषागार से साढ़े पैंतीस करोड़, देवघर कोषागार से 90 लाख एवं 2 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर रखी है. इन मामलों में लालू प्रसाद पर सीबीआई ने आरोप तय करते हुए यह कहा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद ने घोटालेबाजों को छूट दे रखी थी और उनकी जानकारी में ये अवैध निकासी हुई. सीबीआई का कहना है कि लालू प्रसाद ने चारा घोटाले के किंग पिन माने जाने वाले श्यामबिहारी सिन्हा के साथ मिल कर एक हजार करोड़ से भी अधिक का घोटाला किया. लेकिन लालू इन तथ्यों से भी पूरी तरह से इंकार करते हैं. वे कहते हैं, 'जैसे ही मुझे पशुपालन विभाग में अवैध निकासी होने की जानकारी मिली, मैंने तत्कालीन मुख्य सचिव बी.एस. दुबे को निर्देश दिया कि वे पूरे तथ्यों से अवगत कराएं. इस मामले में निगरानी की भी जांच कराई गई, पर निगरानी ने कहा कि जांच से यह पता चलता है कि इस तरह की कोई अवैध निकासी नहीं हुई है. उसके बाद इस जांच की फाईल बंद की गई. इस मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा भी मैंने की थी, लेकिन सीबीआई ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया. अगर मैं इस मामले में आरोपी रहता, तो मैं जांच का आदेश क्यों देता.' एक राजनीतिक साजिश के तहत भाजपाईयों ने मुझे ही फंसा दिया. अब देखना है कि इस मामले में अदालत का फैसला क्या आता है. वैसे चारा घोटाले में आरोपी होने के कारण लालू यादव पर चुनाव लड़ने की पाबंदी है. ■

ज़िद जहां जीतने की

सिवान के गांव से निकलकर गुजरात में लहराया सफलता का झंडा

मीरा पटेल

सिवान जिले के रिसौरा गांव के दिव्यांग निर्मल और उनकी दिव्यांग पत्नी ज्योति ने गुजरात में कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके मुरीद बन गए. उन्होंने बुद्धिमता और उद्यमिता के शानदार मिश्रण से अपनी शारीरिक दुर्बलता पर विजय पाई.

सिवान जिले के रिसौरा गांव में शिक्षक राजाराम सिंह के घर 1980 में निर्मल का जन्म हुआ. जब वे तीन साल के थे, तभी पोलियो के शिकार हो गए. 1996 में निर्मल ने महमदा हाई स्कूल से दसवीं की परीक्षा पास की. आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें पटना भेज दिया गया. इंटर के बाद निर्मल ने हैदराबाद के आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय से बीटेक (कृषि विज्ञान) करने का फैसला किया. निर्मल को राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति (नेशनल टैलेंट

स्कॉलरशिप) के रूप में हर महीने भारत सरकार की ओर से 800 रुपए मिलने लगे. पहले ही प्रयास में उन्हें आईआईएम अहमदाबाद में प्रवेश मिल गया.

एक घटना से मिल गया जवाब

आईआईएम में दूसरे साल की पढ़ाई चल रही थी. एक दिन वे डिनर के लिए साथियों के साथ कैंपस से बाहर निकले. ऑटोचालक ने रेस्तरां पहुंचाने के लिए 25 रुपए मांगे. लेकिन वापसी में दूसरे ऑटोचालक ने आईआईएम गेट तक पहुंचाने के लिए 35 रुपए ले लिए. निर्मल ने जानना चाहा कि जब रास्ता वही, दूरी वही, मीटर भी वही, तब वापसी में भाड़ा ज्यादा कैसे हो गया. इस पर ऑटो वाले ने उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी. निर्मल ने सोचा कि देश भर में कई लोग ऑटोचालकों की बेईमानी और बदतमीजी का शिकार होते हैं. फिर ख्याल आया कि क्यों न ऑटोचालकों की व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्हें संगठित कर प्रशिक्षण दिया जाए.

इस फैसले को अमलीजामा पहनाते हुए उन्होंने 15 ऑटोचालकों को इकट्ठा किया. उनको योजना का हिस्सा बनने के लिए इंसेंटिव दिए. उनके बैंक में खाते खुलवाए, जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा भी करवाया. सवारियों से अच्छा व्यवहार करने के लिए उनको विशेष प्रशिक्षण दिया. ग्राहकों के लिए ऑटो में अखबार और पत्रिकाएं उपलब्ध करवाईं. मोबाइल फोन चार्जर लगवाया. कूड़ादान रखा. रेडियो की सुविधा भी दी.

इस परियोजना को प्रायोजकों से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. अखबार और पत्रिकाओं के मालिकों व विज्ञापनदाताओं ने अन्य ऑटोचालकों को भी इस मुहिम से जोड़ने के सुझाव दिए. फिर 100 ऑटोचालकों को इस मुहिम से जोड़ा गया. कई कंपनियों ने भी विज्ञापन के लिए जी-ऑटो का सहारा लिया. इसके बाद उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने जी-ऑटो प्रोजेक्ट का विधिवत उद्घाटन करवाने का फैसला लिया. मोदी जी परियोजना से प्रभावित होकर उद्घाटन करने के लिए राजी हो गए. सीएम के हाथों जी-ऑटो की विधिवत शुरुआत के बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

देखते-देखते ऑटो की संख्या बढ़कर 22 हजार हो गई. अब यह सिर्फ अहमदाबाद तक सीमित नहीं है. गांधीनगर, राजकोट, सूरत, गुड़गांव और दिल्ली में भी इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया. निर्मल ने 2009 में सिवान के सारीपट्टी गांव में दिव्यांग ज्योति से शादी की. ज्योति ने केमिस्ट्री में एमएससी की है. अब वे भी इस परियोजना को सफल बनाने में जी-जान से जुटी हैं. ■

ग़रीबी के कारण नहीं किया था एमबीए आज सैकड़ों एमबीए को दिया रोज़गार

कहते हैं न कि मान लो तो हार, ठान लो तो जीत. सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के हीरमकरिया गांव के एक युवा ने कुछ करने की ठानी, तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. जिस शख्स के पास कभी ट्रेन से मुम्बई जाने के लिए रुपए नहीं थे, जिसका एमबीए का सपना गरीबी के कारण अधूरा रह गया हो, आज उसी का कारोबार दुबई, बहरीन, कतर, सऊदी से लेकर भारत तक फैला है. अजय सिंह के जीवन की कहानी किसी फिल्म की पटकथा सरीखी है. साधारण किसान परिवार में जन्मे अजय सिंह ने सिवान के डीएवी कॉलेज से 1992 में ग्रेजुएशन किया. वे एमबीए करना चाहते थे, लेकिन पैसों की तंगी आड़े आने लगी. फिर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी शुरू कर दी. एक बार रेलवे की परीक्षा देने मुम्बई पहुंचे, तो एक मित्र के यहां ठहरना हुआ. परीक्षा देने के बाद लौटते समय उस मित्र ने कहा कि कहां घर जाओगे, तुम भी यहीं कोई जॉब कर लो. प्रस्ताव अच्छा था, सो मान लिया. उसी मित्र ने रीयल इस्टेट की एक कंपनी में ढाई हजार प्रतिमाह पर नौकरी दिलवा दी. दो साल में उनकी सैलरी ढाई हजार से बढ़कर पांच हजार रुपए हो गई. इसी बीच एक घटनाक्रम ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी. अजय ने बताया कि उनके गांव के एक अंकल विदेश में नौकरी करने के लिए एक एजेंसी से मिलने यहां आए हुए थे. वे उनके यहां ही ठहरे थे. उनको एजेंसी तक पहुंचाने गया, तो वहां दुबई के एक उद्योगपति से मुलाकात हो गई. वे उनकी बातचीत से इतने प्रभावित हुए कि दुबई चलने का न्योता दे दिया. हालांकि वे जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके द्वारा आने-जाने का इंतजाम करने और बार-बार कहने के बाद वे राजी हो गए. वहां उन्होंने अपनी रीयल इस्टेट कंपनी में सुपरवाइजर का काम दिया. तीन साल बाद कंपनी के मैकेनिकल डिवीजन का प्रमुख बना दिया गया. वे बताते हैं, कुछ वर्षों तक काम करने के बाद मैंने सोचा कि अब अपना काम शुरू किया जाए. हालांकि इसमें रिस्क था, पर सफलता के लिए यह कदम उठाना जरूरी था. उन्होंने रीयल इस्टेट की एक कंपनी बनाई. बिजनेस अच्छा हुआ. बाद में इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंपनी बनाकर काम शुरू कर दिया. आयात-निर्यात का भी काम करने लगे. रेडीमेड गार्मेंट के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया. सभी में सफलता मिलती चली गई. आज दुबई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब और भारत के नोएडा में उनका काम चल रहा है. करीब पांच सौ करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर है. अभी जिस हिसाब से कारोबार बढ़ रहा है, उम्मीद है जल्द यह हजार करोड़ तक पहुंच जाएगा. प्रख्यात पार्श्वगायक कुमार शानू के हाथों उन्हें गत वर्ष दुबई में आईबीएफए द्वारा बेस्ट पर्सनालिटी ऑफ दुबई के अवॉर्ड से भी नवाजा गया. ■

हमारा भारत अच्छा है, नया भारत कैसा होगा

कमल मोरारका

www.kamalmorarka.com

लोकतंत्र में बातचीत ही समस्या के समाधान का एकमात्र माध्यम होता है. इस बात से पूरी दुनिया सहमत है. केवल तानाशाही सरकारें ही बल से अपनी जनता को काबू में रखती हैं. बहरहाल प्रधानमंत्री ने जो बातें की हैं, वो स्वागत योग्य हैं. हमें आशा करनी चाहिए कि ये बातें उन्होंने केवल कहने के लिए नहीं कही होंगी, बल्कि इसमें उनकी भूल की स्वीकारोक्ति भी होगी, क्योंकि उन्हें अपनी बातों पर अमल भी करना पड़ेगा.

प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त का भाषण लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा. यह फीका और मंद भाषण था और अपेक्षाकृत छोटा (45 मिनट) भी था. प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर समस्या का समाधान न तो गाली से होगा और न ही गोली से, बल्कि कश्मीरियों को गले लगाने से होगा. यह बहुत ही विचित्र स्थिति है. उनकी बातें हर विवेकशील व्यक्ति के लिए शहद की तरह मीठी थीं. पिछले तीन वर्षों से वे धमकाते रहे हैं कि कश्मीर समस्या का समाधान बुलेट, सेना, अर्धसैनिक बलों या पुलिस द्वारा किया जाएगा. आखिर इस हृदय परिवर्तन की वजह क्या है?

लोकतंत्र में बातचीत ही समस्या के समाधान का एकमात्र माध्यम होता है. इस बात से पूरी दुनिया सहमत है. केवल तानाशाही सरकारें ही बल से अपनी जनता को काबू में रखती हैं. बहरहाल प्रधानमंत्री ने जो बातें की हैं, वो स्वागत योग्य हैं. हमें आशा करनी चाहिए कि ये बातें उन्होंने केवल कहने के लिए नहीं कही होंगी, बल्कि इसमें उनकी भूल की स्वीकारोक्ति भी होगी, क्योंकि उन्हें अपनी बातों पर अमल भी करना पड़ेगा.

यह कहना बिल्कुल सही है (जैसा कि उन्होंने अपने लालकिला के भाषण में कहा) कि आस्था के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. लेकिन सच्चाई ये है कि हिन्दू कभी गाय के नाम पर, कभी बीफ के नाम पर या किसी अन्य बहाने से देश के हर हिस्से में मुसलमानों को मार रहे हैं. अपनी बातों पर अमल करना असल चीज़ है. यदि प्रधानमंत्री जो कहते हैं, उसमें विश्वास भी रखते हैं तो उन्हें समान विचारधारा के संगठनों, जैसे बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद्, आरएसएस आदि पर नकेल कसनी चाहिए. उन्हें कहना चाहिए कि हम सत्ता में हैं, हमें देश चलाना है, इसलिए हमें समझदार, शांतिपूर्ण और ज़िम्मेदार राष्ट्र की तरह व्यवहार करना चाहिए. चाहे आपकी जो भी भावनाएं हों, उनका इज़हार कानून की परिधि में ही करना चाहिए. यदि आपको लगता है कि कोई कानून के खिलाफ बीफ बेच रहा है, तो उसे पकड़ने के लिए पुलिस है. आप किसी के खिलाफ कार्रवाई कर उसे मारना शुरू नहीं कर सकते हैं. यदि ऐसा होता रहा, तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा. लोकतंत्र शांतिपूर्ण सामाजिक परिवर्तन के लिए जनता और सरकार के बीच एक समझौता होता है. इसका मकसद सामाजिक असमानता को दूर करना और गरीबों की देखभाल करना है, ताकि अमीर उनके खिलाफ मनमानी न कर सकें.

बहरहाल, प्रधानमंत्री का भाषण बहुत नर्म था. पिछले भाषणों में जो जोश था, वो इस बार नहीं दिखा. यह एक अच्छी और स्वागत योग्य बात है. लेकिन उनकी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह उनकी इस शैली का अनुसरण करते नहीं दिख रहे हैं. वे एक के बाद दूसरे राज्य का लगातार भ्रमण कर रहे हैं. वहां वे जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वह उचित भाषा नहीं है. पिछले दिनों मैंने एक ट्विट देखा, जिसकी पृष्ठभूमि ये थी कि बेंगलुरू में अमित शाह ने एक बयान दिया था कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार पर जीरो–टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी. इसके बाद किसी ने ट्विट किया कि जब आपके बगल में येदियुरप्पा खड़े हों तो इस तरह का बयान देने के लिए उच्च दर्जे की बेशर्मी की जरूरत होगी.

बहरहाल उन्हें आम लोगों की राय सुननी चाहिए. मैं येदियुरप्पा के कृत्यों के लिए अमित शाह को दोषी नहीं ठहराऊंगा, लेकिन उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की अपनी सीमाएं होती हैं. आप भ्रष्टाचार रहित समाज नहीं बना सकते. इस बात की तस्दीक इस तथ्य से भी होती है कि आप खुद ही येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर रहे हैं. लोग ऐसे झांसों में नहीं आते, वे इसकी असलियत समझते हैं. जो बात बिहार के लिए सच है, वो कर्नाटक पर भी लागू होता है. आपने लालू यादव को क्या कुछ नहीं कहा. आप येदियुरप्पा के बारे में क्या कहेंगे? यदि आप नई तरह की राजनीति चाहते हैं, तो आपको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है.

प्रधानमंत्री ने जो दूसरी बात कही, वो ये थी कि वो 2022 तक एक नया भारत बना देंगे. नए भारत का मतलब क्या है, यह मेरी समझ से बाहर है. हमारा भारत अच्छा है. हमने 70 साल में अच्छा काम किया है. 1947 से लेकर 2017 तक हमारी उपलब्धियां शानदार रही हैं. इस दौरान हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी देश ने बिना बल प्रयोग या सेना के हस्तक्षेप के हासिल किया हो. यहां सिर्फ 17 महीनों के लिए लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की गई, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था. यहां 70 वर्षों में शांतिपूर्ण ढंग से सरकारें बदली हैं. शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं. शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक बदलाव हुए हैं. ताकतवर लोगों के खिलाफ कानून बनाए गए हैं. हर एक मुश्किल दौर का सामना आसानी से किया गया है. मौजूदा सरकार के सत्ता में आने से पहले 97 प्रतिशत गांवों तक बिजली पहुंचा दी गई थी, केवल 3 प्रतिशत गांव ऐसे थे, जहां बिजली नहीं पहुंची थी. इसके बावजूद यह सरकार कह रही है कि 70 वर्षों तक लोग अंधकार में रहे. अपनी उपलब्धियों को ऊंचे स्वर में गिनाने से ये बड़ी उपलब्धियां नहीं बन जाती हैं. ऊंचे स्वर में बात करने या कटु शब्दों के इस्तेमाल से आपका पक्ष बहुत मज़बूत नहीं होता है.

अब गोरखपुर त्रासदी की बात करते हैं. हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं. मुद्दा यह नहीं है कि यह त्रासदी क्यों हुई, लेकिन मुद्दा यह है कि इस मामले में क्या किया गया. इस प्रधानमंत्री को अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी. उन्होंने एक ट्विट करना भी गवारा नहीं किया. वे तुर्की, इटली आदि देशों में हुई मौत की घटनाओं पर ट्विट करते हैं, लेकिन यहां उन्होंने चुप्पी साधे रखी. अमित शाह सार्वजनिक तौर पर ये कहने का साहस जुटा लेते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. सवाल ये है कि पहली बार नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि बार–बार इन घटनाओं की पुनरावृत्ति होते रहनी चाहिए! मैं समझता हूं कि भाजपा में सत्ता का अहंकार पैदा हो गया है. यह खुद उनके लिए ठीक नहीं है. लोग इससे प्रभावित नहीं होते. अहंकारी नेता आते हैं और चले जाते हैं. भारत मुग़लों और अंग्रेजों के शासनकाल से निकल गया, यह मौजूदा हुकूमत के दौर से भी निकल जाएगा. लेकिन सवाल ये है कि यदि आप सत्ता में हैं और लम्बे समय तक सत्ता में रहना चाहते हैं तो आपको अपना अंदाज दुरुस्त करना होगा. समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने की कोशिश करनी होगी और छोटी–मोटी टिप्पणियों को नजरअंदाज करना होगा. आखिरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी उसे कहते हैं, जिसमें आप वो बातें भी सुनें, जिन्हें सुनना पसंद नहीं करते हैं. यदि लोग आप की तारीफ करते हैं तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है.

निवर्तमान उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक बहुत ही हल्का–फुल्का बयान दिया, जिस पर भी वे आहत हो गए. उन्होंने कहा था कि मुसलमानों में एक तरह की बेचैनी का माहौल है. उन्होंने यह बयान बेंगलुरू में दिया था. इससे पहले भी उन्होंने राज्य सभा में कहा था कि यदि विरोधी पक्ष की बातें नहीं सुनी जाएंगी या असहमति को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो लोकतंत्र तानाशाही का रूप धारण कर लेगी. इसमें कोई नई बात नहीं है. भाजपा इसको लेकर आहत क्यों है? हामिद अंसारी देश के बेहतरीन उपराष्ट्रपतियों में से एक थे. उन्होंने अत्यंत गरिमा के साथ अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन किया. उन्होंने बेहतरीन ढंग से राज्यसभा का संचालन किया. नए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का अनादर किए बिना मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्हें हामिद अंसारी का स्थान लेने में समय लगेगा. दूसरे अन्य लोगों की तरह वेंकैया नायडू की भी राजनैतिक पृष्ठभूमि रही है. वे भाजपा में रहे हैं. आखिर किसी न किसी को उपराष्ट्रपति बनना होता है. अब वे गैर–दलीय व्यक्ति हैं, इसके बावजूद वे निवर्तमान उपराष्ट्रपति के बयान का खंडन करते हैं, यह उचित नहीं था. अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद हामिद अंसरी ने ये बात कही थी. अब आपने उनका स्थान लिया है. आप अब भी राजनीति करने में दिलचस्पी रखते हैं. यह भाजपा है. मैं इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा. कांग्रेस को भी लोकतंत्र की खूबियों को समझने में लंबा समय लगा था, हालांकि जवाहरलाल नेहरू जैसी कद्दावर शख्सियत उनके पास मौजूद थी. यहां सभी पिग्मी हैं. अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी जैसी कद्दावर शख्सियतें या तो बीमार हैं यह फिर उन्हें दरकिनार कर दिया गया है. जो बाकी बचे लोग हैं, उनसे यही आशा की जा सकती है, जो बहुत ही दुखद है. आप पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में हैं. अपने सहयोगियों के साथ लोक सभा की 445 में से 330 सीटें आपके पास हैं. आपसे निवेदन है कि आप अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरिए. अपने स्वर को धीमा रखिए. प्रधानमंत्री के भाषण की मैं एक मामले में तारीफ ज़रूर करूंगा कि उनका स्वर बहुत ही सौम्य और सुलझा हुआ था. उनके भाषण से जम्मू और कश्मीर के लोगों को नई उम्मीद मिली है. मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो बातें की हैं, उसका पालन किया जाएगा.

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार युद्धोन्मादी (हॉकिश) प्रवृत्ति के हैं. गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर के आधे जिले आतंकवाद से प्रभावित हैं और हम इसका स्थायी समाधान तलाश रहे हैं. स्थायी समाधान से उनका आशय क्या है, यह समझ से परे है. प्रधानमंत्री को अपनी टीम को साथ लेकर ऐसा माहौल बनाना चाहिए, ताकि सकारात्मक बातचीत शुरू की जा सके और समस्या के समाधान की ओर बढ़ा जा सके. उनकी पार्टी के सदस्य यशवंत सिन्हा पिछले साल कश्मीर गए थे. वापस आने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया. प्रधानमंत्री अपने दल के लोगों से भी नहीं मिलना चाहते, जो उनकी मदद करना चाहते हैं. लाल किला से आप कहते हैं कि मसले का हल गाली और गोली से नहीं, बल्कि कश्मीरियों को गले लगाने से होगा. बिलकुल यही चीज़ यशवंत सिन्हा करना चाह रहे थे. दरअसल प्रधानमंत्री जो कहते हैं और जो पार्टी चाहती है और जो आरएसएस करता है, उनमें बड़ा फासला है. जितनी जल्द इस फासले को कम किया जाए, उतना ही बेहतर होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

आर्टिकल 35-ए पर कश्मीरी दल एक हैं

शुजात बुखारी

कश्मीर में राजनीतिक अनिश्चितता के पिछले 27 वर्षों में समय का चक्र कई बार बदला है. 1947 के राजनीतिक उथल–पुथल और भारत विभाजन से उत्पन्न होने वाले राजनीतिक मुद्दों पर एक बड़ा विचार और प्रभावी चर्चा हुई है. बिना संदेह, जम्मू और कश्मीर में स्वतंत्रता के लिए जारी संघर्ष, भारत की आजादी की लड़ाई से अलग था, लेकिन जिस तरह से ये विभाजन के साथ उलझा हुआ है वो पिछले 70 वर्षों से एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है. जब 1987 में कश्मीर के युवाओं ने हथियार उठाए, तब उन्होंने राज्य का राजनीतिक रंग बदल दिया. यद्यपि जम्मू और लद्दाख इस कश्मीरी मांग से काफी हद तक बचे हुए थे, लेकिन इस मुद्दे को वो ठंडा नहीं कर सके. प्रदर्शन का आधार आजादी की मांग रही, जो पहले बन्दूक और बाद में पत्थर के जरिए व्यक्त हुआ.

दिल्ली की कई सरकारों ने उनके साथ बैकचैनल और आधिकारिक वार्ताएं भी कीं, जो आजादी मांग रहे हैं. इसमें राइट विंग भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी सहित कई सरकारें शामिल हैं, लेकिन कुछ भी मूर्त रूप से सामने नहीं आया. लेकिन बैकचैनल और आधिकारिक वार्ता की कोशिशें दिल्ली व इस्लामाबाद और दिल्ली व श्रीनगर के बीच समानान्तर चलने वाली प्रक्रिया बनी रही. इसे कंफिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पर देखा गया. इससे दोनों देशों के बीच व्यापार भी चल रहा है. अलगाववादी या विरोधी नेता, जो आजादी की मांग के अगुआ रहे हैं, स्वतंत्र विचार व निर्णय लेने में विफल रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.

हालांकि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पिछले तीन सालों में, सरकार द्वारा यह नकारे जाने से कि ज़म्मू और कश्मीर एक राजनीतिक मुद्दा है, न केवल भारत के भीतर स्थिति बदली है, बल्कि अलगाववादियों के बीच भी स्थिति बदली है, जो पहले से ही इस मुद्दे को अप्रासंगिक मानते हैं.

भाजपा सरकार ने उन सभी चर्चाओं को हटा दिया है, जो जम्मू–कश्मीर को एक राजनीतिक मुद्दा बनाती है. राज्य का पूर्ण एकीकरण और धारा 370 को रद्द करना (जो भारत के संविधान के दायरे में राज्य को स्पेशल स्टेटस देता है) भाजपा का राजनीतिक एजेंडा रहा है. हालांकि, राज्य में सत्ता में शामिल होने की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए भाजपा ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ एजेंडा ऑफ एलायंस (एओए) किया और इस संवैधानिक स्थिति की सुरक्षा का वादा किया.

एओए के हिस्से के रूप में ये वादे शामिल हुए, फिर भी भाजपा ने धारा 370 के साथ छेड़छाड़ करने के लिए

नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पिछले तीन सालों में, सरकार द्वारा यह नकारे जाने से कि ज़म्मू और कश्मीर एक राजनीतिक मुद्दा है, न केवल भारत के भीतर स्थिति बदली है, बल्कि अलगाववादियों के बीच भी स्थिति बदली है, जो पहले से ही इस मुद्दे को अप्रासंगिक मानते हैं. भाजपा सरकार ने उन सभी चर्चाओं को हटा दिया है, जो जम्मू–कश्मीर को एक राजनीतिक मुद्दा बनाती है.

न्यायपालिका के माध्यम से एक युद्ध शुरू कर दिया है. भाजपा के वैचारिक साथी आरएसएस समर्थित एक एनजीओ वी द पीपुल ने उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 35–ए को खत्म करने के लिए एक याचिका दायर की है. 14 मई, 1954 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा जारी संवैधानिक (जम्मू–कश्मीर के लिए लागू) आदेश के जरिए जम्मू–कश्मीर में ये आर्टिकल लागू किया गया था. यह विशेष रूप से राज्य के सब्जेक्ट कानूनों (नागरिक) को संरक्षण देने के लिए तैयार किया गया था, जो महाराजा के शासन के तहत निर्धारित किए गए थे और 1927 और 1932 में अधिसूचित किए गए थे. इसके मुताबिक केवल राज्य के नागरिक ही राज्य में भूमि के मालिक होने के हकदार हैं. यहां पर यह शोर मचाया जा रहा है कि यह जम्मू और कश्मीर को एक्सक्लुसिव बना देता है. इसे भारत के बाकी हिस्सों के लोगों के लिए खुला होना चाहिए.

हालांकि कानूनी लड़ाई चल रही है और अदालत में राज्य अकेले ही रह गया है. ऐसे में विशेषज्ञ कुछ उचित प्रश्न उठा रहे हैं. एक यह कि अनुच्छेद 35–ए खत्म हो, तो फिर राष्ट्रपति के सभी 41 आदेश कानूनी जांच के अधीन होंगे, क्योंकि ये सभी ऑर्डर 1954 के जरिए संशोधित किए गए थे. इसे देखते हुए, बाद के ऑर्डर से ही राज्य में (जम्मू–कश्मीर) संघ सूची की 97 एंट्रीज में से 94 और भारतीय संविधान के 260 आर्टिकल्स को लागू किया गया था. समय–समय पर इन आदेशों का उपयोग राज्य की विशेष स्थिति या स्वायत्तता को नष्ट करने के लिए भी किया गया है.

यह ज्ञात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय क्या होगा, लेकिन यह आशंका है कि यह प्रतिकूल हो सकती है, भले ही राज्य सरकार इसका बचाव कर रही है. मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पहले से चेतावनी दे चुकी हैं. दिल्ली में एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि यदि अनुच्छेद 35–ए को खत्म किया जाता है, तो कश्मीर में भारतीय ध्वज को कोई नहीं लहराएगा. लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई (एम) और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों समेत विपक्ष इसका बचाव करने के लिए एक जगह इकट्ठे हुए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने 7 अगस्त को विपक्ष की बैठक की अध्यक्षता की और परिणाम भुगतने की चेतावनी दी. अब्दुल्ला ने मेरे साथ एक साक्षात्कार में कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 35–ए को स्क्रैप करने का निर्णय करता है, तो नई दिल्ली को परिणाम का सामना करना होगा और युद्धक्षेत्र में उतरने के लिए तैयार रहना होगा. हम जेल जाएंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं. उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए. इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अब्दुल्ला के निवास पर महबूबा गईं. इससे इस मुद्दे पर राजनीतिक तस्वीर बदल रही है. विपक्षी दल ने इस पर सरकार को समर्थन का आश्वासन दिया है. इससे यह लड़ाई सभी पार्टी बनाम भाजपा के बीच होने की संभावना है. जैसाकि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को उन खतरों के बारे में आगाह किया है, जो इस आर्टिकल को खत्म करने से सामने आ सकते हैं. ऐसे में देखना होगा कि भारत सरकार 26 अगस्त को अपना रुख बदलती है या नहीं, जब मामले की सुनवाई के लिए इसे सूचीबद्ध किया जाएगा.

सैयद अली गिलानी, मीरवाइज फारूक और यासीन मलिक का संयुक्त नेतृत्व भी इस कोरस में शामिल हो गया है और हड़ताल की मांग की है. यह पहली बार है कि वैचारिक रूप से विभाजित लोग एक जगह पर इकट्ठे हैं. चिंता यह है कि अनुच्छेद 35–ए को हटाने से भाजपा के पूर्ण एकीकरण का सपना पूरा होगा, जो अंततः राज्य में गैर–जम्मू और कश्मीर निवासियों के लिए दरवाजा खोल देगा. क्या भारत–विरोधी और भारत–समर्थक एक साथ प्रदर्शन करेंगे, यह ज्ञात नहीं है, लेकिन इस मामले ने न केवल दिल्ली और श्रीनगर के बीच टकराव के दरवाजे खोल दिए हैं, बल्कि एक संभावित विद्रोह का भी रास्ता खोल दिया है.

नेकां की अध्यक्षता में मुख्यधारा कैंप जम्मू और लद्दाख को इस विशेष स्थिति की रक्षा की लड़ाई में शामिल करने की सोच रही है, हालांकि जम्मू को भाजपा और आरएसएस के मौजूदा प्रभाव के कारण ध्रुवीकृत कर दिया गया है. लेकिन वे उन्हें संदेश देना चाहते हैं कि अनुच्छेद हटाना उनके लिए समान रूप से हानिकारक है. महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने राज्य नागरिक कानून लागू किया था, जम्मू से थे और यह पंजाबी प्रभाव को शामिल करने के लिए किया था. सीपीआई (एम) नेता एम वाई तारिगामी ने कहा कि हम उन्हें याद दिलाएंगे कि राज्य की विशिष्ट प्रकृति, राज्य की पवित्रता क्या है और क्यों उसका पालन करना चाहिए. यद्यपि पिछले साल जम्मू के कैमिस्ट द्वारा किया गया हड़ताल महत्वपूर्ण था. उन्होंने एक गैर कश्मीरी फर्म को अनुबंध का आवंटन करने वाले एक सरकारी आदेश का विरोध किया था और इसे आर्टिकल 370 पर हमला कहा था.

अब तक राजनीतिक सर्कल विशेष दर्जा के मुद्दे पर केंद्रित है. इसने आजादी के मुद्दे को अभी पीछे रख दिया है. तो क्या भाजपा ने बदल कर कुछ हासिल किया है या उसने कश्मीर में राजनीतिक एकता के लिए जगह दे दी है? स्पेशल स्टेटस के मुद्दे में इतनी ताकत है कि वह राजनीतिक विद्रोह करवा दे. अगर दिल्ली लोगों को आजादी नहीं दे सकता है, तो वह उन्हें स्वायत्तता से वंचित नहीं कर सकती है.■

–लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के भाषण ने मेरी आंखें खोल दी

इस बार 15 अगस्त ने हमें बहुत सारे नए ज्ञान दिए. एक ज्ञान तो ये दिया कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भाषा, बिल्कुल कौमा और फुलस्टॉप के साथ एक है. शैली भी एक है. दोनों ने मिलकर जो बातें देश के सामने रखीं, उसने मेरे जैसे लोगों को बहुत चमत्कृत कर दिया. मेक इन इंडिया, जिससे नया हिन्दुस्तान बनता, सफल हो गई है. मेक इन इंडिया अब न्यू इंडिया बन गया है, मतलब नया हिन्दुस्तान बन रहा है. अब नया इंडिया नाम, एक अखबार नया इंडिया नाम से निकलता है, तो उसके संपादक बहुत खुश होंगे कि उनका नाम प्रधानमंत्री मोदी को बहुत पसंद आया.

पर मुझे जो ज्ञान मिला, वो ये है कि हम लोगों को नौकरियां दे चुके हैं, देश का नौजवान खुश है, किसान का 90 प्रतिशत से ज्यादा कर्ज माफ हो चुका है, बहुत सारी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने नए नाम से शुरू की हैं. उन योजनाओं का पहले से चल रही योजनाओं से कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने सारी पुरानी योजनाओं का नाम बदलकर नई योजनाओं का चेहरा बना दिया है, वो गलत कहते हैं. मोदी जी ने बिल्कुल नई योजनाएं शुरू की हैं और देश में खुशहाली हमारे दरवाजे पर खड़ी है. इसका मतलब है कि सिर्फ दरवाजा खोलने की देर है, खुशहाली की आंधी हमारे जीवन में आने वाली है. ये सब जानकर हमें इतना अचम्भा हुआ और अच्छा लगा कि हमें अपने आस-पास उन्हें देखने की जरूरत नहीं है. हमारे कानों में बस आवाज आनी चाहिए कि हिन्दुस्तान बदल रहा है. हिन्दुस्तान लगभग बदल गया है. इतना ही नहीं, हिन्दुस्तान महाशक्ति बन गया है. सारी दुनिया में घूमकर बाहर का इन्वेस्टमेंट हिन्दुस्तान में लाने की बात करते थे, हमारे प्रधान सेवक जी. वो इन्वेस्टमेंट अवश्य आ गया होगा, लेकिन उसका कोई आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध नहीं है.

लोग खामखाह मूर्खता की बात करते हैं कि नोटबंदी से देश की प्रगति नहीं हुई, बल्कि इस नोटबंदी के प्रचार में कितने हजारों-करोड़ रुपए खर्च हो गए. उसका भी कोई मतलब नहीं है. रिजर्व बैंक गणित नहीं लगा पा रहा है कि कितने रुपए उसके पास आए, इसके बावजूद कि लोग मांग कर रहे हैं, कम से कम ये तो बताओ कि नोटबंदी की वजह से जो नोट बदले गए, कितने आए. उन सवालों का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कालाधन समाप्त हो चुका है. इसका मतलब आजादी से लेकर अब तक कालेधन को लेकर जितने भी सवाल खड़े हो रहे थे, वो बेवकूफी के सवाल थे. क्योंकि कितना कालाधन आया, कम से कम यही सरकार को पता नहीं है. कभी दो लाख करोड़ कहते हैं, कभी तीन लाख करोड़ कहते हैं. वो कालेधन का हिसाब क्या है? अगर प्रधान सेवक जी की अभी की बात मानें तो हम कोई भी रकम कह सकते हैं कि ये कालाधन है. कालाधन अब स्विस बैंकों या पनामा या डिफरेंट आइलैंड्स में, दुनिया के जो टैक्स हैवन देश माने जाते हैं, मॉरीशस में नहीं है. आतंकियों को तो कोई फंडिंग हो ही नहीं रही है और वो फंडिंग बंद हो गई. आतंकवाद के ऊपर कंट्रोल हुआ है, क्योंकि कश्मीर में पत्थरबाजी कम हुई है. हमने कहा है कि ये हमारी नोटबंदी की वजह से हुआ है, क्योंकि अब उनको रुपया नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए अब कश्मीर में नौजवान पत्थर नहीं चला रहे हैं. इतनी ज्ञान की बातें उन अखबारों को भी नहीं पता, जो दिन-रात आरती उतारने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके पास भी इन तर्कों को पुष्ट करने के कारण जरूर होंगे. वो कोई भी कारण हमें नहीं बता पा रहे हैं. शायद बताना नहीं चाहते. लेकिन मैं और मेरे जैसे लाखों-करोड़ों लोग अपना माथा पीट रहे हैं, अपनी बुद्धि को कोस रहे हैं कि हमें ये सब क्यों नहीं दिखाई दिया और नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब हमारा आईक्यू गड़बड़ है. हमारी समझ गड़बड़ है. हमारी बुद्धिमत्ता को कहीं जंग लग गई है.

मोदी जी ने बिल्कुल नई योजनाएं शुरू की हैं और देश में खुशहाली हमारे दरवाजे पर खड़ी है. इसका मतलब है कि सिर्फ दरवाजा खोलने की देर है, खुशहाली की आंधी हमारे जीवन में आने वाली है. ये सब जानकर हमें इतना अचम्भा हुआ और अच्छा लगा कि हमें अपने आस-पास उन्हें देखने की जरूरत नहीं है. हमारे कानों में बस आवाज आनी चाहिए कि हिन्दुस्तान बदल रहा है.

हमें देखना चाहिए कि 2022 में हम इस देश को नया बनता हुआ देखेंगे, नया बना हुआ देखेंगे. हर व्यक्ति को मकान मिल जाएगा, तीन साल में कितने लोगों को मकान मिले, इसका कोई आंकड़ा नहीं है. 2022 में अचानक हमारे देश के सभी बेघर लोगों को घर मिल जाएंगे. किसानों की फसल का भाव बढ़ जाएगा, उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी. कैसे होगी, ये सवाल करना आज की तारीख में बहुत गलत है. जावेद अख्तर जैसे लोगों को तो सजा होनी चाहिए, जो नया हुक्मनामा नाम की नज्म सुना रहे हैं. आप जावेद अख्तर की वो नज्म सुनिए, नया हुक्मनामा और जावेद अख्तर को हजारों गालियां दीजिए कि तुमको इस देश में होने वाली प्रगति क्यों नहीं दिखाई दे रही है. उस प्रगति के बारे में लिखो भाई. ये क्या लिख रहे हो कि हवाएं चले तो पूछ के चले, समुद्र में लहरें उठे तो कितनी उठेंगी, ये पहले अफसरों से पूछ लें. ये सब बेवकूफी और वाहियात बातें हैं. इस 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री मोदी ने और देश के महामहिम राष्ट्रपति ने जो भाषण दिए हैं, वही जीवन का अंतिम सत्य है. जिसको उस सत्य के ऊपर भरोसा नहीं है, उसे इस देश में आजादी और चैन से जीने का हक नहीं है. उसे चाहिए कि वो कूपमंडूक हो जाए. लोग कहते हैं कि अपना ज्ञान बढ़ाओ. उसे चाहिए कि वो अपने उस बेवकूफी भरे ज्ञान को, जो इन बातों को सत्य नहीं मानता है, अपने दिमाग को किसी कैदखाने में, काल कोठरी में डाल दे.

मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि मुझे आपसे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार हमें ये पता चला कि 2019 के इलेक्शन के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है. 2019 के इलेक्शन में तो जनता मौजूदा नीतियों का समर्थन ही करने जा रही है, बल्कि 450 भाजपा सांसदों को जिताने जा रही है. 412 राजीव गांधी को मिले थे, उससे ज्यादा की जीत होने वाली है. इसलिए 2019 का तो कोई सवाल है ही नहीं. सवाल 2022 का है. अगर हम 2022 में इस सरकार को नहीं देखना चाहते हैं या हम सवाल उठाते हैं तो हम उन सारे अच्छे विषयों को कूड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए. जैसे हरेक को मकान मिल जाएगा, हरेक को रोटी मिल जाएगी, किसान की आमदनी बढ़ जाएगी, ये सब चीजें 2022 में होंगी. 2022 में और क्या-क्या होगा? नई अर्थनीति आ जाएगी. हमारी विकास दर 10 को पार कर जाएगी. कोई गरीब नहीं रहेगा और रहेगा भी तो क्या हुआ? उन गरीबों की कोई हैसियत नहीं होगी. उनको किसी तरीके से दो रोटी मिल जाए, उतना ही काफी है. हमारे देश में नक्सलवाद की समस्या है, हमारे देश में जातीय तनाव हैं, हमारे देश में सांप्रदायिक तनाव हैं, इन सारे सवालों का कोई मतलब नहीं है, न ही उनको छूने की जरूरत है. हम एक नए हिन्दुस्तान, नए युग में प्रवेश कर चुके हैं. हम नए भारत को 2022 में देखना चाहते हैं. मैं इन सारे सवालों के आगे अपने को बौना पाता हूं. मैं चाहता हूं कि ऐसा ही हो. मैं अपने साथियों से, खासकर जर्नलिज्म में कुछ लोग हैं, जो अब भी अपनी कलम उठाने की कोशिश करते हैं, रवीश कुमार जैसों से कहता हूं कि अगर आसानी से जीना है, सुख से जीना है तो इन सवालों को मत उठाओ. उसे देखो, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कह रहे हैं. वो दिखाई क्यों नहीं देता तुमको?

मैंने देखा कि एबीपी न्यूज के अभिसार शर्मा गोरखपुर हादसे को लेकर थोड़ा ज्यादा ही विचलित हो उठे हैं. उनसे भी मुझे कहना है कि तुम्हारी पत्नी सरकारी नौकरी करती है और तुम एबीपी न्यूज में हो. क्या चाहते हो कि उसका कालापानी, अंडमान में तबादला हो जाए या तुम्हें एबीपी से निकाल दिया जाए. अंतरात्मा क्यों अचानक बोलने लगती है? आपके अंतरात्मा में कुछ गड़बड़ी है. उसको ठीक कीजिए, उसको थोड़ा टाइट कीजिए. बहुत ज्यादा अंतरात्मा को बोलना नहीं चाहिए, समझना चाहिए. जो हमें समझाने की कोशिश हो रही है, उसे समझना चाहिए. मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि अमित शाह कहते हैं कि ऐसे हादसे होते ही रहते हैं. इसमें परेशानी की क्या बात है? मानिए इसको कि वो सही कहते हैं. जब वो ये कहते हैं, तो उसमें ये अंतर्निहित है कि ऐसे हादसे भी होंगे और दूसरी तरह के हादसे भी होंगे. एक दिन आप गायब हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा. तो क्या हुआ? 2022 में एक नया देश बनने वाला है, जिसमें भले ही वो पांच प्रतिशत लोग हों, लेकिन उन्हें सबकुछ मिलेगा. जिनको नहीं मिलेगा, उनकी कोई हैसियत नहीं होगी. उन्हें खामोश रहने की ही सजा दी जाएगी. तो अगर हमने प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी की बातों से कोई गलत मतलब निकालने की कोशिश की हो, तो उसके लिए हम दोनों से क्षमा चाहते हैं. मैं अपने को सुधार रहा हूं. मैं 2022 में एक नए हिन्दुस्तान को वैसा ही देख रहा हूं, जैसा प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी हमें दिखाना चाहते हैं. आपको इस दिव्य ज्ञान को मूर्त रूप देने के लिए जितनी बधाई दी जाए, उतनी कम है. फिर से आप दोनों को 15 अगस्त के भाषण के लिए और देश को नई वास्तविकता से परिचित कराने के लिए बहुत धन्यवाद.■

editor@chauthiduniya.com

आज़ादी का उत्सव मनाएं या गंवाए गए मौकों पर दुख जताएं

15 अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि को उम्मीद की जो किरण पैदा हुई थी, वह आज मद्धम पड़ गई है. हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आजादी को हमारी साझी तकदीर से सामना कहा था. वहीं संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर ने नए गणराज्य को यह कहते हुए चेताया था कि अंतर्विरोधों का जीवन है, जहां नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिए बगैर राजनीतिक समानता की गारंटी दी जा रही है. महात्मा गांधी ने नोआखली में जाकर कम्युनिस्टों की भाषा में कहा, ये आजादी झूठी है.

आजादी को लेकर इस तरह के विरोधी विचार पिछले 70 साल में लगातार सुनाई देते रहे हैं. उत्सव मनाने को बहुत कुछ है. हम लोकतंत्र बने रहे और इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि करोड़ों लोग आज के 70 साल पहले के मुकाबले अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने के मामले में अधिक स्वतंत्र हैं. दूसरी तरफ यह भी एक सच है दलित सीवर साफ करते हुए मर रहे हैं, महिलाओं पर हमले हो रहे हैं और मुसलमानों को पीट-पीटकर मार दिया जा रहा है. हमने चुनाव आयोग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जैसे कई संस्थाओं को खड़ा तो किया, लेकिन देश की सेहत के लिए जरूरी कई संस्थाओं को बैठा भी दिया. हमने विविधता और सहनशीलता को बनाए रखा. इसके बावजूद हमने एक ऐसी सरकार को चुना, जो धर्मनिरपेक्षता की सरकारी नीति को खत्म करने और बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने में लगी है. तो क्या हमें आजादी का उत्सव मनाना चाहिए या फिर गंवाए गए मौकों पर भी दुख जाहिर करना चाहिए और मौजूदा चुनौतियों पर विचार करना चाहिए?

आजादी की व्याख्या के विरोधाभासों का एक सकारात्मक पहलू भी है. इसने राजनीतिक और अकादमिक बहस को जन्म दिया, जिससे सभी का ज्ञानवर्धन हुआ. इस जर्नल ने इस काम में अपनी भागीदारी निभाई. इसमें लिखने वाले लोगों की संख्या और उनका फलक व्यापक है. एक तरह से सामाजिक विज्ञान और लोकनीति को लेकर विमर्श और शोध बढ़ा है. इसके बावजूद अकादमिक क्षेत्र और लोकनीति व राजनीति में दूरी बढ़ी है. नीतियों के निर्धारण में अकादमिक क्षेत्रों की नहीं सुनी जा रही है और सरकार में शामिल लोगों को अकादमिक क्षेत्रों से कोई लेना-देना नहीं है.

आजादी के बाद के दशकों में सामाजिक विज्ञान से जुड़े जानकार राष्ट्र निर्माण की चुनौती से जूझ रहे थे. इसलिए यह कोई संयोग नहीं है कि संसाधनों की कमी के बावजूद सामाजिक विज्ञान भारत में बढ़ा. भारतीय विश्वविद्यालयों ने वैश्विक स्तर की सोच और प्रतिभाओं का सृजन किया. यह भी कोई संयोग नहीं था कि भारत के विकास के मॉडल पर वैश्विक छाप थी. साम्राज्यवादी शासन से मुक्त हुए देशों में भारत की अकादमिक प्रतिभाओं ने अपनी ऐसी पहचान बनाई, जिसे नजरंदाज नहीं किया जा सकता था. संक्षेप में कहें तो भारत ने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी स्थिति बनाई, जिसका असर लोकनीति और राजनीति पर पड़ा.

आजादी के बाद के दशकों में सामाजिक विज्ञान से जुड़े जानकार राष्ट्र निर्माण की चुनौती से जूझ रहे थे. इसलिए यह कोई संयोग नहीं है कि संसाधनों की कमी के बावजूद सामाजिक विज्ञान भारत में बढ़ा. भारतीय विश्वविद्यालयों ने वैश्विक स्तर की सोच और प्रतिभाओं का सृजन किया. यह भी कोई संयोग नहीं था कि भारत के विकास के मॉडल पर वैश्विक छाप थी. साम्राज्यवादी शासन से मुक्त हुए देशों में भारत की अकादमिक प्रतिभाओं ने अपनी ऐसी पहचान बनाई, जिसे नजरंदाज नहीं किया जा सकता था. संक्षेप में कहें तो भारत ने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी स्थिति बनाई, जिसका असर लोकनीति और राजनीति पर पड़ा.

1980 के दशक से भारत में उच्च शिक्षा का तेजी से विस्तार हुआ. साक्षरता की बढ़ती दर और सामाजिक बदलावों की वजह से लाखों नए छात्र भारतीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आए. यह विस्तार सिर्फ इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रबंधन में नहीं, बल्कि सामाजिक विज्ञान और मानविकी में भी दिखा. इससे पैदा होने वाली मांग को पूरा करने में सरकारी धन हमेशा कम पड़ा. निजी शिक्षण संस्थानों का सामाजिक विज्ञान से कोई मतलब नहीं रहा. कम से कम दो पीढ़ियां ऐसी बड़ी हो गई हैं, जिनका सामाजिक विज्ञान और मानविकी की शिक्षा से कोई संबंध नहीं रहा. इस खाई को टेलीविजन और आजकल वाट्सएप भरने का काम कर रहा है. इस आधार पर राजनीतिक क्षेत्र को यह समझना चाहिए कि इस तरह की शिक्षा का क्या परिणाम हो सकता है?

सामाजिक विज्ञान और मानविकी की उपेक्षा से कई समस्याएं पैदा हो रही हैं. इन क्षेत्रों में ऐसे लोग आ गए हैं, जो सरल से सरल चीज को जटिल बना देते हैं. इससे सामाजिक विज्ञानियों के लिए समाज को समझ पाना मुश्किल हो गया है और यह काम सरकार पर निर्भर होकर रह गया है.

भारत आज के दो या तीन दशक पहले वाला नहीं है. लिखने-पढ़ने वालों की संख्या, काम और घूमने के लिए यात्रा करने वालों की संख्या, संपत्ति रखने वालों की संख्या, पेशे और आय में हुए बदलाव, ये सभी आजादी के वक्त के भारत या इंदिरा गांधी के तुरंत बाद के भारत से काफी अलग हैं.

लेकिन इस भारत को समझने के लिए नए सिद्धांत और नई पद्धति कहां है? आज के भारत को समझाने वाले मॉडल कहां हैं? नए भारत और अकादमिक दुनिया की खाई की वजह से न तो अचंभित करने वाले चुनाव परिणामों को समझा जा सकता है और न ही नोटबंदी के अनापेक्षित नतीजों को. ऐसे ही और भी कई अनसुलझे विषय हैं.

आजादी के 70 साल बाद हम ऐसे देश में रह रहे हैं, जिसकी पहचान करना न सिर्फ उनके लिए संभव नहीं है, जो आजादी के लिए लड़े थे, बल्कि इस जर्नल में लिखने वालों के साथ बहुत अन्य लोगों के लिए भी संभव नहीं है.

स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा मौका है, जब अपने काम के प्रति फिर से प्रतिबद्धता दोहराई जाए. इकॉनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली और इसका पुराना अवतार इकॉनोमिक वीकली भारत की आत्म-जागृति में गर्व से शामिल रहा है. एक ऐसे समय में जब खोज की भावना को मजबूत करने की जरूरत है, हम अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहना चाहते हैं कि हम संवाद, बहस और अनसुने लोगों को आवाज देने के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे. जिन लोगों को साम्राज्यवाद का अनुभव नहीं है, उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई आवाज का उदय जरूरी है.■

(साभार : इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली)

feedback@chauthiduniya.com

गोरखपुर में बच्चों के 'संहार' का असली अपराधी कौन?

योगी साधे मौन...

बदले निजाम में भी कमीशनखोरी से बाज नहीं आ रहे नेता-नौकरशाह

इसीलिए सपा सरकार के पाप की फसल काट रही है भाजपा सरकार

गड़बड़ी का पहले से पता था फिर भी सही समय पर नहीं की कार्रवाई

प्रभात रंजन दीन

गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 60 से अधिक बच्चों की मौत तकलीफदेह चर्चा का विषय बनी रही. बच्चों की मौत पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बेजा बयान भी निंदा के केंद्र में रहा. जांच और कार्रवाइयों की घोषणाएं बच्चों की दुखद मौत की अक्षम्य घटना पर पर्दा नहीं डाल सकतीं. यूपी की मौजूदा भाजपा सरकार हवा में हाथ भांज रही है. निवर्तमान सपा सरकार ने स्वास्थ्य के मसले को इतनी गुत्थियों में उलझा रखा था कि गोरखपुर हादसे की जिम्मेदारी तय करने में योगी सरकार के पसीने निकल आएंगे और कोई पकड़ में भी नहीं आएगा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने नासमझ बयान जारी कर लोगों का आक्रोश अपनी तरफ कर लिया, लेकिन जमीनी वास्तविकता यही है कि गोरखपुर अस्पताल हादसा यूपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन के विभाग की बुरी सेवाओं का भी प्रतिफल है. प्रदेश के पूर्वांचल के जिन जिलों में तथाकथित जापानी इंसेफ्लाइटिस या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम बीमारी फैली है, वहां-वहां वेंटिलेटर सुविधा स्थापित करने और संचालित करने के लिए बजट मुहैया कराने और उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी यूपी की परिवार कल्याण मंत्री डॉ. रीता बहुगुणा जोशी के तहत चलने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) पर है, जिसपर कोई उंगली नहीं उठा रहा है, क्योंकि लोगों को इस प्रकरण में एनएचएम की अंदरूनी 'खलनायकी' भूमिका की जानकारी ही नहीं है.

अब थोड़ा पृष्ठभूमि में चलें. वर्ष 2013 में तत्कालीन समाजवादी सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अहमद हसन के चहेते चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशक डॉ. बलजीत सिंह अरोरा ने प्रदेश के जापानी इंसेफ्लाइटिस व एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम प्रभावित जिलों में इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) को प्रस्ताव भेजा और टर्न-की प्रॉसेस पर अहमद हसन की चहेती कंपनी 'पुष्पा सेल्स' को काम दे दिया. बजाज स्कूटर बेचने वाली इस कंपनी को स्वास्थ्य से सम्बन्धित करोड़ों का काम देने का तब विरोध भी हुआ था, लेकिन अहमद हसन और डॉ. बलजीत सिंह अरोरा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा. इस कंपनी को गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कालेज में सौ वेंटिलेटर लगाने और मरीजों के इलाज में सुविधा देने के लिए टेक्नीशियन मुहैया कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. वर्ष 2014 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्कालीन निदेशक अमित कुमार घोष ने इस क्षेत्र में एक टीम भेज कर 'पुष्पा सेल्स' के काम की समीक्षा की थी और गोरखपुर में दो मंडलों के मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों सहित जिम्मेदार अधिकारियों की बैठक में 'पुष्पा सेल्स' की ख़राब सेवाओं को उजागर किया था. सेंट्रल ऑक्सीजन यूनिट को बिजली की हाई-टेंशन लाइन के नीचे स्थापित करने और पुरानी पाइप-लाइन से ऑक्सीजन सप्लाई करने का मामला भी उनके समक्ष आ चुका था. उस समय प्रदेश के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन के दबाव में घोष के न चाहने के बावजूद डॉ. बलजीत सिंह अरोरा रिटायरमेंट के बाद भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रधान सलाहकार बना दिए गए. स्वाभाविक है कि उपकृत अरोरा ने 'पुष्पा सेल्स' पर कोई कार्रवाई नहीं होने दी. 'पुष्पा सेल्स' कंपनी ने जैसे-तैसे मनचाहे तरीके से इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर्स स्थापित किए और अयोग्य एवं अक्षम कर्मचारियों को भर कर जानलेवा तरीके से पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट चलाया. कंपनी जो भी बिल भेजती महानिदेशालय के जरिए एनएचएम उसका भुगतान करता जाता.

अहमद हसन ने अपनी सरकार के आखिरी महीनों में डॉ. विजय लक्ष्मी को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का महानिदेशक बना दिया और सपा सरकार के आखिरी समय तक लूटपाट वाली व्यवस्था जारी रही. उस दरम्यान ही हाईकोर्ट ने डेंगू, मलेरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से बेतहाशा हो रही मौतों पर राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी दी थी. आप यह जानते चलें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम सहित सभी संचारी रोगों के कार्यक्रम के संचालन और नियोजन की जिम्मेदारी 'राष्ट्रीय कार्यक्रम' नामक अनुभाग के पास है. एनएचएम के तत्कालीन निदेशक अमित कुमार घोष ने डॉ. विजय लक्ष्मी के दबाव में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश में ईमानदार छवि के 'राष्ट्रीय कार्यक्रम' के महाप्रबंधक डॉ. अनिल कुमार मिश्र को हटा कर उनके खास डॉ. मनीराम गौतम को महाप्रबंधक बना दिया था, ताकि महानिदेशालय में डॉ. विजय लक्ष्मी की करतूतें जारी रह सकें. यह भी बताते चलें कि दिसम्बर 2015 में डॉ. विजय लक्ष्मी भी डॉ. बलजीत सिंह अरोरा की तरह ही एनएचएम में सवा लाख के वेतन पर चोर-रास्ते से मिशन निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के गैर-सृजित पद पर काबिज हो गईं. उन्हें एनएचएम में 'राष्ट्रीय कार्यक्रम' सहित कई महत्वपूर्ण अनुभागों का नोडल अधिकारी बनाया गया था.

समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्य सचिव आलोक रंजन के स्टाफ अफसर रहे आलोक कुमार को अप्रैल में एनएचएम का मिशन निदेशक बनाया गया. उनके आने के बाद पूर्व महानिदेशक रहे डॉ. बलजीत सिंह अरोरा और डॉ. विजय लक्ष्मी की और तूती बोलने लगी. वर्ष 2016 के जुलाई महीने में डॉ. मनीराम गौतम के रिटायर होने के बाद डॉ. विजय लक्ष्मी ने अपने दूसरे खास व्यक्ति अस्थि रोग के सर्जन और संचारी रोग के वर्तमान संयुक्त निदेशक डॉ. एके पांडेय को एनएचएम में 'राष्ट्रीय कार्यक्रम' का महाप्रबंधक बनवा दिया. डॉ. पांडेय को सप्ताह के तीन दिन एनएचएम और दो दिन महानिदेशालय में काम करने का आदेश जारी करवाने में डॉ. विजय लक्ष्मी का विशेष हाथ था. दूसरी तरफ डॉ. मनीराम गौतम को जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम उन्मूलन में सहयोग देने के लिए प्रदेश में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठन 'पाथ' में विशेषज्ञ के रूप में एक लाख से अधिक की सैलरी पर चयनित करवा दिया. वर्तमान मिशन निदेशक आलोक कुमार ने इस तरह इस अति महत्वपूर्ण अनुभाग को बेहद हल्के से लिया. हद तो यह है कि एनएचएम के अनुश्रवण और मूल्यांकन विभाग ने अगले छह महीने के लिए भी डॉ. एके पांडेय को ही गोरखपुर मंडल का प्रभारी बनाया है. डॉ. पांडेय प्रत्येक महीने गोरखपुर मंडल में कम-से-कम तीन दिन बिताकर 'राष्ट्रीय कार्यक्रम' सहित सभी कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति से प्रदेश सरकार को अवगत कराने के लिए जिम्मेदार हैं. सवाल यह भी है कि अप्रैल से लेकर अगस्त महीने तक डॉ. पांडेय ने इन जिलों में जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से बचाव के लिए क्या-क्या कदम उठाए? उनकी सलाह पर इस कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉ. विजय लक्ष्मी ने क्या किया? इन अधिकारियों ने सरकार को किस तरह की ब्रीफिंग दी? यह तथ्य भी सामने आना जरूरी है कि क्लीनिकल सेवाओं के विशेषज्ञ माने जाने वाले डॉ. एके पांडेय को हाल में जब मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बना दिया गया था तब डॉ. विजय लक्ष्मी ने उन्हें एनएचएम में ही क्यों रोक लिया?

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मौजूदा मिशन निदेशक आलोक कुमार ने समाजवादी पार्टी की सरकार में भ्रष्ट गतिविधियों के लिए चर्चित रहे पूर्व महानिदेशक डॉ. बलजीत सिंह अरोरा और डॉ. विजय लक्ष्मी के इशारों पर काम करते हुए डॉ. एके पांडेय को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और पॉलिटेक्निक से कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त सिफ्सा के कर्मचारी बीके जैन को मूल्यांकन और अनुश्रवण (रख-रखाव) का महानिदेशक बना कर इतने ढेर सारे बच्चों की तकलीफदेह मौत की साजिश रच दी. इसके बावजूद महामूर्धन्य योगी सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही. विडंबना यह है कि गोरखपुर हादसे की जांच के लिए योगी सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित जांच समिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के निदेशक आलोक कुमार भी शामिल हैं. हादसे के लिए जो लोग दोषी हैं, वही जांच करेंगे तो पकड़ा कौन जाएगा? शासन के ही एक आला अधिकारी कहते हैं कि दोषी को ही जांच अधिकारी बनाने में योगी सरकार को महारत हासिल है. विधानसभा में अवैध नियुक्तियों के मामले की जांच भी योगी सरकार ने नियुक्ति घोटाले में लिप्त रहे विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे को ही दे दी थी. उस जांच का भी कोई नतीजा नहीं निकला, उसी तरह बच्चों की मौत के मामले की जांच का भी कोई परिणाम नहीं निकलेगा.

(शेष पृष्ठ 11 पर)

वो भी फूटे जिनमें हैं छेद ही छेद

गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 60 से अधिक बच्चों की मौत पर समाजवादी पार्टी ने फौरन अपनी प्रतिक्रिया का पिटारा खोल दिया. पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी तक भाजपा सरकार की बदइंतजामी के खिलाफ ताबड़तोड़ बोलने लगे, ऐसा करते समय समाजवादी पार्टी के इन नेताओं ने अपनी गिरेबान में नहीं झांका कि सब किया धरा उन्हीं का है, ठीकरा योगी सरकार पर फूट रहा है. अखिलेश यादव ने कहा कि बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है. मृतकों के परिजनों को आनन-फानन लाश देकर भगा दिया गया. मृत बच्चों का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया. अखिलेश ने आरोप लगाया कि योगी सरकार ने सच्चाई छुपाने के लिए यह किया. सरकार बच्चों की जान जाने का कारण नहीं बता पा रही है. सरकार मौतों को छिपा रही है. मृतक बच्चों के परिजनों को अस्पताल के पीछे के रास्ते से बाहर निकाला जा रहा था. अखिलेश ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री स्तर पर हुई समीक्षा में भी ऑक्सीजन का भुगतान न होने की बात सामने नहीं लाई गई तो गलती किसकी है. अखिलेश ने कहा कि हो सकता है कि कमीशन की वजह से ऑक्सीजन का भुगतान न हुआ हो. सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा अध्यक्ष ने गोरखपुर अस्पताल में बच्चों की मौत की जांच पार्टी की जांच समिति से कराने का फैसला किया है. जांच समिति में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी, पूर्वमंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, एमएलसी संतोष यादव सनी, पूर्व राज्यमंत्री राधेश्याम सिंह, जिलाध्यक्ष प्रह्लाद यादव और महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम शामिल हैं. दूसरी तरफ स्वराज अभियान संस्था ने बच्चों की मौत को सरकार की आपराधिक लापरवाही बताया है और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांगा है. स्वराज अभियान के राज्य कार्य समिति सदस्य और यूपी वर्कर्स फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनकर कपूर ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई का बाधित होना और सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं देना प्रदेश सरकार की आपराधिक लापरवाही है. स्वास्थ्य मंत्री द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बच्चों की मौत के जो आंकड़े पेश किए गए, वे यह बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौतों को रोकने का किया गया वायदा झूठा साबित हुआ है. दिनकर कपूर ने कहा कि योगी सरकार के बनने के बाद प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को धन नहीं भेजा गया. यहां तक कि कई जगह दवा की आपूर्ति तक नहीं की गई है. हालत इतनी बुरी है कि प्रदेश में डाक्टरों समेत चिकित्सा स्टाफ की भारी कमी है. कपूर ने हादसे का शिकार हुए बच्चों के परिजनों को पचास लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की. ■

गोरखपुर में 60 से अधिक बच्चों की मौत हादसा नहीं हत्या है

पृष्ठ 10 का शेष

नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 60 से अधिक बच्चों की मौत को हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या का मामला बताया है और दोषियों पर हत्या का मुकदमा चलाए जाने की मांग की है. गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले दिनों 60 से अधिक बच्चों की मौत हो गई. बच्चों की मौत का मुख्य कारण अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई का बंद हो जाना है. इसके अलावा जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से भी बच्चों की मौत हुई. यह बात भी सामने आई कि अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाली कंपनी 'पुष्पा सेल्स' ने सरकार को बकाया भुगतान करने के बारे में पहले ही लिखा था और सरकार को अमानवीय-चेतावनी भी दी थी कि भुगतान नहीं हुआ तो ऑक्सीजन की सप्लाई तत्काल बंद कर दी जाएगी. योगी सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय भी उतना ही बड़ा हृदयहीन साबित हुआ, जिसने 'पुष्पा सेल्स' की चेतावनी को संजीदगी और गंभीरता से नहीं लिया.

'पुष्पा सेल्स' ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को भी छह अप्रैल को बकाये के भुगतान का रिमाइंडर भेजा था. उस पत्र में लिखा गया था कि तीन अप्रैल 2017 तक अस्पताल पर 52 लाख 34 हजार 774 रुपए का बकाया है. अगर लंबित बिल का भुगतान नहीं हुआ, तो सप्लाई नहीं मिल पाएगी. 'पुष्पा सेल्स' का यह पत्र स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन को भेजा गया था. पत्र की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री को भी भेजी गई थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत होना सही तथ्य नहीं है. मुख्यमंत्री ने प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन की रिपोर्ट के हवाले से इसकी आधिकारिक पुष्टि की कि ऑक्सीजन सप्लायर ने एक अगस्त को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बकाये के भुगतान के बारे में पत्र लिखा था. प्रिंसिपल ने चार अगस्त को मेडिकल एडुकेशन के डीजी को पत्र लिखकर सूचित किया था और पांच अगस्त को दो करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई थी. मुख्यमंत्री ने माना कि इस प्रकरण में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. राजीव मिश्र की लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते उन्हें निलम्बित कर दिया गया है. प्राचार्य की सरपरस्ती में अस्पताल में तमाम अवैध गतिविधियां चलाने के आरोप में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इंसेफ्लाइटिस विभाग के चीफ नोडल अफसर डॉ. कफील अहमद को भी पद से हटा दिया गया है. अस्पताल की पर्चेज कमेटी के सदस्य डॉ. कफील अस्पताल में ऑक्सीजन सिलिंडरों के बंदोबस्त के भी प्रभारी थे. उन पर ऑक्सीजन सिलिंडरों के बेजा निजी इस्तेमाल की भी शिकायतें सामने आई हैं. अंबेडकर नगर राजकीय मेडिकल कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. पीके सिंह को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई वाले पहलू की जांच के लिए मुख्य सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर दी गई है. घटना की मैजिस्टीरियल जांच भी कराई जा रही है.

'पुष्पा सेल्स' कंपनी पहले भी विवादों में रही है. किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के शताब्दी फेज-दो अस्पताल में ऑक्सीजन पाइप लाइन बिछाने के काम में इस कंपनी को तीन करोड़ का टेंडर महज 80 लाख रुपए में दे दिया गया था. जून 2014 तक न्यूरो डिपार्टमेंट

में पाइप लाइन बिछाने का काम पूरा होना था, लेकिन 2015 तक काम पूरा नहीं हुआ. अस्पताल प्रशासन की फटकार के बाद वर्ष 2016 में किसी तरह काम पूरा हो सका. वर्ष 2014 में कानपुर के हृदय रोग संस्थान ने भी इस कंपनी को खराब वेंटिलेटर और खराब कम्प्रेस्ड एयर पाइप लाइन बनाने के लिए कड़ी फटकार लगाई थी. अस्पताल प्रबंधन ने 'पुष्पा सेल्स' कंपनी को लिखा था, 'पुष्पा सेल्स फर्म ने संस्थान में ऑक्सीजन की पाइपलाइन स्थापित की थी जिस पर पांच साल की वारंटी का भुगतान भी हुआ था, लेकिन अत्यंत खेद है कि कम्प्रेस्ड एयर की पाइपलाइन में पानी आ रहा है और कंपनी का लगाया हुआ ड्रायर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है. इससे पाइप-लाइन के जरिए ऑपरेशन थियेटर (ओटी) व आइसीयू के वेंटीलेटर्स में पानी आ रहा है. इसी वजह से एक वेंटीलेटर खराब भी हो चुका है. इस बारे में दो बार शिकायत करने के बावजूद ड्रायर नहीं बदला गया. अब भी देर हुई तो कंपनी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होगी.' यह शिकायती पत्र 14 जुलाई 2014 को कानपुर हृदय रोग संस्थान के निदेशक ने 'पुष्पा सेल्स' को भेजा था. वही फर्म अब गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद करने को लेकर विवादों में है. लखनऊ के आलमबाग में बजाज स्कूटर बेचने वाली एजेंसी समाजवादी सरकार की कृपा से सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन बेचने लगी. 'पुष्पा सेल्स' के खिलाफ तमाम शिकायतों के बावजूद सपा सरकार ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की. फर्म की लगाई पाइप लाइन से आइसीयू में ऑक्सीजन के बजाए पानी पहुंचने की गंभीर शिकायत के बावजूद सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. समाजवादी सरकार बेहतर स्वास्थ्य का फर्जी नारा बेचती रही और 'पुष्पा सेल्स' बेहतर रिश्वत देकर अपना धंधा चलाती रही और लोगों को मारती रही. दुखद तथ्य यह है कि बीआरडी अस्पताल के बाल रोग विभाग ने 20 जून 2014 को 'पुष्पा सेल्स' से औपचारिक तौर पर कहा था कि सौ बिस्तर वाले मस्तिष्क ज्वर विभाग में लगाए गए ऑक्सीजन पाइप लाइन के कम्प्रेसर, एयर वैक्यूम और इमरजेंसी रेगुलेटर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं. नवजात शिशुओं के लिए चौबीसों घंटे ऑक्सीजन की जरूरत होती है. यदि विषम परिस्थिति सामने आई, तो सारी जिम्मेदारी फर्म की होगी. लेकिन फर्म ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया और अस्पताल ने भी अपनी औपचारिकता पूरी कर ली. 'पुष्पा सेल्स' कंपनी ने वर्ष 2013 में ही लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण में टेंडर की शर्तों का उल्लंघन किया था. निर्माण कार्य में देरी के कारण इस कंपनी को तत्कालीन प्रिंसिपल डॉ. सतीश कुमार ने कड़ी चेतावनी भी दी थी, लेकिन सरकार में बैठे अफसरों ने इस पर ध्यान नहीं दिया. याद करते चलें कि 'पुष्पा सेल्स' कंपनी को वर्ष 2013 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक विभाग में सौ बेड के मस्तिष्क ज्वर वार्ड में ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन स्थापित करने का ठेका दिया गया था. टेंडर की शर्तों के अनुसार इस कंपनी को दो महीने में काम पूरा करना था, लेकिन कंपनी ने तय समय में काम पूरा नहीं किया. इस पर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रधानाचार्य ने गहरी आपत्ति जताई थी, लेकिन अखिलेश सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी. कंपनी ने नवम्बर 2013 तक काम पूरा करने का आश्वासन दिया लेकिन काम पूरा नहीं कर सकी. दिसम्बर तक काम पूरा नहीं हुआ तब प्रधानाचार्य ने कंपनी को कड़ी चेतावनी दी. 24 दिसम्बर 2013 को लिखे पत्र में प्रधानाचार्य ने 15 दिन के अंदर काम पूरा करने को कहा और चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. प्रधानाचार्य ने इस पत्र की प्रतिलिपि चिकित्सा शिक्षा विभाग के महानिदेशक के साथ-साथ गोरखपुर के जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को भी भेज दी थी. चिकित्सा शिक्षा के महानिदेशक ने भी अपनी जांच में पाया कि 'पुष्पा सेल्स' निर्धारित समय पर लिक्विड गैस प्लांट की स्थापना नहीं कर सकी. इसके लिए कंपनी को लापरवाह करार दिया गया. इसके बावजूद कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. जबकि नियमानुसार अगर कोई कंपनी टेंडर की शर्तों का उल्लंघन करती है, तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है. सपा सरकार इस कंपनी के उपकार से इतनी लदी थी कि कंपनी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया.

बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पैसा बकाया होने की जो बात फैलाई जा रही है वह नियोजित है. सरकार पर दोष डालने के लिए इसे तूल दिया जा रहा है. तथ्य यह है कि 'पुष्पा सेल्स' वर्ष 2014 से ही अस्पताल को लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है. नवम्बर 2016 से मेडिकल कॉलेज के साथ कंपनी का पेमेंट को लेकर विवाद शुरू हुआ, लेकिन उस समय कंपनी ने ऑक्सीजन सप्लाई नहीं रोकी. 'पुष्पा सेल्स' अब तक करोड़ों रुपए का पेमेंट सरकार से ले चुकी है. लेकिन महज कुछ लाख रुपए के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दिए जाने की घटना की गहराई से जांच होनी चाहिए. गोरखपुर के लोग कहते हैं कि इस हादसे के पीछे सुनियोजित षड्यंत्र है. चिकित्सा शिक्षा के महानिदेशक डॉ. केके गुप्ता ने कहा भी कि 'पुष्पा सेल्स' के पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए हैं. कंपनी को पहले भी कई बार बिलंब से पेमेंट दिया गया है, लेकिन कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि ऑक्सीजन सप्लाई ही बंद कर दी जाए. कंपनी ने जब ऑक्सीजन सप्लाई रोकने की नोटिस दी थी, उसी समय मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को इस समस्या का हल करना चाहिए था. गहराई से छानबीन हो तो यह मामला भी एनआरएचएम घोटाले की तरह विकराल घोटाला निकले. शासन ने प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण और बेहद संवेदनशील मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई का ठेका एक नौसिखिया कंपनी को दे दिया, इसकी भी गहराई से जांच होनी चाहिए. सियासी पहुंच के कारण बगैर अनुभव वाली इस कंपनी को चिकित्सा शिक्षा विभाग के अफसरों ने भी काम देने में कोई आपत्ति नहीं जताई. यह कंपनी ऑपरेशन थिएटर को मॉड्यूलर बनाने के उपकरण भी सप्लाई करती थी. एनआरएचएम में भी गैर पंजीकृत सोसाइटी को 1546 करोड़ रुपए दे दिए गए थे. इसमें भी बहुत सी चहेती कंपनियों को सरकार ने ठेका दे दिया था. ■

feedback@chauthiduniya.com

इंसेफ्लाइटिस का कहर, मंत्री के बचने का बहाना

पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस का कहर अब सरकारों के बचने का बहाना बनता जा रहा है. गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे में 60 से अधिक बच्चों की मौत पर प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री यह कहता हो कि इस मौसम में तो बच्चे इंसेफ्लाइटिस से मरते ही रहते हैं तो आप समझ लें कि यह लोकतंत्र के मरने की पूर्व घोषणा है. बच्चों की मौत पर इंसेफ्लाइटिस का बहाना यह बताता है कि सरकारों को दुष्टता का रोग लग गया है. इंसेफ्लाइटिस रोग दशकों से बच्चों की जान ले रहा है और सरकारें बेशर्मी से कहती हैं कि इस मौसम में बच्चे मरते ही हैं तो यह कितने शर्म की बात है! लेकिन भारतीय लोकतंत्र में नेताओं को शर्म नहीं आती है. यह कितना दर्दनाक आधिकारिक आंकड़ा है कि बारिश के मौसम में एक अकेले गोरखपुर बीआरडी अस्पताल में दो हजार से ढाई हजार बच्चे भर्ती होते हैं और करीब पांच सौ बच्चे मर जाते हैं. यूपी के गोरखपुर समेत पूरब के 12 जिलों के एक लाख से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है. वर्ष 2016 में इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों की संख्या 15 फीसदी बढ़कर 514 हो गई. यह आंकड़ा सिर्फ गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का है. बच्चे मर रहे हैं लेकिन इसका कोई उपाय नहीं किया गया. सरकारें इसे जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का नाम देती रहीं, लेकिन बेशर्म सरकारों को इस बात पर तनिक भी झेंप नहीं आई कि जापान ने इस बीमारी पर 1958 में ही कारगर तरीके से काबू पा लिया था और हम अब भी लाचार हैं. पूर्वांचल में पिछले चार दशक से जापानी इंसेफ्लाइटिस से बच्चे लगातार मर रहे हैं. पूरब के जिलों के अधिकांश मरीज बच्चे गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही भर्ती होते हैं. इस अस्पताल में न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से बल्कि पश्चिमी बिहार और नेपाल के मरीज भी भर्ती होते हैं. अत्यधिक दबाव के कारण मेडिकल कॉलेज को दवाइयों, डाक्टरों, पैरा मेडिकल स्टाफ, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन व अन्य जरूरतों के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है. इंसेफ्लाइटिस की दवाओं, चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, उपकरणों की खरीद, मरम्मत और उनके रखरखाव के लिए अलग से कोई बजट का प्रबंध नहीं है. गोरखपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सौ बेड का इंसेफ्लाइटिस वार्ड बन जाने के बावजूद मरीजों के लिए बेड व अन्य संसाधानों की भारी कमी है. मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आने वाले इंसेफ्लाइटिस मरीजों में आधे से अधिक अर्ध बेहोशी के शिकार होते हैं और उन्हें तुरन्त वेंटिलेटर उपलब्ध कराने की जरूरत रहती है. इस अस्पताल में पीडियाट्रिक (बाल रोग) आईसीयू में 50 बेड उपलब्ध हैं. वार्ड संख्या 12 में कुछ वेंटिलेटर हैं. बच्चों की मौत पर मर्सिया पढ़ने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र के मंत्री तक गोरखपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए धन की कमी नहीं होने देने की बातें करते हैं, लेकिन असलियत यही है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज की तरफ से पिछले चार-पांच वर्षों के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार को जो भी प्रस्ताव भेजे गए, वे मंजूर नहीं हुए. इन प्रस्तावों में यह भी शामिल था कि इंसेफ्लाइटिस के मरीजों के इलाज में लगे चिकित्सकों, नर्स, वार्ड ब्वॉय और अन्य कर्मचारियों का वेतन, मरीजों की दवाइयां और उनके इलाज के काम आने वाले उपयोगी उपकरणों की मरम्मत के लिए एकमुश्त बजट आवंटित किया जाए. यह बजट सालाना करीब 40 करोड़ आता है, लेकिन इस प्रस्ताव को न तत्कालीन अखिलेश सरकार ने सुना और न केंद्र सरकार ने. यह आधिकारिक तथ्य है कि 14 फरवरी 2016 को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक से इंसेफ्लाइटिस के इलाज के मद में 37.99 करोड़ मांगे थे. महानिदेशक ने इस पत्र को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक को भेज कर अपनी ड्यूटी निभा ली और एनएचएम को भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं मिली.

दुखद पहलू यह भी है कि जापानी इंसेफ्लाइटिस की बीमारी से जो बच्चे उबर जाते हैं, उनमें से भी अधिकांश बच्चे विकलांग होकर ही वापस लौटते हैं. अनधिकृत रिपोर्ट है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम बीमारी के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग हुए बच्चों की संख्या 50 हजार से कम नहीं है. जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम बीमारी में एक तिहाई बच्चे मानसिक और शारीरिक विकलांगता का शिकार हो जाते हैं. बाल आयोग ने कई बार प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम बीमारी से विकलांग हुए बच्चों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कराए और उनके इलाज, शिक्षा और पुनर्वास के लिए ठोस काम हो, लेकिन यह काम सरकारों की रुचि के दायरे में नहीं आता, क्योंकि विकलांग बच्चों से नेताओं को वोट नहीं मिलता. सर्वेक्षण का काम सरकार नहीं करा पाई और गैर सरकारी संस्थाओं ने भी इस सर्वेक्षण के काम में रुचि नहीं ली. ■

बहुत कुछ तय होगा राजद की रैली से

सुकान्त

बिहार में रैलियों का जिक्र होता है, तो लालू प्रसाद की बात जरूर होती है. उनके आह्वान पर पटना में आयोजित रैलियां राजनीतिक दलों के लिए पैमाना बनती रही हैं. हालांकि सत्ता के बाहर (विपक्ष में) रहते हुए रैली आयोजित करने का जोखिम लालू प्रसाद बहुधा मोल नहीं लेते हैं. फिर भी, गत संसदीय और विधानसभा चुनावों के पहले, जब वे सत्ता के हिस्सेदार नहीं थे, उन्होंने रैलियां की थी. ये बड़ी रैलियां थीं, पर ऐतिहासिक नहीं. पिछले विधानसभा चुनावों से पहले आयोजित रैली में श्रीमती सोनिया गांधी भी आई थीं. इससे राजद सुप्रीमो की राजनीतिक वक़त को देश की गैर-सांप्रदायिक राजनीति में व्यापक स्वीकृति के तौर पर लिया गया था. अब फिर लालू प्रसाद के आह्वान पर पटना में राजद की रैली हो रही है. इसे 'देश बचाओ, भाजपा भगाओ' नाम दिया गया है. इस रैली के आयोजन का फैसला तो तब ही हो गया था, जब सूबे में महागठबंधन की सरकार थी. महागठबंधन के इस तरह और इतनी जल्दी बिखरने का अंदाजा कम से कम लालू परिवार को तो नहीं ही था. उस समय यह उम्मीद की गई थी कि सरकार में 'बड़े भाई' होने का लाभ राजद को रैली में मिलेगा. लेकिन यह उम्मीद धरी की धरी रह गई. भाजपा के खिलाफ तो रैली का आयोजन है ही, अब सूबे के बदले राजनीतिक समीकरण के कारण जनता दल(यू) सुप्रीमो व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसके केन्द्र में हैं. महागठबंधन से अलग होने और भाजपा के साथ जाने के नीतीश कुमार के पाला-बदल को राजद और उसके समर्थक विधानसभा चुनाव के जनादेश का अपमान और विश्वासघात मानते हैं. रैली के लिए राजद के प्रचार अभियान में इसे बड़ा मसला बनाया जा रहा है. रैली के प्रचार अभियान के दौरान लालू-राबड़ी के दोनों पुत्र- पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस राजनीतिक पाला-बदल को सीधे निशाने पर ले रहे हैं. अपने पिता की तरह तेजप्रताप और तेजस्वी भी जनता के बीच अपनी भूल स्वीकार करते हैं कि 'नीतीश कुमार को पहचानने में उनसे चूक हुई'.

एनडीए को सीधी चुनौती

देश के अगले संसदीय चुनाव में अभी कम से कम डेढ़ साल की देरी है, पर लालू प्रसाद भाजपा को चुनौती देने की किसी भी कोशिश में पीछे नहीं रहना चाहते. वे अपनी भाजपा विरोधी राजनीति को शान देने के हर उपकरण का इस्तेमाल सुनिश्चित करना चाहते हैं. इसलिए रैली में बिहार के लोगों की व्यापक भागीदारी तो वे चाहते ही हैं, देश में भाजपा विरोधी राजनीति के तमाम बड़े चेहरों को भी अपनी इस रैली के साथ देखने-दिखाने की पूरी कोशिश करना चाहते हैं. वे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ-साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, चौधरी देवीलाल के उत्तराधिकारी दुष्यंत चौटाला और वामपंथी दलों के नेताओं को भी अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं. इसके जरिए लालू प्रसाद देश में भाजपा विरोधी राजनीति के केन्द्र में खुद को लाने की कोशिश कर रहे हैं. राजद सुप्रीमो ने रैली के आयोजन का फैसला तब लिया था, जब वे सूबे की सरकार के बड़े पार्टनर थे. लेकिन अब सूबे की राजनीति बदल गई है. ऐसे

अब एनडीए के मुख्यमंत्री बन गए. इसलिए बड़े बेआबरू होकर सत्ता से बाहर आए राजद सुप्रीमो के लिए इस रैली की सफलता-विफलता उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा से जुड़ गई है. इसके जरिए वे दिखाना चाहते हैं कि वे सत्ता में रहें या उसके बाहर, सूबे की भाजपा विरोधी आबादी उनके साथ है और इस लिहाज से देश की भाजपा विरोधी राजनीति में बिहार के प्रतिनिधित्व के असली हकदार वे ही हैं. यह बताने की जरूरत नहीं कि देश में भाजपा विरोधी राजनीति में नीतीश कुमार नेतृत्वकारी भूमिका चाहते थे, पर उन्हें ये महत्वाकांक्षा पूरी होती नहीं दिखी और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस को ही जिम्मेवार बताया था.

राजनीतिक भाष्यकारों व राजनेताओं की कमी नहीं है, जो इसकी सफलता-विफलता को सत्ता के साथ राजद के रिश्ते से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं. इसलिए लालू प्रसाद और राजद में उनके खास लोग चाहते हैं कि रैली में भीड़ तो बेशुमार हो ही, इसमें मंडलवादी राजनीति से जुड़े सभी सामाजिक समूहों की भागीदारी भी हो और वो दिखे भी. इसके जरिए लालू अपने विरोधियों को 'माय' समीकरण का संदेश भी देना चाहते हैं. इस रैली में दलितों की भी व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है. लोगों को पटना तक लाने और ले जाने की व्यवस्था तो की ही जा रही है, उनके आवास-भोजन का भी उपाय किया जा रहा है. राजद के सभी विधायकों, सासंदों, पूर्व सासंदों, पूर्व मंत्रियों के साथ-साथ सभी बड़े नेताओं को इस मामले में जरूरी टास्क दे दिया गया है. रैली आयोजन के रोड-मैप और उसके कार्यान्वयन की समीक्षा लालू प्रसाद खुद कर रहे हैं.

रैली के कई राजनीतिक निहितार्थ तो हैं ही, बिहार के बदले राजनीतिक हालात में इसकी सफलता-विफलता के भी दूरगामी महत्व हो गए हैं. पिछले एक महीने में राजनीति का चक्र कुछ ऐसा चला कि बिहार की सियासत में सब कुछ बदल गया. सूबे की सत्ता में 'बड़ा भाई' राजद और सबसे 'छोटा भाई' कांग्रेस अब विपक्ष में हैं और विपक्ष में बैठने वाले जनादेश से विधानसभा पहुंची भाजपा सत्ता की हिस्सेदार बन गई है. तत्कालीन महागठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में

जनादेश का आकलन

रैली की घोषणा और इसके आयोजन के बीच बिहार की राजनीति पूरी तरह बदल गई. महागठबंधन के सत्ता में आने के कुछ ही दिन बाद से राजद और जद(यू) के बीच इसे लेकर छाया-युद्ध आरंभ हो गया था कि इस ऐतिहासिक जनादेश का सेहरा किसके सर बंधना चाहिए? विधानसभा चुनावों के दौरान सीटों के बंटवारे में राजद और जद(यू) को बराबर-बराबर हिस्सा मिला था, लेकिन चुनाव परिणाम में लालू प्रसाद के राजद को 80 तो नीतीश कुमार के जद(यू) को 71 सीटों पर जीत मिली. इस मुद्दे पर छाया-युद्ध चलता रहा कि महागठबंधन को वोट किसके नाम पर मिला और इसका बड़ा नेता कौन है. महागठबंधन के बिखराव तक यह विवाद अंततः बना ही रहा. लालू प्रसाद व उनके पुत्र तेजस्वी कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी ने अकले अब तक एक विधानसभा और एक संसदीय चुनाव लड़ा है. इनमें से किसी में भी उन्हें दो अंकों में सीट हासिल नहीं हुई. वे ऐसा कहते हैं, तो गलत नहीं कहते. अब लालू प्रसाद अपनी रैली के जरिए नीतीश कुमार और उनके जद(यू) के नेताओं-प्रवक्ताओं के इस दावे को छिन्न-भिन्न करना चाहते हैं कि गत विधानसभा चुनावों में महागठबंधन को वोट नीतीश कुमार के नाम पर ही मिला था. वे खुद को बिहार में मंडलवादी सामाजिक समूहों का बड़ा नेता साबित कर नीतीश कुमार और जद(यू) की बोलती बंद करना चाहते हैं. रैली की सफलता लालू प्रसाद की राजनीति को नई उड़ान देगी और वे फिर बिहार में पिछड़ों के बड़े नेता साबित हो सकते हैं.

तेजस्वी के उत्तराधिकार पर मुहर

लालू प्रसाद की ये रैली अपने उत्तराधिकारी को सर्व-स्वीकृति दिलाने के अभियान के अंतिम चरण की राजनीति भी है. हालांकि अब यह तय हो गया है और परिवार में भी मान लिया गया है कि तेजस्वी ही लालू प्रसाद की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं. यह बात कोई चार-पांच साल पहले से कही जा रही है और लालू प्रसाद अपनी राजनीतिक गतिविधियों से इसे जताते भी रहे हैं. तेजस्वी को महागठबंधन सरकार में उपमुख्यमंत्री की हैसियत दिलाने और सरकार से बाहर होने के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने से यह बात साफ हो गई थी. फिर भी, राजद सुप्रीमो को बार-बार इसे जताना पड़ता है, क्यों? इसका बेहतर जवाब वे खुद या उनके खास राजद नेता ही दे सकते हैं. लेकिन राजनीतिक हलकों के अनुसार, लालू परिवार में उत्तराधिकारी को लेकर माहौल अब भी सहज नहीं हुआ है. एक ओर उनकी बेटियां भी अपना हक जता रही हैं, तो दूसरी ओर दोनों पुत्रों को लेकर भी घर में सहमति नहीं है. जनादेश अपमान यात्रा पर पहले तेजस्वी को अकेले जाना था. सारी तैयारी भी हो गई थी. लेकिन घर में ही इसे लेकर विवाद हो गया कि तेजप्रताप भी क्यों नहीं? अब इस पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं कि यह सवाल किसने उठाया, लेकिन ये सवाल उठा और तेजस्वी के साथ तेजप्रताप भी यात्रा पर गए. हालांकि लालू प्रसाद चाहते हैं कि उनकी राजनीतिक विरासत तेजस्वी ही संभालें. पार्टी में भी कई बड़े नेताओं द्वारा ये मान लिया गया है कि तेजस्वी ही राजद के युवराज हैं. अब लालू प्रसाद के वोटरों को इसे स्वीकार करना है और वोटरों की यह स्वीकृति 27 अगस्त की रैली में मिल जाएगी. उसी दिन देश भर के भाजपा विरोधी नेता तेजस्वी को अपना आशीर्वाद भी देंगे और इस तरह से तेजस्वी का औपचारिक राजतिलक हो जाएगा. इसके साथ रैली का यह उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा.

लालू प्रसाद के पास समय बहुत कम है. चारा घोटाले के मामलों की सुनवाई तेजी से चल रही है. अदालत के रुख से साफ है कि वो शीघ्रता से मामलों को निपटाना चाहती है. इधर पिछले कुछ महीनो में भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने राजद सुप्रीमो की भ्रष्टाचार-गाथाओं का पुलिंदा खोल कर उनका संकट और बढ़ा दिया है. महागठबंधन के बिखराव का तात्कालिक कारण भी मोदी के खुलासे पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो की कार्रवाई ही बनी थी. इन मामलों में जांच एजेंसियों के भी तेजी से आगे बढ़ने की ही संभावना दिख रही है. वस्तुतः राजद सुप्रीमो कानूनी तौर पर गंभीर रूप से घिर गए हैं और इनसे अभी उनकी मुक्ति नहीं दिख रही है. केन्द्र की भाजपा सरकार भी उनकी सियासी राह में रोड़े अटका रही है. ऐसे में लालू प्रसाद अपनी इस रैली के जरिए 'राजद की राजनीति को समाप्त करने की भाजपा की रणनीति' पर भी हमला करेंगे. हालांकि यह कितना तर्कसम्मत होगा, यह हम न तो जानते हैं और न कह सकते हैं. लेकिन ये आम अनुभव है कि लालू प्रसाद अपने संवाद-कौशल से अपने वोटरों को कुछ भी समझाने में सफल रहते हैं. अब देखना ये है कि इस बार उन्हें कितनी सफलता मिलती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

राजद और शरद दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत

संजय सोनी

पूरे कोसी में आजकल एक सवाल काफी चर्चा में है. जगह-जगह राजनीतिक मिजाज के लोग एक दूसरे से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोसी में शरद यादव राजद को बचाएंगे या राजद यहां शरद यादव को सहारा देगा. इस सवाल का जबाव तो आने वाला वक्त ही देगा. हालांकि इसे लेकर कोसी में राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है कि राजद और शरद यादव दोनों को एक दूसरे की जरूरत है. शरद यादव के हालिया कोसी यात्रा को विश्लेषक इसी नजरिये से देख रहे हैं.

जन संवाद यात्रा के बहाने कोसी की धरती पर एक बार फिर से जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद शरद यादव ने अपनी राजनीतिक जमीन टटोली. उन्होंने वहां राजद के वजूद को भी जांचा-परखा. उन्हें जन समर्थन भी मिला. कोसी के लोगों ने उन्हें कोसी में राजद की डूबती नैया का खेवनहार कहा, तो वहीं बहुजन चौपाल के छात्रों व राजद समर्थकों ने शरद यादव को मंडल मसीहा घोषित कर दिया. बीपी मंडल की धरती कोसी में पहले एक नारा बुलंद किया जाता था- 'रोम है पोप का और मधेपुरा है गोप का.' लेकिन जब शरद यादव, नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगे, तब ये नारा भी ठंडा पड़ गया. अब शरद यादव को मंडल मसीहा घोषित करने के बाद फिर से आरक्षण की बुझती आग को ताजा किया जा रहा है. इसी के साथ आरक्षण का लाभ पाने वाली जातियों को जागृत करने, खासकर यदुवंशियों की भावना भड़काने का भी पूरा प्रयास शुरू हो गया है. ये तो सब जानते हैं कि कोसी की धरती पर मंडल मसीहा बीपी मंडल सरीखे नेताओं की कुर्बानी का मार्केटिंग करने में राज्यसभा सांसद शरद यादव को महारत हासिल है. राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो कोसी प्रमंडल में भाजपा का वैसा जनाधार नहीं है, जिसपर वो इतरा सके. कांग्रेस का आधार वोट ही भाजपा को मिलता है. भाजपा का आधार वोट कहे जाने वाले बनियां समुदाय ने कोसी में भाजपा ने कभी तवज्जो नहीं दिया. लिहाजा, भाजपा का जदयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ना भले ही बिहार व देश में लहर पैदा करे, लेकिन विषम परिस्थिति में भी कोसी में

राजद व कांग्रेस का गठबंधन भारी पड़ सकता है. वर्तमान में मधेपुरा व सुपौल लोकसभा क्षेत्र के कुल 13 सीटों में से, जदयू के पास 8, राजद के पास 4 व एक सीट भाजपा के कब्जे में है. जबकि सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल का विधानसभा क्षेत्र खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के अधीन है और इस सीट पर भी जदयू का ही कब्जा है. अब महागठबंधन टूट जाने से जदयू की 9 सीटों में से सुपौल मुख्यालय की सीट छोड़कर, बाकी पर राजद व कांग्रेस गठबंधन को लाभ मिल सकता है. अभी सुपौल लोकसभा सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा है. राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन यहां से सांसद हैं. जदयू से अलग होने के बाद कोसी में भाजपा केवल एक सीट ही निकालने में सफल रही थी. इधर कोसी में जदयू के सीटिंग विधायकों को अभी से ही ये चिंता सताने लगी है कि भाजपा के साथ गठबंधन के बाद अब सीटों का बंटवारा कैसे होगा. दुबारा टिकट लेने से वंचित रहने वाले जदयू विधायकों का भी एक बड़ा हिस्सा शरद यादव के साथ आ जाएगा. इन्हीं सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए शरद यादव ने अभी से राजद के साथ सुर मिलाना शुरू कर दिया है. हालांकि राजद के सभी सीटों पर भाजपा व राजग के अन्य घटक दलों की जीत से भी इंकार नहीं किया जा सकता. लेकिन जदयू की सीटों के बंटवारे का विवाद कैसे सुलझेगा ये जदयू के लिए चिंता की बात होगी. इसे लेकर अभी से अटकलों का दौर शुरू हो गया है. इन सबसे इतर, ये तो तय है कि कोसी में राजद की डूबती नैया को शरद यादव के पतवार की दरकार है, वहीं शरद यादव को भी लोकसभा सांसद के रूप में संसद पहुंचने के लिए राजद की जरूरत है. यही वजह भी है कि कोसी में अपनी जन संवाद यात्रा के दौरान शरद यादव ने सूबे की जदयू-भाजपा गठबंधन सरकार का खुलकर विरोध किया.

इस जन संवाद यात्रा में शरद यादव के समर्थन में जदयू के सहरसा जिला अध्यक्ष धनिकलाल मुखिया के अलावा जदयू का कोई कद्दावर नेता या विधायक शामिल नहीं हुआ. धनिकलाल मुखिया अपने सैकड़ों समर्थकों और कुछ स्थानीय नेताओं के साथ पूरी यात्रा में शरद यादव के साथ रहे. शरद यादव का साथ देने के कारण जदयू ने कई स्थानीय नेताओं के साथ धनिकलाल मुखिया को भी पार्टी से निलंबित कर दिया है. धनिकलाल मुखिया पिछले चार टर्म से अध्यक्ष बने हुए थे. पिछली बार तो तमाम विरोधों के बावजूद शरद यादव के प्रयास से ही वे अध्यक्ष मनोनित हुए. जदयू से निलंबित ऐसे तमाम नेता अब इसी आस में हैं कि शरद यादव जल्द से जल्द राजद व कांग्रेस गठबंधन का हाथ थामें, ताकि इन्हें भी उनके साथ ईमानदारी व वफादारी के साथ खड़े होने का इनाम मिल सके.■

feedback@chauthiduniya.com

समस्त देशवासियों को 71वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

वैज्ञानिक चिंतन

ariskon Pharma Pvt. Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

डॉ.के.एन. शर्मा मेन रोड, हसपुरा

डॉ के.एन. शर्मा जो मुख्यतः न्यूरो और साईकेट्रिक का इलाज करते हैं ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे उनका कहना है कि आजकल जो मनुष्य खोज कर रहा है वह पहले से ही धरती पर विद्यमान है चाहे वह न्यूटन के गुरूत्वाकर्षण का नियम हो या कुछ । उन्होंने बताया कि जरूरत है कि आज जरूरत है तार्किक चिन्तन करने की पृथ्वी और इस ब्रह्मांड में सबकुछ विद्यमान है बस उसे तार्किक चिंतन के जरिए खोज निकालना है। लॉजिकल मैनेजमेंट के द्वारा चिंतन कर वह भी पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना और पक्षपात रहित तार्किक चिंतन कर निष्कर्स निकाला जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विज्ञान की आधारशिला रखने के चलते धर्म का पाया लड़खड़ा रहा है। आईचे जानते हैं चिंतन के भेद सामान्यतः मनोविज्ञान में चिंतन के निम्न रूपों में भेद किया जाता है - संवेदी-क्रियात्मक, बिंबात्मक और अमूर्त (सैद्धांतिक)। संवेदी-क्रियात्मक चिंतन- मानवजाति के इतिहास के आरंभिक दौर में लोग अपनी समस्या को शुद्ध व्यावहारिक आधार पर हल किया करते थे, सैद्धांतिक सक्रियता का जन्म बाद में जाकर हुआ। उदाहरण के लिए, हमारे सुदूर पूर्वजों ने शुरू-शुरू में अपने कदमों, आदि को गिनकर भूमि को नापना सीखा था और इस व्यावहारिक सक्रियता के दौरान शनैः शनैः जो अनुभव संचित होता गया, वह एक विशेष सैद्धांतिक शाखा के रूप में की उत्पत्ति तथा विकास का आधार बना। व्यावहारिक और सैद्धांतिक सक्रियताएं परस्पर-अविभाज्य हैं, किंतु दोनों में पहले व्यावहारिक सक्रियता पैदा हुई और बाद में सैद्धांतिक सक्रियता। व्यावहारिक सक्रियता के विकास के एक अपेक्षा×त ऊंचे चरण में ही सैद्धांतिक सक्रियता का जन्म हुआ। बिंबात्मक चिंतन- अपने सरलतम रूप में बिंबात्मक चिंतन मुख्यतः स्कूलपूर्व अवस्था (६-६ वर्ष) की विशेषता है। चिंतन अभी भी व्यावहारिक क्रियाओं से जुड़ा होता है, किंतु यह संब जरूरी नहीं होता, किंतु उसका प्रत्यक्ष किए बिना, मस्तिष्क में उसका बिंब बनाए बिना उसका काम नहीं चल सकता। ■ भारती

डॉ. के.एन. शर्मा (एमबीबीएस)
हसपुरा औरंगाबाद
Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate 100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.
A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil
Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg
Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

स्वतंत्रता दिवसके पुनीत अवसर पर सम्मानित पाठकों विज्ञापनदाताओं एवं जिलेवासियों को हार्दिक बधाई -सुरेश चौहान, प्रभारी, बेगूसराय, मो0 नं0- 9431211009

शोध से दूर हिंदी की रचनात्मकता

अनंत विजय

हिंदी में आजादी के पूर्व और आजादी के कुछ दिनों बाद जिस तरह की रचनाएं आ रही थीं, धीरे-धीरे उनका ह्रास होता चला गया. हम तो अपने व्याकरण, पुरातत्व, वैदिक और पौराणिक वांग्मय, संस्कृत काव्य को नए सिरे से व्याख्यायित करने की ओर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. भारतीय धर्म शास्त्रों को नए सिरे से उद्घाटित करने का उपक्रम भी नहीं दिखता है. वेद और पुराणों को लेकर शोध भी लगभग नहीं के बराबर हो रहे हैं. यह जानने की कोशिश भी नहीं हो रही है कि जिस वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी, उसी वेदव्यास ने पुराणों की रचना की थी. यह प्रश्न भी हिंदी के शोधार्थियों को नहीं मथता है कि अकेले वेदव्यास सभी पुराणों के रचयिता कैसे हो सकते हैं. पुराणों के रूप में जो करीब चार लाख श्लोकों का विशाल साहित्य मौजूद है, उससे मुठभेड़ का साहस लेखक क्यों नहीं कर पाता है. भारतीय धर्म के ज्ञानकोष वेद को लेकर भी हमारे साहित्यकार उत्साहित नजर नहीं आते हैं. वासुदेव शरण अग्रवाल जैसा विभिन्न विषयों पर विपुल लेखन करने वाला कोई लेखक भी इस समय हिंदी में नजर नहीं आता है. अगर कोई है तो हिंदी समाज का दायित्व है कि ऐसे लेखक को विशाल हिंदी पाठक वर्ग से जोड़ने का उपक्रम किया जाए. पौराणिक चरित्रों को लेकर जिस तरह से लेखन किया जा रहा है, वो युवा वर्ग के पाठकों के बीच लोकप्रिय भी हो रहा है या नहीं, ये भी भ्रम पैदा करता है. राम-सीता और कृष्ण के चरित्रों के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ किया जा रहा है, उसपर कहीं से किसी तरह की गंभीर लेखकीय आपत्ति का नहीं आना भी खेदजनक है.

उधर विदेशों में पौराणिक भारतीय साहित्य को लेकर बेहद उत्साहजनक रचनात्मकता दिखाई देती है. अमेरिका से लेकर जर्मनी तक में भारतीय पौराणिक साहित्य से मुठभेड़ करते विद्वान नजर आते हैं. संभव है कि उनमें से कई लेखकों की राय पर अन्य लोगों को आपत्ति हो, लेकिन वो काम तो कर रहे हैं. ऐसी ही एक छिहत्तर साल की लेखिका हैं- वेंडी डोनिगर. इतिहास और धर्म की प्रोफेसर रहीं वेंडी डोनिगर की किताब- 'द हिंदूज, एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री' को लेकर भारत में काफी विरोध हुआ था. विरोध के बाद प्रकाशक ने उसको वापस लिया फिर किसी अन्य प्रकाशक ने उसको छापा. दरअसल हिंदू धर्म और उसका धार्मिक इतिहास वेंडी डोनिगर की रुचि के केंद्र में रहे हैं. ऋगवेद, मनुस्मृति और कामसूत्र का उन्होंने अनुवाद किया है. इसके अलावा शिवा, द इरोटिक एसेंटिक, द ओरिजन ऑफ एविल इन हिंदू मायथोलॉजी जैसी विचारोत्तेजक कृतियां भी वेंडी डोनिगर के खाते में हैं. 'द हिंदूज, एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री' में वेंडी डोनिगर ने हिंदू धर्म की अवधारणाओं और प्रस्थापनाओं को पश्चिमी मानकों और कसौटी पर कसा है. वेंडी डोनिगर के मुताबिक, हिंदू धर्म की खूबसूरती उसकी जीवंतता और विविधता है, जो हर काल में अपने दर्शन पर डिबेट की चुनौती पेश करता है. हिंदू धर्म पर प्रचुर लेखन करने के बाद अब उनकी एक और दिलचस्प किताब आई है, 'द रिंग ऑफ ट्रुथ, मिथ ऑफ सेक्स एंड जूलरी'. अपनी इस किताब में डोनिगर ने जूलरी का बिजनेस करने वाले अपने मामा के अनुभवों के आधार पर कई सिरों को जोड़कर उसकी व्याख्या की है. वेंडि डोनिगर ने माना है कि उन्होंने अंगूठियों और गहनों पर करीब दो सौ लेख लिखे हैं और कई लेक्चर में उन्होंने इसको विषय बनाया है. वेंडी के मुताबिक, जब भी वो इस विषय पर कोई लेक्चर देती थीं, तो कोई ना कोई उनके पास आता था और अपनी रिंग फिंगर को दिखाकर उससे जुड़ी कोई कहानी सुनाता था. सबकी अपनी-अपनी कहानी थी. इसके बाद जब उन्होंने ग्रीक और संस्कृत साहित्य पढ़ना और पढ़ाना शुरू किया, तो उन्हें इस विषय पर इतने उदाहरण मिले कि वो चकित रह गईं और उन्होंने उसको सहेजना और जोड़ना प्रारंभ कर दिया था. हमारे प्राचीन और पौराणिक ग्रंथों में अंगूठी को लेकर बहुत कुछ कहा गया है. राजा जब खुश होता था, तो अंगूठी उतारकर दे देता था, राजा के हाथ में जो अंगूठी होती थी, वो उसके राजा होने की जानकारी भी देती थी आदि आदि.

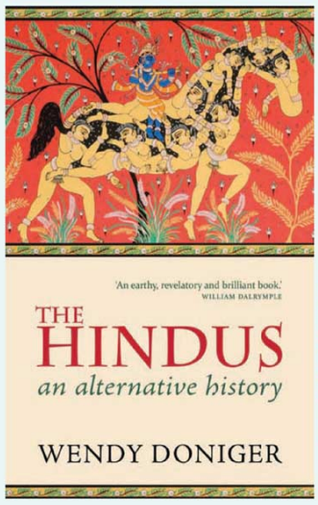

अपनी इस कृति में वेंडि इस सवाल का जवाब तलाशती हैं कि अंगूठियों का कामेच्छा से क्या संबंध रहा है और स्त्री पुरुष संबंधों में उसकी इतनी महत्ता क्यों रही है. क्यों पति-पत्नी से लेकर प्रेमी-प्रेमिका और विवाहेत्तर सम्बन्धों में अंगूठी इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है. अंगूठी प्यार का प्रतीक तो है, इसके मार्फत वशीकरण की कहानी भी जुड़ती चली जाती है. बहुधा यह ताकत के प्रतीक के अलावा पहचान के तौर पर भी देखी जाती रही है.

इस पुस्तक में यह देखना बेहद दिलचस्प है कि किस तरह से वेंडी डोनिगर पूरी दुनिया के धर्मग्रंथों से लेकर शेक्सपियर, कालिदास और तुलसीदास तक की कालजयी रचनाओं में अंगूठी के उल्लेख को जोड़ती चलती हैं. ग्रीक और रोमन इतिहास में भी अंगूठियों को स्त्री-पुरुष के प्रेम से जोड़कर देखा गया है. चर्च ने भी अंगूठी को वैवाहिक बंधन के चिन्ह के रूप में मान्यता दी थी. वो इस बारे में पंद्रह सौ उनसठ के बुक ऑफ कॉमन प्रेयर का जिक्र करती हैं. वो बताती है कि किस तरह से सोलहवीं शताब्दी में इटली में पुरुष जो अंगूठियां पहनते थे, उसमें लगे पत्थरों में नग्न स्त्रियों के चित्र उकेरे जाते थे. माना जाता था कि इस तरह की अंगूठी को पहनने वाले स्त्रियों को अपने वश में कर लेते थे. अंगूठी और सम्बन्धों के बारे में मिथकों में क्या कहा गया है, अपनी इस खोज के सिलसिले में लेखिका ने जितना शोध किया है, वो आश्चर्यजनक है. प्राचीन भारतीय ग्रंथों से उसने इतना कुछ उद्धृत किया है कि पाठक चमत्कृत रह जाते हैं और उनके मन में यह सवाल भी कौंधता है कि हिंदी में इस तरह की किताबें क्यों नहीं लिखी जाती हैं.

वेंडि डोनिगर के मुताबिक, करीब हजारों साल पहले जब सभ्यता की शुरुआत हुई थी तभी से कविताओं में गहनों का जिक्र मिलता है. उन कविताओं में स्त्री के अंगों की तुलना बेशकीमती पत्थरों से गई थी. जब नायिका के बालों को सोने जैसा बताया गया था. वेंडि डोनिगर इस क्रम में जब भारत के मिथकीय और ऐतिहासिक चरित्रों की ओर आती हैं, तो वो सीता का उदाहरण देती हैं. इस संदर्भ में वे भी कहती हैं कि अपने पति की अनुपस्थिति में गहने पहनने वाली औरतों को उस वक्त के समाज में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था. सीता चूंकि राजकुमारी थीं, इसलिए गहने उनके परिधान का आवश्यक अंग थे. इसलिए अपने पति से अलग निर्वासन में रहने पर भी सीता के गहने पहनने पर किसी तरह का सवाल नहीं उठा था. सीता के अलावा वो दुश्यंत का भी उदाहरण देती हैं कि कैसे उसको अंगूठी को देखकर अपनी पत्नी शकुंतला की याद आती है. तो आप देखें कि किस तरह से एक शोध के सिलसिले में कालिदास से लेकर तुलसीदास की रचनाओं का उल्लेख मिलता है. इसके अलावा लेखिका जिस कालखंड में विचरण करती हैं, वो कितना बड़ा है. इतने बड़े कालखंड को अपने लेखन में साधने के लिए कितने कौशल और ज्ञान की जरूरत होती है, इसका सहज अंदाज लगाया जा सकता है.

इन दिनों मिथ पर इतना अधिक लिखा जा रहा है. जनश्रुतियों और लोककथाओं के आधार पर उपन्यास पर उपन्यास लिखे जा रहे हैं, उससे यह लगता है कि मिथक लेखन के पाठक बहुत हैं. हाल में जिस तरह से भारतीय अंग्रेजी लेखकों ने मिथकों पर लिखा है, उससे यह प्रतीत होने लगा है कि मिथ को अपने तरीके से तोड़ने-मरोड़ने की छूट वो लेते हैं और फिर संभाल नहीं पाते हैं. वेंडी डोनिगर की यह किताब बताती है कि मिथकों, मिथकीय पात्रों और परिस्थितियों पर लिखने के लिए कितनी मेहनत की आवश्यकता होती है. अपने तर्कों के समर्थन में कितने उदाहरण देने पड़ते हैं. जिस तरह से वेंडि डोनिगर ने अपनी इस किताब में मेसोपोटामिया की सभ्यता से लेकर हिंदी, जैन, बौद्ध, ईसाई और इस्लाम धर्म के लेखन से तथ्यों को उठाया है और उसको व्याख्यायित किया है, वो अद्भुत है. आजादी के सत्तर साल बाद आज हम हिंदी के लोगों को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि हिंदी मे स्तरीय शोध आधारित लेखन को कैसे बढ़ावा दिया जाए. ■

इन दिनों मिथ पर इतना अधिक लिखा जा रहा है. जनश्रुतियों और लोककथाओं के आधार पर उपन्यास पर उपन्यास लिखे जा रहे हैं, उससे यह लगता है कि मिथक लेखन के पाठक बहुत हैं. हाल में जिस तरह से भारतीय अंग्रेजी लेखकों ने मिथकों पर लिखा है, उससे यह प्रतीत होने लगा है कि मिथ को अपने तरीके से तोड़ने-मरोड़ने की छूट वो लेते हैं और फिर संभाल नहीं पाते हैं. वेंडी डोनिगर की यह किताब बताती है कि मिथकों, मिथकीय पात्रों और परिस्थितियों पर लिखने के लिए कितनी मेहनत की आवश्यकता होती है. अपने तर्कों के समर्थन में कितने उदाहरण देने पड़ते हैं. जिस तरह से वेंडि डोनिगर ने अपनी इस किताब में मेसोपोटामिया की सभ्यता से लेकर हिंदी, जैन, बौद्ध, ईसाई और इस्लाम धर्म के लेखन से तथ्यों को उठाया है और उसको व्याख्यायित किया है, वो अद्भुत है. आजादी के सत्तर साल बाद आज हम हिंदी के लोगों को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि हिंदी मे स्तरीय शोध आधारित लेखन को कैसे बढ़ावा दिया जाए.

anant.ibn@gmail.com

आरटीआई से जानें शिकायत की स्थिति

चौथी दुनिया ब्यूरो

आरटीआई सिर्फ शिकायत या सूचना मांगने का माध्यम नहीं है, बल्कि इसके द्वारा शिकायत की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली जा सकती है. आरटीआई आवेदन के जरिए ही हम जान सकते हैं कि हमने जिस सूचना के लिए आवेदन दाखिल किया था, उसकी स्थिति क्या है. सूचना मिलने में क्यों देरी हो रही है या वो सूचना कहां तक पहुंची इस बारे में जानकारी जुटाई जा सकती है. किसी और के जरिए दाखिल किए गए सार्वजनिक आवेदन के बारे में भी जानकारी ली जा सकती है कि उस आरटीआई कार्यकर्ता ने अपने नाम से आवेदन दाखिल किया है, या गुमनाम के रूप में. जिसके खिलाफ आवेदन दाखिल किया गया है, उस व्यक्ति या प्राधिकरण के बारे में भी सूचना ली जा सकती है. कई बार ये होता है कि आरटीआई के जरिए मांगी जानकारी नहीं दी जाती और इसके बारे में आवेदक को भी सूचित नहीं किया जाता. इस स्थिति में आवेदक आरटीआई के द्वारा ही ये जान सकता है कि कितनी शिकायतें आगे की जांच के लिए स्वीकार की गई हैं और कितने मामलों में जांच बन्द हो चुकी है?

आवेदन का प्रारूप:

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,
कृपया निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं

1. केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिनांक.....से..... के बीच प्राप्त की गई शिकायतों का संक्षिप्त विवरण, क्या शिकायत गुमनाम थी, शिकायत की तिथि, उन अधिकारियों या प्राधिकरण का पूरा विवरण (नाम, पद तथा संपर्क का पता आदि) जिनके खिलाफ शिकायत की गई है.

2. उपर्युक्त में से कौन सी शिकायतें तुरन्त ख़ारिज़ कर दी गई तथा कौन सी आगे की जांच के लिए स्वीकार की गईं. केस के अनुसार शुरुआती जांच की तिथि या ख़ारिज करने के कारण का संक्षिप्त विवरण भी दें.

3. आगे की जांच के लिए स्वीकार की गई शिकायतों में से कितने मामलों में जांच बन्द हो चुकी है? प्रत्येक के बन्द होने का संक्षिप्त विवरण दें.

4. विभिन्न कानून, नियम, निर्देश, प्रक्रिया, मैन्युअल आदि के अनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद कितने समय बाद जांच पूरी हो जाती है. कृपया ऐसे दिशानिर्देशों की प्रति उपलब्ध कराएं, जिसमें शिकायत प्राप्ति से लेकर उस पर कार्रवाई और दण्डारोपण तक के विभिन्न चरणों के लिए समय सीमा का वर्णन हो.

5. दिनांक..... से अब तक आयोग को कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उनमें से कितनी तत्काल ख़ारिज कर दी गई तथा कौन-कौन सी आगे की जांच के लिए रखी गईं? जांच के लिए रखी गई शिकायतों में से कितनी शिकायतों की छानबीन में उपरोक्त समय सीमा का पालन किया गया?

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपए अलग से जमा कर रहा /रही हूं.

या

मैं बीपीएल कार्ड धारी हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नम्बर ..... है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं.

भवदीय
नाम:
पता:
फोन नं:

संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

feedback@chauthiduniya.com

अगर आपके पास आरटीआई से संबंधित कोई ख़बर या सवाल है, तो हमें इमेल करें:
rti@chauthiduniya.com

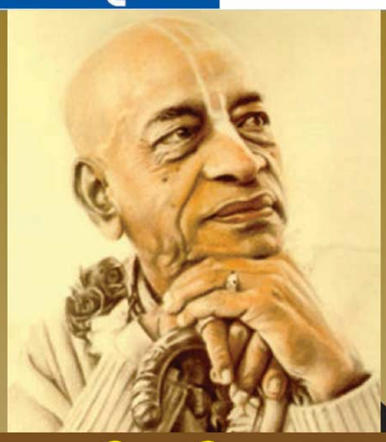

जन्मदिन- 1 सितम्बर, 1896
पुण्यतिथि- 14 नवम्बर, 1977

जन्मदिन विशेष

भारतीय अध्यात्म को दुनियाभर में पहुंचाने वाले संत स्वामी श्री भक्तिवेदांत प्रभुपाद

श्रील प्रभुपाद के दार्शनिक ज्ञान एवं भक्ति की महत्ता को देखते हुए गौड़ीय वैष्णव समाज ने 1947 में उन्हें भक्ति वेदान्त की उपाधि से सम्मानित किया. सन्यास ग्रहण करने के बाद 1959 में स्वामी प्रभुपाद ने वृन्दावन, मथुरा में श्रीमद्भागवत पुराण का अनेक खंडों में अंग्रेज़ी में अनुवाद किया. आरंभिक तीन खंड प्रकाशित करने के बाद 1965 में अपने गुरुदेव के अनुष्ठान को संपन्न करने वे अमेरिका चले गए. मालवाहक जलयान द्वारा जब वे पहली बार न्यूयॉर्क पहुंचे तो उनके पास एक पैसा भी नहीं था. एक वर्ष उन्होंने अत्यंत कठिनाई भरे दिन गुजारे. जुलाई, 1966 में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ (इस्कॉन) की स्थापना की.

चौथी दुनिया ब्यूरो

भारतीय सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्म को दूसरी सभ्यताओं और रहन-सहन वाले लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने की जब भी बात होगी, स्वामी प्रभुपाद का नाम आदर के साथ लिया जाएगा. आज दिल्ली-मथुरा सहित भारत के विभिन्न भागों में विदेशी नागरिकों को कृष्ण भक्ति में मग्न देखा जा सकता है. इसके पीछे स्वामी प्रभुपाद का बहुत बड़ा योगदान है. अपनी सभ्यता और अपने धर्मानुरागियों के बीच अपने धर्म व अध्यात्म का प्रचार-प्रसार कठिन कार्य नहीं है. लेकिन स्वामी प्रभुपाद ने उन गोरों के बीच हमारी धर्म-संस्कृति का बीज बोया, जो भारत को उपेक्षा की नजरों से देखते रहे हैं.

स्वामी प्रभुपाद का जन्म 1 सितम्बर, 1896 को कोलकाता में हुआ था. इनके बचपन का नाम अभय चरण था. इनके पिता का नाम गौर मोहन डे और माता का नाम रजनी था. पिता एक कपड़ा व्यापारी थे. गौर मोहन डे ने अपने बेटे अभय चरण का पालन पोषण एक कृष्ण भक्त के रूप में किया. 1922 में अभय चरण की मुलाकात सरस्वती गोस्वामी से हुई, जिन्हें अभय चरण ने अपना गुरु बना लिया. 1933 में प्रयाग में उनसे विधिवत दीक्षा प्राप्त करने के बाद अभय चरण श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य हो गए.

ये स्वामी प्रभुपाद के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आदेश था कि वे अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से वैदिक ज्ञान का प्रसार करें. आगामी वर्षों में श्रील प्रभुपाद ने 'श्रीमद्भगवद्गीता' पर एक टीका लिखी, जो उस समय बहुत ही लोकप्रिय हुआ. साथ ही उन्होंने गौड़ीय मठ के कार्य में भी सहयोग दिया. 1944 ई. में श्रील प्रभुपाद ने बिना किसी सहायता के एक अंग्रेज़ी पाक्षिक पत्रिका आरंभ की. इस पत्रिका का संपादन, पाण्डुलिपि का टंकण और मुद्रित सामग्री के शोधन का सारा कार्य वे स्वयं करते थे. कई बार ऐसा समय भी आया कि वो पत्रिका बंद होने के कगार पर आ गई. लेकिन बेहद संघर्ष और अभावों के बावजूद श्रील प्रभुपाद ने इसे बंद नहीं होने दिया. वर्तमान समय में यह पत्रिका 'बैक टू गॉड हैड' तीस से अधिक भाषाओं में छप रही है और पश्चिमी देशों में भी खूब लोकप्रिय है.

श्रील प्रभुपाद के दार्शनिक ज्ञान एवं भक्ति की महत्ता को देखते हुए गौड़ीय वैष्णव समाज ने 1947 में उन्हें भक्ति वेदान्त की उपाधि से सम्मानित किया. सन्यास ग्रहण करने के बाद 1959 में स्वामी प्रभुपाद ने वृन्दावन, मथुरा में श्रीमद्भागवत पुराण का अनेक खंडों में अंग्रेज़ी में अनुवाद किया. आरंभिक तीन खंड प्रकाशित करने के बाद 1965 में अपने गुरुदेव के अनुष्ठान को संपन्न करने वे अमेरिका चले गए. मालवाहक जलयान द्वारा जब वे पहली बार न्यूयॉर्क पहुंचे तो उनके पास एक पैसा भी नहीं था. एक वर्ष उन्होंने अत्यंत कठिनाई भरे दिन गुजारे. जुलाई, 1966 में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ (इस्कॉन) की स्थापना की.

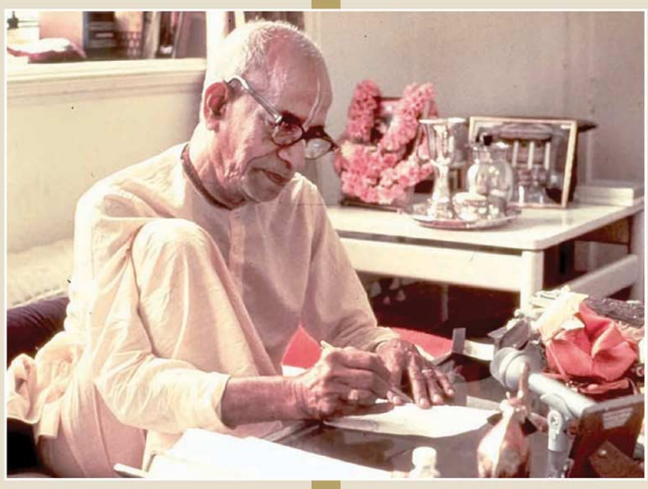

उसके बाद 1968 में वर्जीनिया, अमेरिका की पहाड़ियों में उन्होंने नव-वृन्दावन की स्थापना की. दो हज़ार एकड़ के इस समृद्ध कृषि क्षेत्र से प्रभावित होकर उनके शिष्यों ने अन्य जगहों पर भी ऐसे समुदायों की स्थापना की है. 1972 में टेक्सस के डलास में गुरुकुल की स्थापना कर उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की वैदिक प्रणाली का सूत्रपात किया. इस्कॉन के माध्यम से श्रील प्रभुपाद ने विश्व को कृष्ण भक्ति का अनुपम उपहार प्रदान किया. उनके कुशल मार्गदर्शन में इस्कॉन विश्व भर के सौ से अधिक मंदिरों, विद्यालयों, संस्थानों और कृषि समुदायों का वृहद संगठन बन गया. आज विश्व भर में इस्कॉन के आठ सौ से ज्यादा केंद्र, मंदिर, गुरुकुल एवं अस्पताल आदि प्रभुपाद की दूरदर्शिता और अद्वितीय प्रबंधन क्षमता के जीते जागते साक्ष्य हैं. कृष्ण को सृष्टि के सर्वेसर्वा के रूप में स्थापित करने और उनके अनुयायियों के मुख पर हरे राम हरे राम, राम-राम हरे-हरे और हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण-कृष्ण हरे-हरे का उच्चारण सदैव रखने की प्रथा का श्रेय श्रील प्रभुपाद को ही दिया जाता है.

1950 में श्रील प्रभुपाद ने गृहस्थ जीवन से अवकाश लिया और फिर वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने लगे, ताकि वे अपने अध्ययन और लेखन को अधिक समय दे सकें. वे वृन्दावन धाम जाकर वहां के सात्विक माहौल में मध्यकालीन ऐतिहासिक श्रीराधा दामोदर मन्दिर में रहने लगे. वहां वे अनेक वर्षों तक गंभीर अध्ययन एवं लेखन में संलग्न रहे. 1959 में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया. श्रीराधा दामोदर मन्दिर में श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन के सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण ग्रंथ का आरंभ किया. यह ग्रंथ था- अठारह हज़ार श्लोक संख्या के श्रीमद्भागवत पुराण का अनेक खण्डों का अंग्रेज़ी में अनुवाद और उसकी व्याख्या. आज श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों की वैश्विक प्रामाणिकता है. 14 नवम्बर, 1977 को धार्मिक नगरी मथुरा के वृन्दावन धाम में ही श्रील प्रभुपाद जी का निधन हो गया. ■

feedback@chauthiduniya.com

चिकनगुनिया: लक्षण, जांच व बचाव

चौथी दुनिया ब्यूरो

चिकनगुनिया की पहचान सबसे पहले तंज़ानिया में 1952 में हुई थी. वहां की भाषा में चिकनगुन का मतलब होता है, जकड़न वाली स्थिति. भारत में बीते कुछ सालों में चिकनगुनिया का प्रकोप तेजी से बढ़ा है. मानसून के दौरान और मानसून समाप्त होने के बाद भी जगह जगह पानी इकट्ठा होने से मच्छर पनपते हैं. इन्हीं मच्छरों में चिकनगुनिया के मच्छर भी होते हैं. चिकनगुनिया उसी मच्छर के काटने से फैलता है, जो डेंगू फैलाता है, यानि एडिस एजिप्टी प्रजाति का मच्छर. मच्छर के काटने के बाद 4 से 7 दिन के अंदर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है.

चिकनगुनिया के लक्षण

चिकनगुनिया की शुरुआत बुखार और जॉइंट पेन से होती है. इसमें मरीज को शरीर में जकड़न, सिर दर्द, थकान, उल्टी और चक्कर आने और घबराहट की शिकायत भी होती है. चिकनगुनिया के पीड़ित को स्किन रेशेज हो सकते हैं.

इसके लक्षण बहुत कुछ डेंगू जैसे ही होते हैं. एक समय था जब चिकनगुनिया को डेंगू ही समझा जाता था. कई बार पता नहीं चल पाता कि चिकनगुनिया है या डेंगू. हालांकि चिकनगुनिया और डेंगू दोनों साथ में भी हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में इलड टेस्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाती है. चिकनगुनिया ठीक होने के बाद भी कई महीनों तक जॉइंट पेन बना रहता है.

चिकनगुनिया की जांच

❖ जीनोमिक टेस्ट पीसीआर विधि- यह टेस्ट चिकनगुनिया की सही जानकारी दे देता है. हालांकि ये टेस्ट तभी सफल हो सकता है, जब बुखार आने के सात दिन के अंदर इसे कराया जाय. सात दिन बाद ये टेस्ट कराने से सही परिणाम मिलना मुश्किल होता है.

❖ आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज टेस्ट- चिकनगुनिया होने पर हमारे शरीर में इसके वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनने लगती है. बुखार होने के एक सप्ताह बाद आईजीएम एंटीबॉडीज बनते हैं, जबकि बुखार के 12-13 दिन बाद आईजीजी एंटीबॉडीज बनते हैं. अगर दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आए और लक्षण चिकनगुनिया जैसे ही हों, तो 5-7 दिन बाद नए सैंपल के साथ टेस्ट करवाना चाहिए. यदि दोनों पॉजिटिव आए, तो वायरस का होना निश्चित होता है. अगर आईजीएम पॉजिटिव आए और आईजीजी नेगेटिव आए, तो इसका मतलब है कुछ समय पहले ही वायरस का हमला हुआ है.

बचाव का तरीका

चिकनगुनिया से बचने का तरीका यही है कि मच्छर से बचा जाए. मच्छर की रोकथाम करने से ही चिकनगुनिया पर काबू पाया जा सकता है. यदि थोड़ा सा भी पानी कहीं इकट्ठा है, तो वहां मच्छर पनप सकते हैं. इसलिए बारिश के बाद आसपास पानी जमा ना हो इसका ध्यान रखें. टायर, बोतल, कूलर, गमले आदि में बारिश का पानी जमा हो गया हो, तो उसे सुखाएं. कूलर का पानी बदलते रहें, ताकि उसमें मच्छर पैदा ना हो पाएं. यदि पानी सूख ना सके, तो वहां थोड़ा मिट्टी का तेल डाल दें, इससे मच्छर पैदा नहीं होंगे. मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी, मच्छर वाली क्रीम आदि का उपयोग कर सकते हैं. संभव हो तो ऐसे कपड़े पहनें, जिससे पूरा शरीर ढका रहे. बाहर से मच्छर घर के अंदर ना आने पाए उसके लिए खिड़की पर जाली होना जरूरी है. ■

चिकनगुनिया से बचने के आयुवेर्दिक घरेलू उपचार

सब्जियों का जूस

चिकनगुनिया से बचने का दूसरा सरल उपाय है कि आप जितना हो सके सब्जियों और स्ट्रिंस फलों का सेवन अधिक से अधिक करें. इसके अलावा आप सब्जियों के जूस का सेवन भी कर सकते हैं.

गिलोय का सेवन

कम से कम तीन इंच का गिलोय लें, इसे एक कप पानी में डालें और उबाल लें. तब तक उबालें जब तक पानी आधा कप ना हो जाए. फिर इसे ठंडा करके सेवन करें. इससे चिकनगुनिया के वायरस का प्रभाव कम होने लगता है.

पपीता का सेवन

चिकनगुनिया में पपीते का सेवन फायदेमंद होता है. कच्चे पपीते का रस भी लाभकारी सिद्ध हाता है.

नींबू और संतरा

जितना हो सके नींबू व संतरा का एकदम ताजा जूस पीएं. नींबू का पानी चिकनगुनिया में असरकारक होता है.

तुलसी पत्ते का काढ़ा

काली मिर्च मिला हुआ तुलसी पत्ते का काढ़ा चिकनगुनिया में लाभकारी होता है. इसके नियमित सेवन से चिकनगुनिया का वायरस खत्म हो जाता है.

feedback@chauthiduniya.com

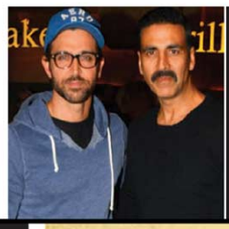

ऋतिक को मुझसे कोई दिक्कत नहीं हुईः अक्षय

अक्षय कुमार की *रुस्तम* और ऋतिक रोशन की *मोहन जोदाड़ो* के कारण पिछले साल पंद्रह अगस्त के मौके पर इन दोनों की बॉक्स ऑफिस पर भिड़त हुई थी. इसमें अक्षय कुमार ने बाजी मार ली थी. इसके बाद लंबे समय तक दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें भी आती रहीं. लेकिन समय के साथ दोनों ने अपने रिश्ते फिर से सुधार लिए. अक्षय कुमार की हालिया रिलीज *टॉयलेट एक प्रेम कथा* में ऋतिक रोशन के नाम का जमकर इस्तेमाल किया गया. लेकिन अक्षय ने सेंसर बोर्ड को आश्वस्त किया कि ऋतिक ने फिल्म देखी है और उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है. दरअसल, फिल्म में ऋतिक रोशन की छह उंगलियों को लेकर काफी चुटकुले हैं. फिल्म में अक्षय कुमार के पापा अंधविश्वास के कारण उनकी शादी छह उंगली वाली लड़की से करवाना चाहते हैं. फिल्म के बीच में एक जगह ऋतिक रोशन और सुज़ैन खान के तलाक को लेकर भी मज़ाक बनाया गया है. अक्षय ने ऋतिक को इसके लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने इन चुटकुलों को चुटकुलों जैसा ही लिया.

सितंबर माह में आने वाली फिल्में

सितंबर महीने का अगाज़ हो चुका है. साल की मोस्ट अवेटिंग फिल्मों में से एक, अजय देवगन की *बादशाहो* इसी हफ्ते 1 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर कदम रख रही है. *बादशाहो* के अलावा इस महीने बॉक्स ऑफिस पर कई और बड़ी फिल्में भी आ रही हैं. आइए जानते हैं, इस महीने रिलीज होने वाली फिल्मों के बारे में...

नोटः फिल्म की डेट रिलीज कभी भी चेंज हो सकती है.

01 सितंबर 2017

बादशाहो

कलाकार : अजय देवगन, इमरान हाशमी, इलियाना डीक्रूज, ईशा गुप्ता, विद्युत जामवाल आदि

डायरेक्टर : मिलन लूथरिया

शुभ मंगल सावधान

कलाकार : आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर आदि

डायरेक्टर :आर.एस.प्रसान्ना

08 सितंबर 2017

पोश्टर बॉईज

कलाकार : सनी देओल, बॉबी देओल और श्रेयष तलपड़े

डायरेक्टर : श्रेयष तलपड़े

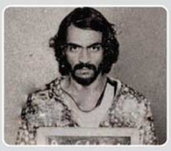

डैडी

कलाकार : अर्जुन रामपाल और फरहान अख्तर

डायरेक्टर : अशीम आहलूवालिया

15 सितंबर 2017

सिमरन

कलाकार : कंगना रनौत

डायरेक्टर : हंसल मेहता

लखनऊ मेल

कलाकार : फरहान अख्तर, श्वामी खेर, डायना पेंटी, जिप्पी ग्रेवाल आदि

डायरेक्टर : रंजीत तिवारी

22 सितंबर 2017

भूमि

कलाकार : संजय दत्त और आदिती रॉय हैदरी

डायरेक्टर : ओमंग कुमार

हसीना

कलाकार: श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर

डायरेक्टर: अपूर्व लखिया

29 सितंबर 2017

जुड़वा-2

कलाकार: वरूण धवन, जैकलीन फर्नांडिस और तापसी पन्नू

डायरेक्टर : साजिद खान और डेविड धवन

पिटती फिल्मों के बीच बादशाहो से है उम्मीद

> मिलन लथूरिया फिल्म *बादशाहो* में अजय देवगन और इमरान हाशमी को एक बार फिर साथ लेकर आ रहे हैं. इससे पहले वे इस जोड़ी को *वन्स अपॉन अ टाईम इन मुंबई* में लेकर आ चुके है. फिल्म सुपरहिट रही थी और दर्शकों ने भी इस जोड़ी को ख़ूब पसंद किया था.

प्रवीण कुमार

आधा साल से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन इन 8 महीनों में बहुत कम ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हो पाई हैं. *बाहुबली-2* ने तो कई रिकॉर्ड अपने नाम किए, जिसे तोड़ना किसी के लिए आसान नहीं होगा. इसके अलावा बॉलीवुड की बहुत कम ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं. इनमें रईस, काबिल, जॉली एलएलबी-2, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, हिंदी मीडियम, सचिनः ए बिलियन ड्रीम, मॉम, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का और टॉयलेटः एक प्रेम कथा शामिल हैं. इन फिल्मों के अलावा ज्यादातर फिल्मों ने दर्शकों को निराश किया. यहां तक कि सलमान खान की *ट्यूबलाईट* और शाहरुख खान की *जब हैरी मेट सेजल* भी दर्शकों का दिल नहीं जीत सकी.

अब दर्शकों की नज़रें अजय देवगन की फिल्म *बादशाहो* पर टिकी हैं. इसका इंतजार उनके फैंस काफी समय से कर रहे हैं. दर्शकों को पूरी उम्मीद है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड

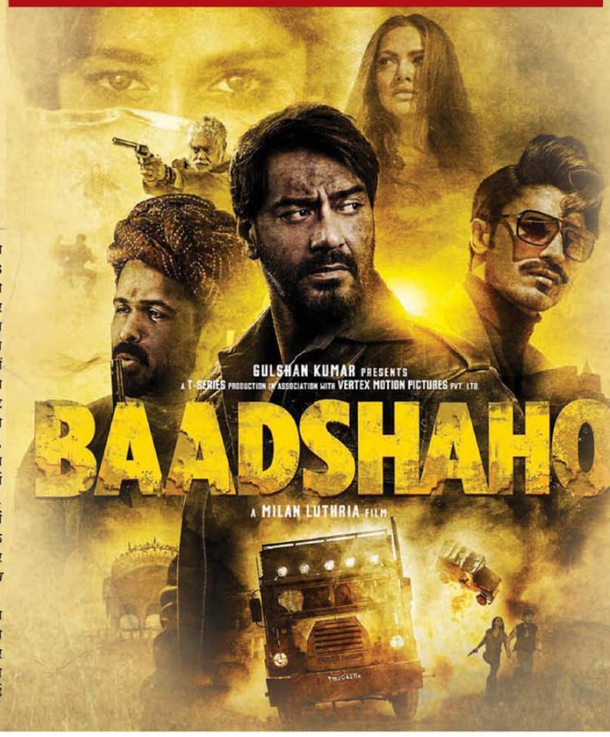

अपने नाम करेगी. इस फिल्म को मिलन लूथरिया बना रहे हैं. कहा जा रहा है कि इस फिल्म की जान उसकी रियल स्टोरी और शानदार एक्शन है.

बादशाहो उस समय की कहानी है, जब 1975 की इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने महारानी गायत्री देवी के महल पर रेड करवा दी थी. उन्होंने महारानी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने काफी धन महल में छिपा रखा है, जिसका गलत उपयोग किया जा सकता है. वहीं दूसरी तरफ, गायत्री देवी ने इंदिरा के इस आरोप को गलत बताया था. इंदिरा गांधी ने रातों-रात महल को खोदवा डाला, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ. माना गया था कि गायत्री देवी ने सारा धन पहले ही वहां से हटा दिया था. बादशाहो उसी दौर के एक सोने से लदे ट्रक की कहानी है, जिसे इमरजेंसी के दौरान छह बदमाश इधर से उधर करते हैं. ये ट्रक किसका है, इसका क्या उद्देश्य है, ये फिल्म देखने पर पता चलेगा.

मिलन लथूरिया बादशाहो में अजय और इमरान हाशमी को एक बार फिर साथ लेकर आ रहे हैं. इससे पहले वे इस जोड़ी को वन्स अपॉन अ टाईम इन मुंबई में लेकर आ चुके हैं. फिल्म सुपरहिट रही थी और दर्शकों ने भी इस जोड़ी को ख़ूब पसंद किया था. बादशाहो में अजय देवगन के अलावा इलियाना डी-क्रूज, ईशा गुप्ता, इमरान हाशमी, विद्युत जामवल और संजय मिश्रा भी नज़र आएंगे. फिल्म एक सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है.■

feedback@chauthiduniya.com

दिलचस्प है सुनील सिकन्दरलाल से शक्ति कपूर बनने की कहानी

चौथी दुनिया ब्यूरो

शक्ति कपूर सिर्फ एक अच्छे खलनायक ही नहीं बल्कि बेहतरीन मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं. हिंदी सिनेमा में आज भी उनके प्रसिद्ध डायलॉग दर्शकों की जुबान पर चढ़े हुए हैं. जिनमे कुछ मशहूर डायलॉग हैं, राजा बाबू का- नंदू सबका बंदू, समझता नहीं है यार, फिल्म चालबाज का- मैं नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा बच्चा हूं. इसके अलावा, अउउउउ....आला रे आला स्पेक्टर भिंडे आला, साथ में लाया कानून का ताला, तो शायद ही किसी को याद नहीं हो. शक्ति कपूर ने सिल्वर स्क्रीन पर लगभग हर प्रकार के किरदार को बखूबी जिया है. फिर वो चाहे विलेन की भूमिका हो या कॉमेडी वाला रोल, बॉलीवुड का यह नन्दू हर किरदार में एक दम फिट बैठता है.

जन्मदिन मुबारक

शक्ति कपूर 3 सितंबर को 59 साल के हो जाएंगे. उनका पूरा नाम है, सुनील सिकन्दरलाल कपूर. वे हिंदी सिनेमा में अपनी खलनायकी और कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं. शक्ति कपूर का जन्म नई दिल्ली में एक निम्न मध्यमवर्गीय पंजाबी परिवार में 3 सितंबर 1958 को हुआ था. उनके पिता दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक दर्जी की दुकान चलाते थे. शक्ति कपूर के नाम बदलने के पीछे भी एक खास वजह हैं. दरअसल, जब सुनील दत्त साहब ने संजय दत्त स्टारर फिल्म रॉकी में इन्हें विलेन का रोल ऑफर किया, तो उन्हें इनका नाम सुनील कपूर विलेन की तरह नहीं लगा. इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर शक्ति कपूर कर लिया.

शक्ति कपूर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में ही पूरी की. वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएट हैं. शक्ति कपूर की शादी शिवानी कपूर से हुई है. उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी. बेटा सिद्धार्थ कपूर सहायक निर्देशक और डीजे हैं, वहीं बेटी श्रद्धा कपूर हिंदी सिनेमा की उभरती हुई अभिनेत्री हैं.

शक्ति कपूर के करियर की बात की जाए, तो फिल्म इंडस्ट्री में वे आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है. 1980 के दौर में शक्ति कपूर को लोग बतौर अभिनेता पहचानने लगे थे. उस साल उनकी दो फ़िल्में कुर्बानी और रॉकी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थीं. इन दोनों ही फिल्मों में उन्होंने मुख्य ख़लनायक की भूमिका अदा की थी. इसके बाद 1983 में वे जितेंद्र और श्रीदेवी स्टारर फिल्म हिम्मतवाला और सुभाष घई निर्देशित फिल्म हीरो में ख़लनायक के किरदार में नज़र आए. इन चार फिल्मों में ख़लनायकी के बेहतरीन अभिनय ने शक्ति कपूर को बॉलीवुड के बेहतरीन खलनायकों की श्रेणी में ला खड़ा किया. अस्सी और नब्बे के दशक में ख़लनायकी के किरदार के लिए निर्देशकों-निर्माताओं की पहली पसंद अमरीश पूरी या शक्ति कपूर ही होते थे. ■